सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 20 फरवरी, 2026 ई०
द्वितीय सत्र — 01 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–58, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (क्षेत्र सं0–64, कदवा)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–59, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–16, कल्याणपुर)
(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1587, दिनांक–16.12.2025 द्वारा सात निश्चय–3 (2025–2030) के अंतर्गत ''सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन'' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल) के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल) के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्य–योजना तैयार किया जा रहा है । तदोपरान्त चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को भी विकसित किया जाएगा ।

वर्त्तमान में सदर अस्पताल, मोतिहारी में एम0सी0एच0 (मातृ एवं शिशु अस्पताल), एस0एन0सी0यू0 (स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट), पी0आई0सी0यू0 (पेडियाट्रिक इन्टेनसिव केयर यूनिट), प्रसूति एवं स्त्री रोग, सर्जरी, नेत्र रोग, ई0एन0टी0 (कान, नाक एवं गला), आर्थोपेडिक आदि की चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध है । साथ ही अल्ट्रासाउण्ड, ई0सी0जी0, एक्स–रे, ब्लड बैंक, पैथोलॉजिकल जाँच, डायलिसिस आदि की सुविधायें भी उपलब्ध है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब तो प्राप्त है, मेरा सवाल है कि सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना और माननीय मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है कि इसमें

कार्रवाई की जा रही है । मैं धन्यवाद करता हूं मंत्री जी को और आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी चम्पारण जिला जहां का यह प्रश्न है लगभग एक करोड़ की आबादी का आज के दिन में वह जिला है और सरकार ने पहले भी निर्णय लिया है कि जो बड़े जिले हैं, उन बड़े जिलों में जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है उसमें एम0आर0आई0 की सुविधा दी जाएगी सी0सी0यू0 बनाई जाएगी । वहां जो स्वीकृत हार्ट के डॉक्टर का पद है वह दो है, यूरोलॉजिस्ट एक है, नेफ्रोलॉजी है जहां आज के दिन में डायलिसिस भी हो रहा है किसी एजेंसी के द्वारा । लेकिन मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में न तो हार्ट के एक डॉक्टर हैं, न यूरोलॉजी है, न नेफ्रोलॉजी है, न एम0आर0आई0 की सुविधा प्राप्त है, तो सुपर स्पेशलिटी तो बनाएंगे लेकिन जो सुविधा सदर हॉस्पिटल को एक बड़े जिले के रूप में प्राप्त होनी चाहिए उन सुविधाओं को कब तक माननीय मंत्री जी वहां उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सात निश्चय पार्ट–3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की योजना है और कई जिला सदर अस्पतालों में हम लोगों ने सी0सी0यू0 और सी0सी0बी0 बनाना शुरू भी कर दिया है । यह चरणबद्ध तरीके से होगा और यह हमारी जो योजना है यह अगले पांच साल में सभी सदर अस्पतालों में यह व्यवस्था पहुंचाने की है । माननीय सदस्य ने विभागवार सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टर की बात की है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वर्ष से ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ने लगेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तो यह बनाएंगे लेकिन जो सदर हॉस्पिटल को जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और इन्होंने कहा भी है कि चरणबद्ध तरीके से तो सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चम्पारण तो क्या सबसे प्रथम में सबसे प्रायोरिटी में पूर्वी चंपारण को यह सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रमोद जी, आप भी पूरक पूछ लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, वहां अभी आई0सी0यू0 वेंटिलेटर और जैसा माननीय सदस्य सचींद्र जी ने कहा कि सुपर स्पेशियलिस्ट जो बीमारी सब है, वह सब बीमारी के स्पेशियलिस्ट डॉक्टर, उसके शयन, यह सब व्यवस्था जो है एकदम नगण्य बराबर है । मैं आपके माध्यम से महोदय आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं और इनकी सोच है कि मोतिहारी भविष्य की कमिश्नरी है, नगर निगम चला गया । महोदय, इस भविष्य की कमिश्नरी नगर निगम क्षेत्र और राज्य के सबसे बड़े जिला में कब तक सुपर स्पेशलिस्ट की सुख सुविधा

प्रदान होगी, इसकी एक तिथि निर्धारित करा देते क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं तो बहुत बड़ी कृपा होती आपके माध्यम से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि सदर अस्पताल मोतिहारी में एम0सी0एच0 (मातृ एवं शिशु अस्पताल), एस0एन0सी0यू0 (स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट), पी0आई0सी0यू0 (पेडियाट्रिक इन्टेनसिव केयर यूनिट), प्रसूति एवं स्त्री रोग, सर्जरी, नेत्र रोग, ई0एन0टी0 (कान, नाक एवं गला), आर्थोपेडिक आदि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और अल्ट्रासाउण्ड, ई0सी0जी0, एक्स–रे, ब्लड बैंक, पैथोलॉजिकल जाँच, डायलिसिस आदि की सुविधायें भी उपलब्ध हैं । मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब सुपर स्पेशियलिस्ट हॉस्पिटल सभी सदर अस्पताल अगले पांच साल में बनेंगे । माननीय सदस्य की भावना का हम ध्यान रखेंगे और मोतिहारी जिला बड़ा जिला है निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता हम रखेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–60, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पुनर्विकास योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है । सम्पूर्ण निर्माण कार्य तीन फेज में किया जाना है । वर्तमान में प्रथम फेज के दो टावरों का उद्घाटन किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न विभागों के ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 सेवा प्रारंभ की जा चुकी है ।

वर्तमान में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में एम0आर0आई0 मशीन इन्सटॉल हो चुकी है । शीघ्र तकनीशियनों की सेवा उपलब्ध कराकर इसे चालू करा दिया जायेगा । सी0टी0 स्कैन मशीन के लिए वर्किंग परमिशन हेतु Atomic Energy Regulatory Board से प्रक्रिया की जा रही है । वर्किंग परमिशन प्राप्त होते ही इसे चालू कर दिया जायेगा ।

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में फिलहाल पी0पी0पी0 मोड के तहत एम0आर0आई0 एवं सी0टी0 स्कैन जाँच की सुविधा मरीजों को प्रदान की जा रही है । विगत तीन माह में एम0आर0आई0 एवं सी0टी0 स्कैन जाँच संबंधी सूचना निम्नवत् है–

माह का नाम	MRI जांच की संख्या	CT स्कैन जांच की संख्या
नवम्बर, 2025	778	2028
दिसम्बर, 2025	856	1897
जनवरी, 2026	863	1895
कुल –	2497	5820

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पुनर्विकास योजना के तहत उपकरणों को अधिष्ठापित किया जा रहा है । उपकरणों के अधिष्ठापित होते ही इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम0आर0आई0 मशीन इंस्टॉल की जा चुकी है । शीघ्र तकनीशियन की सेवा उपलब्ध कराने हेतु इसे चालू करा दिया जाएगा । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व स्तरीय अस्पताल पी0एम0सी0एच0 है जिस पर हम लोग को गर्व है । माननीय मंत्री जी यह बताएं कि एम0आर0आई0 तकनीशियन के लिए पूर्व से कितने पद रिक्त हैं और जो रिक्ति हैं, उस रिक्ति पर कब तक सरकार नियुक्त करके एम0आर0आई0 जो नया इंस्टॉल किया गया है उसको चालू करा दिया जाएगा । इसी में महोदय, दूसरा पूरक है कि सी0टी0 स्कैन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच के बाद वर्किंग परमिशन अब नहीं दिए जाने के कारण इसको चालू नहीं की गई है तो सरकार उसके लाइसेंस हेतु कब इसकी प्रक्रिया की है और कब तक इसको चालू किया जाएगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, पहला जो विषय माननीय सदस्य ने पूछा कि कितनी रिक्ति थी वह प्रश्न में नहीं है यदि प्रश्न में रहता तो उसकी जानकारी लेकर के मैं आता । दूसरा महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में प्रक्रिया क्या चल रही है, कैसे चल रही है । महोदय, प्रक्रिया शुरू हुई है तभी तो मैंने जवाब दिया है कि इसकी प्रक्रिया की जा रही है और उसकी प्रक्रिया तय करता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और उसके तहत वह अपनी विभिन्न प्रकार की जांच करता है और सारे तरह की समीक्षा करने के बाद वर्किंग परमिशन देता है । मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र वर्किंग परमिशन मिल जाएगी और वर्किंग परमिशन मिलने के बाद हम उसको चालू कर देंगे । सरकार को चालू करने की इच्छा है तभी तो हमने उसके लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से आग्रह किया है । दूसरा महोदय, जो तकनीशियनों की उपलब्धता का विषय है मैंने जवाब में लिखा है कि तकनीशियनों की सेवा शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–61, श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या–92, सकरा (अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य में संचालित एक सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान है । अतः विगत वर्षों से निरंतर यहाँ ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 दोनों स्तर के इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 2025 में कुल 50,284 (पचास हजार दो सौ चौरासी) मरीजों को आई0पी0डी0 में भर्ती कर इलाज किया गया ।

संस्थान के आपातकालीन विभाग में आये मरीजों को सर्वप्रथम ट्राएज में इलाज शुरू करते हुए मरीजों की चिकित्सा स्थिति के अनुसार उन्हें बेड उपलब्ध कराया जाता है ।

संस्थान में आपातकालीन वार्ड, आई0सी0यू0 एवं वेंटिलेटर बेड की संख्या सीमित रहने के कारण आपातकालीन विभाग में मरीजों को बेड मिलने में कभी–कभी समस्या उत्पन्न होती है।

बिहार सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में 500 शैय्या के भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 250 शैय्या के दो ब्लॉक क्रियाशील हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न विभागों का सामान्य बेड/एच0डी0यू0 बेड/ आई0सी0यू0 बेड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है । इसके अतिरिक्त 1200 बेड का अस्पताल भवन निर्माणाधीन है ।

निर्माणाधीन 500 बेड में से शेष बचे 250 बेड की क्रियाशील होने तथा 1200 बेड का अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आपातकाल वार्ड, आई0सी0यू0 एवं वेंटिलेटर बेड की संख्या में बढ़ोतरी होगी । तब यह समस्या काफी हद तक ठीक हो जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री आदित्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री आदित्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जो जवाब इन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं । इनके द्वारा अतिरिक्त 1200 बेड का भवन निर्माण कार्य चल रहा है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आई0जी0आई0एम0एस0 में जो मरीज रेफर होकर आते हैं, हम लोगों के पास पेशेंट कॉल करते हैं कि सर हम आए हैं यहां अस्पताल में, बेड की व्यवस्था नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। माननीय महोदय हम लोग अस्पताल के डायरेक्टर को कॉल करते हैं तो वहां से रिस्पांस नहीं होता है, लेटर पैड पर भी लिख कर देते हैं तो रिस्पांस नहीं हो पाता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से...

अध्यक्ष : अभी बेड कम है ।

श्री आदित्य कुमार : हां, बेड कम है ।

अध्यक्ष : बेड बढ़ाया जा रहा है सरकार ने बताया है ।

श्री आदित्य कुमार : महोदय, हां बेड का जवाब तो आया है । लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं उन लोगों के लिए भी एक कोटा निर्धारित किया जाए कि जब उनका कॉल जाए, उनके पेशेंट जो आते हैं इलाज कराने के लिए यहां पटना आई0जी0आई0एम0एस0 में तो उनको बेड उपलब्ध करा दिया जाए माननीय सदस्यों के द्वारा भी क्योंकि हम लोग बहुत समस्या झेलते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय आई0जी0आई0एम0एस0 एक ऐसा संस्थान है जिस पर बिहार गर्व करता है और विगत वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आई0जी0आई0एम0एस0 का काफी विस्तार हुआ है । कुछ वर्ष पूर्व आई0जी0आई0एम0एस0 केवल 600 बेड का अस्पताल होता था । आज लगभग 2000 बेड का अस्पताल हो गया है । महोदय, बहुत शीघ्र 1450 बेड करीब उसमें और बढ़ने वाले हैं और मैंने अपने जवाब में लिखा है कि 2025 में 50,284 मरीजों को आई0पी0डी0 में भर्ती करके इलाज किया गया है । महोदय, ओ0पी0डी0 की बात मैं नहीं कर रहा हूं । 50,284 मरीजों की भर्ती हुई अस्पताल में और उनका ट्रीटमेंट हुआ है और संस्थान के आपातकालीन विभाग में आए मरीजों को ट्राएज में ले जाकर फिर उनको किस डिपार्टमेंट में भेजना है वह काम किया जाता है । माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहां स्वास्थ्य सुविधा बढ़ें उसपर निमित्त सरकार काम कर रही है और मैंने जवाब में लिखा है कि एक 500 बेड का और एक 1200 बेड का अस्पताल बन रहा है 500 बेड में से 250 बेड का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है दो ब्लॉक का और बाकी जो दो ब्लॉक बचे हैं वह दो महीने के अंदर शुरू हो जाएगा । महोदय, शेष जो 1200 बेड के निर्माण का कार्य चल रहा है वह अगले वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने तक वह पूरा हो जाएगा । महोदय, जब बेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को सुविधा और ज्यादा मिलने लगेगी । जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा पैरवी का विषय है तो जो अस्पताल है जब बेड खाली रहेगा तो निश्चित रूप से लोगों की सेवा के लिए वह अस्पताल है कोई भी बेड खाली नहीं रहता है । हां, माननीय सदस्य लोग जब आग्रह करते हैं तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन भी प्राथमिकता के आधार पर उनके विषयों को देखता है, अस्पताल की नजरों में सभी रोगी और मरीज एक समान होते हैं फिर भी माननीय सदस्यों के द्वारा जो आग्रह किया जाता है उसको प्राथमिकता से देखा जाता है ।

टर्न–2 / हेमन्त / 20.02.2026

अध्यक्ष : मो0 कमरूल होदा जी।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम दिल्ली एम्स जाते हैं, तो हम लोगों के लिए पी0आर0ओ0 है कार्ड बनाने के लिए, वहां प्रिविलेज है, तो क्या एम्स की तर्ज पर यहां प्रिविलेज देने का सरकार काम करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, कोई दूसरा खड़ा होकर पूछता, तो मुझे अच्छा लगता। चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं। कोई महीना नहीं जाता होगा, जब इनकी पैरवी रात को 12 बजे भी, मैं सुनता हूं और रात को 12, साढ़े बारह बजे इनके जो मरीज होते हैं, उनका इलाज कराता हूं और क्या फोन पर हमको बोलते हैं, सदन में नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर राजद के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं और मैं सामने कह रहा हूं, करता हूं कि नहीं करता हूं, बताइए। आज तक कभी भी उस आई0जी0आई0एम0एस0 की पैरवी फेल हुई हो, तो बताइए। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो, दवा की जरूरत पड़ी हो, मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराना हो, सुबह के 8 बजे की बात हो और रात को 12.30 बजे की भी बात हो, मंगल पांडे फोन उठाया है कि नहीं चंद्रशेखर जी का और वह काम हुआ है कि नहीं, वह बताएं।

अध्यक्ष : मो0 कमरूल होदा।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : चन्द्रशेखर जी, जो आप फोन पर बोलते हैं, अगर सही–सही बता देंगे, तो खराब हो जायेगा।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय,..

अध्यक्ष : बैठ जाइये, आपकी सारी बातें आ गयी हैं। मो0 कमरूल होदा जी।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी बाकी विधायकों को भी यह सुविधा उपलब्ध करा दें।

अध्यक्ष : जरूर दिया जायेगा।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमारे माननीय सदस्य लोग कह रहे थे, माननीय मंत्री, मंगल पांडे जी ने, जो माननीय सदस्य चन्द्रशेखर जी, जो पूर्व मंत्री हैं उनके संबंध में कहा, सच पूछते हैं तो सत्ताधारी दल के सदस्यों को ईर्ष्या हो रही है।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम किस नंबर पर बात करें, कहीं इनके पास भाभी का तो नबंर नहीं है ? क्योंकि हम लोगों से तो बात होती नहीं है।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–62, मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या–54, किशनगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 12 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, 35 सदर अस्पताल, 34 एस०एन०सी०यू०, 58 अनुमंडलीय अस्पताल, 66

रेफरल अस्पताल, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 327 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1497 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के कार्यरत 2701 विशेषज्ञ चिकित्सक, 6726 सामान्य चिकित्सक, 596 दन्त चिकित्सक एवं बिहार आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के 3044 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 234 विशेषज्ञ चिकित्सक (संविदा) एवं 834 सामान्य चिकित्सक (संविदा) द्वारा प्रतिमाह 33.22 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जाता है।

सभी अस्पतालों में फार्मासिस्ट द्वारा ही दवा वितरण की जाती है। विदित हो कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के स्वीकृत 3180 पद के विरुद्ध 489 कर्मी कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा के अधार पर कुल–494 फार्मासिस्ट नियोजित है। फार्मासिस्ट के कमी को दूर करने हेतु 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को दिनांक– 01.11.2024 को भेजी गयी है। आयोग द्वारा न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर उत्तीर्ण 1025 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक–06.02.2026 से 10.02.2026 तक किया गया है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग से फार्मासिस्ट का अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र सम्पन्न कर ली जाएगी।

विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन) के कुल–304 एवं दन्त चिकित्सक के कुल– 808 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। अनुशंसा प्राप्त होने पर चिकित्सकों का पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

श्री मो0 कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, सरकार एक तरफ दावा करती है कि 1 महीना में 422 मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है और वहीं पर किशनगंज जिला में 204 पद हैं, जिसमें से मात्र 60 पद ही वहां पर डॉक्टर के हैं, 144 पद रिक्त हैं। ये एक दिन में 422 और महीना में 12 हजार मरीज का इलाज किया जाता है। कौन इसका इलाज करता है? एमबीबीएस के भरोसे में कोई भी...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं। महोदय, रेफरल हॉस्पिटल में पद रिक्त हैं, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप रेफरल हॉस्पिटल, पोठिया के बारे में बताएं कि पिछले फरवरी महीना में कितने मरीजों का इलाज हुआ है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है और सिर्फ..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न में अंकित नहीं है। यदि अंकित रहता, तो मैं डाटा भी देता। फिर भी माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। मैं आज शाम तक उनके मोबाइल पर व्हाटस्एप से उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, एक रेफरल हॉस्पिटल जिसके बारे में मैंने बताया, पोठिया रेफरल हॉस्पिटल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा से कि एक कमेटी गठन करके उसकी जांच करवायी जाए। वहां पर डॉक्टर बहाल हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ कागज पर हॉस्पिटल चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक कमेटी बना करके उसकी जांच करवायी जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैं सिविल सर्जन से उसकी जांच करा लेता हूं।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीमती अनिता।

तारांकित प्रश्न संख्या–'क' 185, श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या–239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक ।

2–स्वीकारात्मक ।

3– जिला पदाधिकारी नवादा से उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक– 586 दिनांक– 16.02.2026 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती अनीता : महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी, पर्यटन विभाग से था। ये एक्सेप्ट तो किए हैं, सर, लेकिन एक बिंदु मैं जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि अधूरा है एक्सेप्टेंस, क्लैरिटी उसमें नहीं है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें यह वर्णित नहीं है कि ग्राम बुधौली में पौराणिक स्थल से बने स्थलों की विशिष्टता काफी महत्वपूर्ण है। यहां बने बौद्ध मठ, तालाब, 52 कोठी, 53 द्वार, दुर्गा मंडप इत्यादि काफी भव्य हैं यहां। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना अति आवश्यक है। ग्राम बुधौली के इन सभी स्थलों को कब तक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग के द्वारा पटना से बोध गया, राजगीर तक पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए जो सरकारी और प्राइवेट बस जाती हैं, उसे पार्वती होते हुए बुधौली तक विस्तारित कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए।

श्रीमती अनीता : जी, धन्यवाद सर।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह है नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड पकरीवरावां के ग्राम बुधौली में पौराणिक काल से ही बौद्ध मठ, 10 एकड़ का तालाब, 52 कोठी, 53 द्वार, दुर्गा मंडप इत्यादि भव्य ढंग से बना हुआ है। महोदय, हमने कहा स्वीकारात्मक है। महोदय, तो हमने इसमें कहां कटौती की है ? दूसरा खंड भी, जो इन्होंने कहा है, हमने उसको भी स्वीकारात्मक माना है। खंड तीन में, इनका है कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा बोध गया एवं राजगीर इत्यादि स्थलों में भ्रमण करने वाले पर्यटकों की बस बुधौली तक ले जाने का विचार रखती है, महोदय, हमने बताया है कि जिला पदाधिकारी नवादा से उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 586, दिनांक 16.2.2026 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, हमने कहीं इंकार नहीं किया है।

श्रीमती अनीता : महोदय, कब तक ?

अध्यक्ष : प्रतिवेदन आने के बाद।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग समीक्षा करके उसको आगे देखेंगे।

अध्यक्ष : डॉक्टर सुनील कुमार।

श्री अनीता : सर, कितने साल में या कितने महीनों में? यह मैं जानना चाहूंगी।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : शीघ्र होगा।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1693, डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या–172, बिहारशरीफ)</u>

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जवाब मिला नहीं है कि पढ़े नहीं है ?

महोदय, 1–अस्वीकारात्मक

नालन्दा जिले के अस्थावां प्रखंड अन्तर्गत मालती पंचायत के नेपुरा ग्राम में कृषि कार्य हेतु कुल चार ट्रांसफार्मर (25 के0वी0ए0) लगाये गये हैं। उक्त चार में से तीन ट्रांसफार्मर से पटवन हेतु विद्युत आपूर्ति की जा रही है। चौथे ट्रांसफार्मर को उच्च विभव लाईन बनाने के क्रम में स्थानीय अवरोध एवं फसल होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

2– वर्तमान में पटवन हेतु उपभोक्ताओं को पूर्व से अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर एवं कृषि हेतु अधिष्ठापित तीन नये ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

3– स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर 31 मार्च, 2026 तक आठ अदद पोल लगाकर उक्त ट्रांसफार्मर को भी चालू कर दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–1694, डॉ0 कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या–170, बरबीघा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : (1) वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–1071 (12), दिनांक–04.10.2016 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक–1171, दिनांक–08.06.2017 के द्वारा सभी जिला अस्पताल को एक–एक शव वाहन एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दो–दो शव वाहन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में शेखपुरा जिलान्तर्गत में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा दो (02) शव वाहन की सेवा संचालित है। डायल नं0–102 पर कॉल प्राप्त होने पर शव वाहन की सेवा उपलब्ध करायी जाती है, जो रेफरल अस्पताल, बरबीघा सहित जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लागू है।

राज्य में कुल 106 शव वाहन राज्य के जिला अस्पताल एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा अनुमण्डलीय अस्पतालों में परिचालित है। इसके अतिरिक्त 14 नये शव वाहन के क्रय की कार्रवाई BMSICL, Patna द्वारा प्रक्रियाधीन है।

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सभी सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार सभी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमण्डल अस्पताल तथा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पतालों को यह भी निदेश दिया गया है कि ''उपलब्ध शव वाहन के व्यस्त होने की स्थिति में उनका यह दायित्व होगा कि शव के परिवहन हेतु अन्य एम्बुलेंस अथवा किराये का वाहन उपलब्ध करायें तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–7687, दिनांक–06.02.2026 द्वारा इस हेतु अधिकतम 2000/–(दो हजार रूपये) की राशि निर्धारित की गई है, जिससे शव वाहन की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सभी के लिए सुलभ होगी।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत बरबीघा रेफरल अस्पताल में सामान्य सर्जन के 01 पद , स्त्री रोग विशेषज्ञ के 01 पद, शिशु रोग विशेषज्ञ के 01 पद, मूर्च्छक के 01 पद एवं जी0एन0एम0 के 04 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध 01 सामान्य सर्जन, 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 01 मूर्च्छक एवं 04 जी0एन0एम0 पदस्थापित एवं कार्यरत हैं, जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

रेफरल अस्पताल, बरबीघा में हड्डी रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में लोगों की बहुत बड़ी आबादी है। वहां के लोग इलाज के लिए बरबीघा रेफरल अस्पताल आते हैं, परंतु अधिकांश मरीज को डॉक्टर की व्यवस्था में कमी रहने के कारण

वहां से स्थानांतरित कर दिया जाता है, या तो शेखपुरा, या तो नजदीक पावापुरी, जो कि बरबीघा से दूर है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : पूरक पूछना है सर।

अध्यक्ष : हां, पूरक पूछ लीजिए।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : तो मंत्री जी से मेरा पहला पूरक है कि शिशु रोग विशेषज्ञ का एक पद बरबीघा रेफरल हॉस्पिटल में सृजित है। उस पर कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहां जल्द से जल्द एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, हड्डी रोग विशेषज्ञ का पद सृजित नहीं है, जो आज की डेट में वहां बहुत जरूरी है। इसलिए पद का सृजन करके वहां पर भी एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। तीसरा है, सामान्य सर्जन के जो डॉक्टर पदस्थापित हैं, वह निष्क्रिय हैं, उनको सर्जरी करने में डर लगता है और आज तक एक भी सर्जरी नहीं कर पाए हैं, जैसी हमको जानकारी मिली है। तो उनके स्थान पर कोई योग्य, जो सर्जन हों, उनका स्थानांतरण करने की कृपा करें। यही मंत्री जी से अनुरोध है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

टर्न–3 / संगीता / 20.02.2026

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय लाया है, मैंने शुरू में दूसरे प्रश्न के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री जी की स्वयं की इच्छा है कि जो हमारे प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय अस्पताल हैं, वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा दी जाए और उसी के लिए सात निश्चय पार्ट–3 में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में ऑर्थोपेडिक सर्जन का पद वहां सृजित भी किया जाएगा और उपलब्धता के आधार पर उनकी नियुक्ति भी की जाएगी । शेष जो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर के बारे में, पीडिया के डॉक्टर के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसको दिखवा लेता हूं, उपलब्धता के आधार पर उसकी पदस्थापन करूंगा । जिस सर्जन के बारे में कहा गया है कि सर्जन ने सर्जरी वहां नहीं की है, मैं आज ही वहां सिविल सर्जन से उसका पूरा डिटेल पिछले महीने का रिपोर्ट मंगा लेता हूं कि सर्जन ने सर्जरी किया, नहीं किया और यदि नहीं किया होगा तो उन पर यथोचित कार्रवाई भी होगी और उनके बदले किसी दूसरे को भेजने के संदर्भ में विभाग काम भी करेगा ।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार चौधरी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1695, श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या–80, बेनीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक दुखवा चौपाल के आश्रित श्रीमती घुरनी देवी, पति–स्व0 दुखवा चौपाल, गांव–विश्वनाथपुर, वार्ड नं0–15, पंचायत–तरौनी को चेक सं0–319598, दिनांक– 12.02.2026 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि मो0–4.00 लाख (चार लाख) रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । हम आपके संरक्षण से संयोग से यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अभी सर्पदंश से मृत्यु के बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आपदा पीड़ित के परिवार को अनुदान की राशि मिलती है, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि दिनांक 07.09.2024 को विरोल प्रखंड के देकुलीधाम निवासी चतुरानंद गिरी की पुत्री संख्या कुमारी की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी, लगभग 18 माह बीत चुका है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है । मैं सिर्फ आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि पोस्टमार्टम अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में होता है, वह दरभंगा में भी करवा दिया जाए और अविलंब उसकी रिपोर्ट आ जाए, इसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का । उत्तर आया था बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार राज्य में इस समय लगभग 3 हजार से अधिक विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है । 3–3 साल, 4–4 साल का विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है । हमारे क्षेत्र का एक मामला है जिसमें 4 साल हो गया, विसरा रिपोर्ट नहीं आया तो जरा इसपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि विसरा रिपोर्ट समय पर आये, चूंकि सर्पदंश में आधे से अधिक लोगों की मौत हार्ट–अटैक से हो जाती है और हार्ट–अटैक के केस में विष चढ़ता नहीं है इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विष की पुष्टि नहीं होती है । उस परिस्थिति में विसरा रिपोर्ट भेजा जाता है करने के लिए और विसरा रिपोर्ट 2–2 साल, 3–3 साल में नहीं आता है तो गरीब पैसा से वंचित रह जा रहा है और सरकारी ऑफिस का चक्कर लगा–लगाकर परेशान हो जाता है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से और मेरा सवाल भी है कि इसको जल्दी इसका संपादन कराने की दिशा में कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष : सरकार दिखवा लेगी । सरकार समीक्षा कर लेगी, समीक्षा करने के बाद प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द मिले ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा मानवता के आधार पर, कई वर्ष पुराना यह नियम है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, उसका 5 बजे के पहले तक ही पोस्टमार्टम होना है, इसके बाद जिलाधिकारी अनुमति देंगे उसके बाद पोस्टमार्टम होगा । हम मंत्री जी से

आग्रह करते हैं, बिहार में लगातार एक्सीडेंटल केस तो बढ़ा ही है पूरे देश में, दुनिया में महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था क्या मंत्री जी कर सकते हैं कि जो बेचारे किसी के बच्चे डेथ कर जाते हैं और जिनको अपने विधायक–एम0पी0 से परिचय नहीं होता है, रात भर उनके मां–पिता अस्पताल के बाहर रोते रहते हैं, तो अब जो पहले वह कानून बना था जब लालटेन और ढिबरी में पोस्टमॉर्टम होता था, अब सारी व्यवस्था है पोस्टमार्टम रूम में तो उस नियम में संशोधन हो कि जब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तत्काल उसको पोस्टमार्टम करके और उनके परिवारजनों को बॉडी सौंप दिया जाए, चूंकि सारे विधायक इससे भी परेशान रहते हैं, 12 बजे रात को फोन आता है कि पोस्टमार्टम करा दीजिए तो हम आग्रह करेंगे कि इसको देखकर कोई संशोधन इसमें किया जाए कि जब कोई इस तरह की कोई घटना हो, वह अपने हिसाब से वह डॉक्टर अस्पताल से पोस्टमार्टम करके परिवारजनों को सौंप सके ।

अध्यक्ष : सरकार देखेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1696, श्री नीरज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–45, छातापुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–485, दिनांक–14.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, साहेवान का भवन पुराना है तथा उक्त भवन से स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन नहीं किया जाता है। पुराने भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण हेतु जाँचोपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) से विभागीय पत्रांक–433(10) दिनांक–18.02.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। तदुपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, साहेवान स्थानीय पंचायत भवन में संचालित किया जा रहा है, जहाँ पदस्थापित 02 ए0एन0एम0 द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवायें दी जा रही हैं।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब तो आया है लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि निधि की उपलब्धता में भवन बनाया जाएगा । महोदय, जैसे–तैसे अभी उपस्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है, बिना भवन के काफी परेशानी होती है, दूसरी तरफ ये भवन 30 साल पहले बना हुआ था, छत ढला हुआ है, खिड़की–केबाड़ी नहीं है, बरसात के दिनों में आधा भवन पानी में डूब जाता है और विरोधी वहां जा–जाकर फोटो खिंचाते हैं, विडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं कि देखिए सुशासन का

हॉस्पिटल, इससे काफी परेशानी होती है । चुनाव के समय वे लोग काफी परेशान किए थे तो माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि भवन निर्माण जरूर करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा । ऐसे भी माननीय नीरज जी की बात मैं काट नहीं सकता हूं ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, एक आग्रह होगा, जब तक वह भवन बनता है नया भवन, तब तब कम से कम उसको डिमोलिश करवा दिया जाए ताकि लोग फोटो न खींचे । उसको तुड़वा दिया जाए नहीं तो फोटो खींच–खींच के लोग वायरल करते रहता है ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में काम भी प्रारंभ हो जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1697, श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या–4, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा के नये भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–383(7), दिनांक– 23.01.2025 को दी गयी है। तत्पश्चात भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा निविदा का प्रकाशन दिनांक–20.05.2025 को किया गया था, किन्तु एकल निविदा होने के कारण निविदा रद्द करते हुये दिनांक–29.08.2025 को पुनः निविदा प्रकाशित की गयी है। वर्त्तमान में तकनीकी मूल्यांकन (Techinal Evaluation) का कार्य निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में अनुमंडलीय अस्पताल का संचालन 50 शय्या वाले प्री–फैब फिल्ड अस्पताल में किया जा रहा है, जो ठीक अवस्था में है।

अनुमंडलीय अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु प्रकाशित पुनर्निविदा का निष्पादन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बगहा में अनुमंडलीय अस्पताल है, जो एक जिला से बहुत बड़ा अनुमंडल है वह और भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी जंगल और पहाड़ों में बसा हुआ वह अनुमंडल है, नदी भी है और गंडक नदी भी है और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 20.05.2025 में निविदा हुआ था, निविदा के बाद वह कैंसिल हो गया है, चूंकि वह रद्द हो गया था लेकिन 29.08.2025 को निविदा हुआ है और आज 6 महीना तक नहीं हुआ है, क्या कारण है ? इस वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू होगा या नहीं, चूंकि वह एक निचले पायदान पर, आपकी राजधानी से, आपकी सरकार से निचले पायदान पर वह विधान सभा बसा हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में बताया है कि पहली बार जब निविदा हुई थी तो वह एकल निविदा हो गया था और जब निविदा एकल होता है तो वह मान्य नहीं होता है, पुनर्निविदा करनी पड़ती है । पुनर्निविदा की प्रक्रिया की गई है और उसका Techinal Evaluation का कार्य BMSICL के द्वारा किया जा रहा है तो Techinal Evaluation के बाद Financial Evaluation होगा, उसके बाद वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा । उसके बाद जो भी एजेंसी होगी, उससे एकरारनामा होगा और एकरारनामा के बाद कार्य शुरू होगा तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की जो अपेक्षा है कि इस वित्तीय वर्ष में हो जाए तो एक महीने में ये सारी प्रक्रिया तो शायद नहीं हो पाएगी लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में यह जरूर हो जाएगा और सरकार ने इसको बहुत प्राथमिकता से बनाने के लिए सोचा है । यह बॉर्डर का एरिया है और माननीय सदस्य को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पूर्व में बताया है कि इसका निर्माण शीघ्र करा लिया जाएगा ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं । पूर्व में मेरा एक क्वेश्चन था जो आया था लेकिन डिबेट नहीं हो पाया...

अध्यक्ष : आज की बात कीजिए न, आज जो क्वेश्चन आपका है, उसमें मंत्री जी ने कहा न कि टेंडर हो गया है, टेक्निकल बीड खुल गया है अब रेट बीड खुलेगा, एकरारनामा होगा और काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगा ।

श्री राम सिंह : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1698, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक ।

2– आंशिक स्वीकारात्मक ।

उक्त शौचालय में मरम्मति, यथा नल, फ्लश, विद्युत्त, सिमेंटिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग इत्यादि की आवश्यकता है ।

3– निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में संबंधित शौचालय की मरम्मति हेतु पंचायत स्तर पर प्रस्ताव संख्या 04 में शामिल किया गया है । मरम्मति के उपरान्त शौचालय को क्रियाशील कर दिया जायेगा ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आया है । हमारा प्रश्न था कि सी0एस0आर0 के तहत पावरग्रीड में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है, पावरग्रीड से, तो उत्तर सकारात्मक है । दूसरा सवाल था हमारा कि उद्घाटन के उपरांत अभी तक वह शौचालय चालू नहीं हुआ है, 19 और 20 के ही योजना के तहत ये बनाया गया है, 18 लाख, 19 लाख रुपया का बना है तो सरकार का जवाब

है कि मरम्मति होने पर इसको चालू किया जाएगा, अभी चालू ही नहीं हुआ, उद्घाटन के बाद खुला ही नहीं तो मरम्मति की जरूरत कहां पड़ी ? महोदय से आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द चालू करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1699, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या–1, वाल्मीकिनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– अस्वीकारात्मक ।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बगहा ने प्रतिवेदित किया है कि पश्चिम चंपारण जिला के पंचायत हरनाटाड़ खाता सं0–57, खेसरा सं0–63/01 स्थित सामुदायिक भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया और न ही कार्यस्थल पर उद्घाटन से संबंधित शिलापट्ट का अधिष्ठापन किया गया है ।

2– अस्वीकारात्मक ।

विषयांकित सामुदायिक भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया है ।

3– उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है लेकिन ये जो जवाब आया है, सरासर गलत है । मैं जी0पी0एस0 के माध्यम से भी सारा फोटो वहां का मंगा लिया हूं और मैं कहूंगा कि इसको अध्ययन करते हुए, इसपर अच्छी तरह से जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है, इसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय मंत्री जी, तो ये कागज हम भिजवा देते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1700, श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या–29, रून्नीसैदपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक ।

सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के टाउन फीडर से प्रखंड मुख्यालय के निकट के पंचायतों में लगभग 22 घंटे निर्बाध विद्युत्त आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

सुरसंड पंचायत रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय से निकट नहीं रहने के कारण उक्त पंचायत को टाउन फीडर से जोड़ना तकनीकी रूप से संभव नहीं है ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । उत्तर में है, सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के टाउन फीडर से प्रखंड मुख्यालय के निकट के पंचायतों में लगभग 22 घंटे निर्बाध विद्युत्त आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

...क्रमशः...

टर्न–4 / यानपति / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, और टंकण मिस्टेक के कारण मोरसंड के जगह पर सुरसंड लिख दिया है । मोरसंड पंचायत रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय के निकट नहीं रहने के कारण उक्त पंचायत को टाउन फीडर से जोड़ने की तकीनीकी रूप से होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा करीब–करीब 10 पंचायत ऐसा है, जिसमें कि मोरसंड है, अतरी है, टिकौली है, बघारी है और उधर बेलाही नीलकंठ है । करीब 10 पंचायत ऐसा है जो कि बिजली से त्रस्त रहता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नया फीडर दें नहीं तो टाउन शिप से जुड़वा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1701, श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं॰–180, बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खुसरूपुर शहरी क्षेत्र में एल०टी० लाईन ए०बी० केबल से विस्तारित है एवं मिसी एवं घाघ में एल०टी० के नंगे तारों को ए०वी० केबल से बदलने हेतु सर्वे कर रिकंडक्टरिंग की कार्रवाई की जा रही हैं, जिसे माह जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा । उक्त क्षेत्रों में बिजली का नंगा तार के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से दुर्घटना की सूचना कार्यालय को अप्राप्त है ।

पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर विधान सभा के अंतर्गत मिसी एवं घांघ में 33 / 11 के0वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, बख्तियारपुर से निकलने वाली 11 के०वी० बाढ़ डुप्लीकेट फीडर एवं खुसरूपुर शहरी क्षेत्र में 33 / 11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र खुसरूपुर टाउन फीडर द्वारा सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, संतुष्ट हैं लेकिन एक पदाधिकारी के द्वारा गलत जवाब मिला है कि खुसरूपुर में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है । वह जब आग लगी थी लगभग 20–25 दिन पहले मैं खुद गया था । बाकी हर जगह नंगा तार है, मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि हर जगह

दिखवा कर सुचारू रूप से किया जाय और आपके आदेशानुसार मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से एक आग्रह करता हूं कि...

अध्यक्ष : आपका तो ऊर्जा विभाग से है । वह अलग से कर लीजिएगा ।

श्री अरूण कुमार : हॉस्पिटल का ओपनिंग किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें विचार नहीं हुआ, उसमें देख लिया जाय ।

अध्यक्ष : अरूण जी, क्वेश्चन ऊर्जा विभाग का है, वह अलग से पूछ लीजिएगा, पत्र के माध्यम से आग्रह कर लीजिएगा ।

श्री अरूण कुमार : जी महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर दिया जा चुका है । माननीय सदस्य संतुष्ट भी हैं ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1702, डॉ॰ प्रकाश चंद्र (क्षेत्र सं॰–220, ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चहारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है । ओबरा प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुदवाँ के चहारदीवारी निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार स्वीकृति दी जायेगी ।

डॉ0 प्रकाश चंद्र : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन स्पष्ट नहीं है । मैंने पूछा था कि ओबरा प्रखंड के खुदवाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चहारदीवारी नहीं है चहारदीवारी सरकार कराने का विचार रखती है या नहीं । इसपर उत्तर मिला है कि BMSICL के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, प्राक्कलन तैयार होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार स्वीकृति दी जायेगी । तो मेरा पूरक प्रश्न है कि अगले वित्तीय वर्ष में चहारदीवारी निर्माण करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ।

डॉ0 प्रकाश चंद्र : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय विधायक स्वयं भी फोन करते हैं तो वहां अटेंडेंट न फोन को ठीक से रेस्पोंड करते हैं और 10 बार कॉल करने के बावजूद भी आजतक किसी का बेड उपलब्ध नहीं करवाया गया है ।

अध्यक्ष : दिखवा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1703, श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–224, रफीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रफीगंज में मूर्च्छक के स्वीकृत 01 पद के विरुद्ध 01, फिजिशियन के

स्वीकृत 01 पद के विरुद्ध 01, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत 04 पद के विरुद्ध 03, दन्त चिकित्सक के स्वीकृत 02 पद के विरुद्ध 01, आयुष चिकित्सक के स्वीकृत 01 पद के विरुद्ध 01 वर्तमान में पदस्थापित हैं ।

इसके अतिरिक्त 01 फार्मासिस्ट, 02 ए०एन०एम० एवं 05 जी०एन०एम० भी वर्तमान में पदस्थापित हैं जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा रही है ।

इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में विभागीय अधिसूचना संख्या–249 (2) दिनांक–06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन) का नियुक्ति–सह–पदस्थापन किया गया है ।

उक्त अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं एक्स–रे मशीन उपलब्ध है। अल्ट्रासाउण्ड के पंजीयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र अल्ट्रासाउण्ड जाँच की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी । संस्थान में एक्स–रे की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि एक्स–रे टेक्नीशियन के 1232 एवं फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के आलोक में लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है । अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वहां रफीगंज में रेफरल हॉस्पिटल है लेकिन वहां सिर्फ रेफर ही किया जाता है, 14 की जगह तीन ही डॉक्टर हैं और विभागीय डॉक्टर एक भी नहीं है । विशेषकर के प्रसूति के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं है, शिशु रोग के लिए कोई डॉक्टर नहीं है तो महोदय यह जो खाली जगह है 14 डॉक्टरों की, जो विशेषज्ञ हैं उनकी वहां पोस्टिंग की जाय, यही निवेदन करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, जवाब में मैंने लिखा है वहां पर एक मूर्च्छक हैं, एक फिजीशियन हैं, एक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एक फिजीशियन हैं और चार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध वहां पर नियुक्त हैं, एक दंत चिकित्सक हैं, एक आयुष डॉक्टर हैं । इस प्रकार से सात डॉक्टर वहां पर हैं और अन्य और चिकित्सकों की वहां आवश्यकता है, मैं भी मानता हूं, विभाग के द्वारा लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है । पिछले डेढ़ महीने के अंदर में स्वास्थ्य विभाग में 2500 चिकित्सकों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है और आगे भी ये प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही है । माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में मैं प्राथमिकता पर उस अस्पताल में चिकित्सकों की पदस्थापना का काम करूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री देवेशकान्त सिंह । माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र जी प्राधिकृत हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1704, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं0–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के द्वारा आवेदन/कम्पलेन समर्पित करने के उपरांत तकनीकी जाँच की जाती है आवश्यकतानुसार विभागीय नियमानुसार ट्रांसफॉर्मर के क्षमता का विस्तार अथवा अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन का कार्य किया जाता है।

वस्तुस्थिति यह है कि गोरेयाकोठी प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार Revamped Distribution Sector Scheme से 16 अदद अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन करते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम कालाडुमरा में 01 अदद 25 के०वी०ए० का ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित किया गया है। ग्राम–खुलासा में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है एवं लो वोल्टेज की समस्या नहीं है। ग्राम–मोहम्मदपुर में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विस्तार हेतु सर्वे का कार्य कर लिया गया है। कार्य को पूरा करने का लक्ष्य फरवरी 2026 है।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बहुत ही स्पष्ट उत्तर आया है और उत्तर में इन्होंने बताया है कि तय सीमा के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदल दिया जाता है । महोदय, तय सीमा इनका क्या है, क्योंकि तीन महीना हो गया और ट्रांसफॉर्मर अभीतक बदला नहीं गया है । दूसरा महोदय, इन्होंने कहा है कि जो सर्वे का कार्य कर लिया गया है, दूसरा पूरक है, और गोरेयाकोठी प्रखंड के कलाडुमरा, खुलासा एवं महम्मदपुर के उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये आवेदनों पर 21 तारीख को पहली बार संज्ञान लिया गया यह सारा पूरक है महोदय, तो केवल कौन अधिकारी इस तरह कर रहा है । माननीय मंत्री जी इतनी सहूलियत दे रहे हैं । बिजली इतनी मिल रही है । 125 यूनिट फ्री भी है लेकिन उसके बाद भी माननीय महोदय, ये उनके अधिकारी जो हैं ट्रांसफॉर्मर नहीं बदल रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि सर्वे कराकर मार्च तक कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1705, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. स्वीकारात्मक ।

4. वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से विभागीय पत्रांक– 2654 दिनांक–13.12.2024 के द्वारा उक्त मंदिर को विकसित करने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक– 597 दिनांक– 16. 02.2026 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 10 साल हो गया और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि माधव प्रखंड के दानेश्वर नाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 2024 में ही पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई थी । महोदय, 24–25 खत्म हो गया, अभी 26 तक इसका प्रतिवेदन नहीं आया । अध्यक्ष महोदय, अगर निदेशालय के पत्र पर जिला पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करें और जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करें, दो–दो साल से यह प्रतिवेदन विभाग द्वारा नहीं भेजा जा रहा है तो माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बताएं कि अगर मेरे सब उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अब तक दानेश्वर नाथ मंदिर को विकसित करने की सरकार ने कौन सी योजना बनाई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है महोदय । गोपालगंज जिला के माझा प्रखंड अंतर्गत दानेश्वर नाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से पत्राचार किया गया था । जिसमें मुख्यतः वर्णित स्थल के संबंध में विहित प्रपत्र में भूमि अभिलेख के आधार पर विवरणी, चौहद्दी, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व पर्यटकों के आगमन, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय एवं पर्यटन हेतु प्रस्तावित आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित स्थल जो विवाद रहित भूमि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हस्तांतरण की स्थिति, गैर मजरूआ आम खास मालिक विभागीय रैयती महामहिम राज्यपाल के हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति इत्यादि के प्रतिवेदन की मांग की जाती है । समीक्षोपरांत पुनः पर्यटकीय दृष्टिकोण से मूलभूत सुविधाओं का विकास किस प्रकार किया जाना होगा, इस संबंध में जिला पदाधिकारी से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है । महोदय, प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र कार्रवाई की जायेगी, हमने तो कहा ही है महोदय।

अध्यक्ष : सदस्य की चिंता है कि प्रतिवेदन समय पर आ जाय ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : यह गंभीर विषय है और अक्सर सरकार का जवाब होता है किसी भी पर्यटन स्थल के मामले में कि जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगकर अग्रेतर कार्रवाई की जानी है । अध्यक्ष महोदय, 2024 से सरकार के स्तर पर प्रतिवेदन अगर जिला पदाधिकारी से मांग की जा रही है प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है, सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए क्या इन विषयों की जांच निदेशालय के स्तर के पदाधिकारी से करायेगी और उसको दानेश्वर नाथ मंदिर को पर्यटकीय स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है कि नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, मैंने बता ही दिया कि शीघ्र कार्रवाई की जायेगी, तो मंदिर बनाने से मतलब है महोदय । ये जान रहे हैं महोदय, 2025 में विधान सभा का चुनाव था तो पत्राचार में स्वाभाविक रूप से थोड़ा–बहुत विलंब हो गया था लेकिन कोई वैसा विलंब नहीं है जिसके लिए जांच कराने की जरूरत है । जो विहित प्रपत्र में मांगा जाता है उसमें थोड़ा समय भी लगता है, अंचल से लेना होता है, हर जगह से प्राप्त करना होता है तो जैसे ही आ जायेगा, शीघ्र बनवा देंगे इनका ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, एक समय–सीमा तो बांधिए, दो साल से अधिक समय हो गया है ।

अध्यक्ष : आप जिला पदाधिकारी से बात कर लीजिए, अरूण बाबू ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : दो साल में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप डी0एम0 से बात कर लीजिए कि प्रतिवेदन जल्द भिजवा दें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला पदाधिकारी से बात करवा लूंगा और जितना जल्दी हो सकता है इनका काम हम करवा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1706, श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र सं0–38, झंझारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अनुमण्डलीय अस्पताल, झंझारपुर में पदस्थापित 02 शिशु रोग विशेषज्ञ, 03 आर्थोपेडिक विशेषज्ञ, 01 ई0एन0टी0 विशेषज्ञ, 03 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 01 दन्त चिकित्सक, 01 सर्जन, 02 आयुष चिकित्सक, 02 सामान्य चिकित्सक, 01 फिजियोथेरेपिस्ट एवं 01 नेत्र सहायक के द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराया जा रहा है ।

उक्त अस्पताल में पैथोलॉजिकल जांच, एक्स–रे, नेत्र जांच, अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा एवं पर्याप्त मात्रा में दवा भी उपलब्ध है ।

राज्य के सभी चिकित्सीय संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक/मानव संसाधन/उपकरण आदि की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, मैं पूरक पूछूं उससे पहले माननीय मंत्री महोदय एक प्रश्न का उत्तर पहले दे दें कि जिस अस्पताल का मैंने उल्लेख किया है, वहीं पर बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण के हो जाने के बाद इस अनुमंडल अस्पताल की क्या स्थिति रहेगी क्योंकि उसी कैंपस में, अगर मंत्री जी यह मुझे बता सकें तो मुझे पूरक पूछने में सहूलियत होगी ।

टर्न–5/मुकुल/20.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न में अंकित नहीं था, यदि अंकित होता तो विभाग में समीक्षा चर्चा करके मैं आता और जवाब माननीय सदस्य को देता, माननीय सदस्य ने इस विषय को अभी मेरे संज्ञान में लाया है, मैं जरूर इस पर चर्चा करके माननीय सदस्य को अलग से भी उसकी स्थिति से अवगत करवा दूंगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर अनुमंडल तीन विधान सभा में विभक्त है और इस अस्पताल में झंझारपुर विधान सभा, फुलपरास विधान सभा और राजनगर विधान सभा के मरीज आते हैं । विभाग के द्वारा उत्तर प्राप्त है, मैंने देखा है और मैं यह भी माननीय मंत्री जी के जो उत्तर में कि संसाधन की उपलब्धता पर चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । जो व्यवस्था और जो उत्तर विभाग के द्वारा दिया गया है, विडंबना है अध्यक्ष महोदय कि मेरा पिछला प्रश्न था झंझारपुर का, उत्तर फुलपरास विधान सभा का मुझे मिला । आज जो उत्तर विभाग के द्वारा दिया गया है, मेरे पास पूरा सेंक्शंड पोस्ट और जो उपलब्ध हैं संसाधन उसकी जानकारी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : उदाहरणस्वरूप अध्यक्ष महोदय, जवाब में है कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं और अल्ट्रासाउंड सिर्फ जो गर्भवती महिला हैं सिर्फ उनका किया जा रहा है तो जेनरल अल्ट्रासाउंड वहां नहीं हो रहा है । जो वहां पर इंस्टीच्युशनल डिलीवरी हो रहे हैं वहां उसके लिए एनेसथिसिस्ट की जरूरत है मुर्च्छक की, वह वहां पर नहीं पोस्टेड हैं तो कहीं से उनको लाना पड़ता है । जवाब में दिया गया है कि दवाइयां उपलब्ध हैं, वास्तविकता यह है कि दवाइयां उपलब्ध हैं लेकिन दवा देने के लिए जो फार्मासिस्ट हैं वह मात्र

तीन दिन वहां रहते हैं, तीन दिन वह मधुबनी प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा या पूछना चाहूंगा कि जो भी आपने कहा है कि संसाधन मैं भी स्वीकारता हूं कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कर रही है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है । सिर्फ मेरा इतना आग्रह ये स्वीकार कर लें कि स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी या सचिव समय दे दें कि मेरे साथ उस अस्पताल का भ्रमण कर लें, तकलीफ होती है कि कोविड के समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया वह चालू नहीं है, विगत 10 वर्ष में एक रुपया भी मेंटेनेंस पर खर्च नहीं किया गया उस अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उस अनुमंडल अस्पताल में मरीजों को जाने में बहुत कठिनाई हो रही है । सिर्फ क्या मंत्री जी इस बात पर सिर्फ इतना निर्देश देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव एक बार उस अनुमंडल अस्पताल का भ्रमण कर लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक प्रमुख डायरेक्टर इन चीफ को निर्देश देता हूं कि वह माननीय सदस्य के साथ कार्यक्रम तय करके अस्पताल का पूरा निरीक्षण कर लेंगे और जो भी मेडिकल कॉलेज शुरू होने के पहले हम सुविधाएं वहां उपलब्ध करा सकते हैं वह करायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1707, श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र सं0–243, चकाई)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिविल सर्जन, जमुई के पत्रांक–176, दिनांक–29.01.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनो का भवन ठीक अवस्था में है । मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), BMSICL, पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भवन में रंग–रोगन तथा मरम्मति की आवश्यकता है। इस आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित 05 चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों द्वारा संस्थागत प्रसव (वर्ष–2025 में 1996 तथा वर्ष–2026 में अबतक 255) एवं बहिर्वासी चिकित्सा सेवा (वर्ष 2025 में 26677 तथा वर्ष 2026 में अबतक 3333) सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधायें सुचारू रूप से आमजनों को उपलब्ध करायी जा रही हैं । साथ ही, यहाँ एक्स–रे, ई0सी0जी0 एवं पैथोलॉजिकल जाँच की सुविधा भी उपलब्ध है ।

साथ ही, सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन उस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं । इसमें दिया हुआ है कि भवन ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं कि भवन एकदम जर्जर है, अगर किसी के माथे पर गिर जायेगा तो क्या होगा । मंत्री जी से मैं यही जानना चाहती हूं कि इसको अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैं सदन के पटल पर वह तस्वीर रख देता हूं जो अस्पताल की तस्वीर मैंने मंगवाई है, अब इस तस्वीर को देखकर भी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भवन को तोड़कर नया बनाने की जरूरत है या जो हमने प्रतिवेदित किया है कि इसके रंग–रोगन की जरूरत है तो हमने भी माना है कि मतलब विभाग ने माना है कि रंग–रोगन की आवश्यकता है और इस आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है महोदय । मैं माननीय सदस्या को यह कहना चाहता हूं कि यदि उनको लगता है कि नहीं तोड़कर ही बनाना है तो मैं उनके साथ बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के किसी इंजीनियर को भेज देता हूं और वह साथ में जाकर चर्चा कर लें, समीक्षा कर लें और फिर निर्णय हो जायेगा महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1708, श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र सं0–228, बाराचट्टी (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवगंज बाजार उपयुक्त भूमि के अभाव में पुराने सामुदायिक भवन में संचालित है, जहाँ पदस्थापित 02 चिकित्सक (01 एम0बी0बी0एस0 एवं 01 आयुष चिकित्सक), 02 ए0एन0एम0 सहित अन्य कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवगंज बाजार के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, गया से पत्रांक–378(10) दिनांक–19.03.2025 से अनुरोध किया गया था। परन्तु उपयुक्त भूमि के अप्राप्त रहने के कारण भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार नहीं किया जा सका है। पुनः विभागीय पत्रांक–395(10), दिनांक–18.02.2026 द्वारा समाहर्त्ता, गया से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

मोहनपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डंगरा का भवन पुराना है। उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित 01 आयुष चिकित्सक, 02 ग्रेड–'ए' नर्स, 02 ए0एन0एम0 एवं अन्य कर्मियों द्वारा ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, आकस्मिक सेवा सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,

डंगरा के भवन निर्माण की स्वीकृति राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि दो जगह का मैंने सवाल उठाया था जिसमें एक जगह का इन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं है । मुझे जहां तक मालूम है, माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दे दूं कि वहां पर जमीन उपलब्ध है और वह इतना जर्जर है कि कभी भी आये दिन दुर्घटना हो सकती है । चुनाव के समय में माननीय केन्द्रीय मंत्री जी को भी जनता वहां ले गयी थी और पूरा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है । अगर माननीय मंत्री महोदय जो जांच टीम भेजते हैं तो मैं उनके साथ जाकर के बता भी सकती हूं कि जमीन उपलब्ध है । मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय कि आपने कहा कि डंगरा का पुराना भवन है, वास्तव में वह भी जर्जर है और आपके जो काम करने वाले डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं नियमित वहां काम करती हैं और अच्छी सेवाएं दे रही हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं लेकिन दोनों जगह भवन की बहुत आवश्यकता है कभी भी आये दिन दुर्घटना हो सकती है । इसे तत्काल बनाने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि शिवगंज बाजार के भवन निर्माण की जो बात है वहां जमीन की उपलब्धता नहीं है और उसके संदर्भ में जिला समहर्ता को हमने पत्र भी लिखा है । माननीय सदस्या के पास यदि स्वास्थ्य विभाग की भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, किसी सरकारी जमीन पर जाकर स्वास्थ्य विभाग अस्पताल नहीं बना सकता है तो यदि स्वास्थ्य विभाग के नाम से वह भूमि है तो उसका कोई कागज, रसीद मुझे माननीय सदस्या उपलब्ध करवा दें तो मैं विभाग को निर्देशित करके वहां निर्माण के कार्य के संदर्भ में आदेशित कर दूंगा । दूसरा जो डंगरा का भवन बनाना है मोहनपुर प्रखंड का, वह हमने स्वीकार किया है, उसका भवन हमको बनाना है और उसको अगले वित्तीय वर्ष में मैं बनवा दूंगा ।

अध्यक्ष : श्री राकेश रंजन ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन होनी चाहिए तो क्या जो बिल्डिंग जर्जर हो गयी है वह स्वास्थ्य विभाग की नहीं है । अगर नहीं है तो बिहार सरकार की जमीन वहां पर उपलब्ध है, बिहार सरकार तो जमीन दे ही सकती है ऐसा थोड़े है कि दूसरे का काम के लिए जमीन चाहिए, समाज के काम के लिए तो बिहार सरकार की 1 एकड़ जमीन है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं विनम्र आग्रह के

साथ कहना चाहती हूं कि अगले वित्तीय वर्ष तक वह बना दें, अगर नहीं बनायेंगे तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ऊपर से जो प्लास्टर है सब गिर रहा है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको आप दिखवा लीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हमें आश्वासन दे दें ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, इस संदर्भ में विभाग ने पिछले वर्ष भी जिला समाहर्ता को 19 मार्च, 2025 को पत्र लिखा था और जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है, फिर पुनः स्मारित किया है हमने 18 फरवरी को तो हम तो चाह रहे हैं कि जमीन मिल जाए और निश्चित रूप से सरकार की जमीन का उपयोग जनता की सेवा में हो यह तो हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसकी एक विहित प्रक्रिया होती है महोदय और उस प्रक्रिया के अनुपालन में माननीय सदस्या का भी सहयोग मुझे मिले, मैं भी उसमें मदद करके जमीन हस्तांतरित कराकर के अस्पताल बनाने में सहयोग करूंगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1710, श्री राम चन्द्र सदा (क्षेत्र सं0–148, अलौली (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के पंचायत दहमा खैरी खुटहा एवं चेराखेरा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र–सह–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के नये भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है। साथ ही आनंदपुर मारन पंचायत के ग्राम मारणडीह में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन है।

उल्लेखनीय है कि रेफरल अस्पताल के समतुल्य 30 भाय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य रूप से प्रखंड स्तर पर ही प्रावधानित है। प्रश्न में वर्णित पंचायत आनंदपुर मारन से लगभग 08 कि0मी0 की दूरी पर प्रखंडस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली संचालित है, जहाँ ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, प्रसव सेवा, पैथोलॉजिकल जाँच, टीकाकरण आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं।

उक्त के आलोक में आनंदपुर मारन पंचायत के ग्राम मारणडीह में अलग से रेफरल अस्पताल की स्थापना किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

श्री राम चन्द्र सदा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन हमारी जो चिंता थी कि खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत को कोसी दियरा क्षेत्र में पाये जाने वाले चार पंचायत दहमा खैरी खुटहा, आनंदपुर मारन, चेराखेरा तो ये कई नदियों से घिरे होने के कारण महोदय, लोगों को समय पर स्वास्थ्य की जांच नहीं हो पाती है, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं,

पी0एच0सी0 नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उन कोसी क्षेत्र में लोगों की जो चिंता है वहां के लोगों की एक सी0एच0सी0 अस्पताल हो जाए और वहां प्रसव और रोगियों के लिए एक एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर बैठे और उस इलाके के रोगियों को देखे, यह हमारी वहां के लिए चिंता थी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में उन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की चर्चा की है जिसका प्रश्न में उल्लेख है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के पंचायत दहमा खैरी खुटहा एवं चेराखेरा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र–सह–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के नये भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है तो दो जगहों पर नया भवन बनाकर वहां स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं । साथ ही, आनंदपुर मारन पंचायत के ग्राम मारणडीह में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन है, मतलब तीसरी जगह भी हम बनाने की प्रक्रिया में है । उसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का जो आग्रह है कि उस पंचायत के अस्पताल को जो आनंदपुर मारन में है उसको रेफरल अस्पताल बना दिया जाए, मतलब 30 बेड का अस्पताल बना दिया जाए तो महोदय, ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी पंचायत में अस्पताल को 30 बेड के अस्पताल में हम उत्क्रमित करें, 30 बेड के अस्पताल की सुविधा प्रखंड स्तर पर प्रावधानित है इसलिए यह नहीं कर पायेंगे हम ।

अध्यक्ष : श्री कलाधर प्रसाद मंडल ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश रंजन जी का प्रश्न छूट गया है ।

श्री राम चन्द्र सदा : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इन्होंने जो कहा चेराखेरा पंचायत में रेफरल हॉस्पिटल है उसमें हमलोग जाते हैं तो शिकायतें मिलती हैं कि डॉक्टर यहां आते ही नहीं हैं । चूंकि वह नदियों से घिरा हुआ है, वहां आवागमन की सुविधा सुविधाजनक नहीं है महोदय, इसलिए वहां डॉक्टर जाते ही नहीं हैं तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहां पर जो पदस्थापित डॉक्टर हैं वे नियमित रूप से जाएं ।

अध्यक्ष : श्री राकेश रंजन ।

टर्न–06 / सुरज / 20.02.2026

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, वहां पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र है और स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का प्रावधान नहीं होता है, वहां सी0एच0ओ0 होते हैं, वहां नर्सेज होती हैं और जो वर्णित पंचायत है, उसके बगल में आठ किलोमीटर की दूरी पर सी0एच0सी0, अलौली संचालित है ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1709, श्री राकेश रंजन (क्षेत्र सं॰–198, शाहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहिया में 01 फिजिशियन (विशेषज्ञ), 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 दन्त चिकित्सक, 01 आयुष चिकित्सक, 05 जी०एन०एम, 39 ए०एन०एम०, 03 लैब टेक्नीशियन , 01 एक्स–रे टेक्नीशियन, 01 फार्मासिस्ट एवं 01 नेत्र सहायक वर्त्तमान में पदस्थापित है जिनके द्वारा मरीजों को 24x7 सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में विभागीय अधिसूचना संख्या–249(2), दिनांक–06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) का पदस्थापन किया गया है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री राकेश रंजन : जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । मेरा कहना है कि जो उत्तर मिला है उससे हम काफी हद तक संतुष्ट हैं । लेकिन जब भी बिहिया और शाहपरु, सी0एच0सी0 में फोन किया जाता है, किसी समस्या को लेकर वहां पर डॉक्टरों का यही कहना रहता है कि जितने भी स्टाफ यहां मौजूद हैं, वह पूरे नहीं हैं, कृपया आपलोग वहां पर विभाग से संपर्क कीजिये । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी डॉक्टर की वहां ड्यूटी है, कम से कम वह समय से वहां उपलब्ध रहे । कल भी मैंने इस संदर्भ में एक समस्या को लेकर वहां फोन किया था तो वहां के जो प्रभारी हैं वह बोलते हैं कि हम हैं, लेकिन जब पेशेंट गया तो वह वहां पर पाये नहीं गये । बाद में जब मैंने सिविल सर्जन से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि हां वह डॉक्टर वहां पर रहते नहीं हैं, जिसको लेकर काफी परेशानियां होती हैं वहां के मरीजों को । इस संदर्भ में मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक बार इसकी जांच करायी जाए ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि बिहिया में एक फिजिशियन हैं, जो विशेषज्ञ हैं, तीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, एक दंत चिकित्सक हैं और अभी जैसा मैंने कहा कि हाल में चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है तो 06 फरवरी को एक जेनरल सर्जन का वहां पर पदस्थापना हुआ है और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी पदस्थापना वहां अभी 06 फरवरी को किया गया है, इसके अतिरिक्त भी पद खाली हैं । सृजित जो पद हैं उसके अगेंस्ट खाली है जगह । मैं माननीय सदस्य को जरूर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप युवा हैं, मेहनती हैं और आप क्षेत्र में काम करते हैं । सरकार पूरा सहयोग करेगी और जो रिक्त जगह है वहां पर, उपलब्धता के आधार पर हम पदस्थापना भी करेंगे और जो शिकायत आपने की है, मैं उसकी जांच करा

लेता हूं । जो चिकित्सक वहां नियुक्त हैं वह पिछले तीन महीने में कितने लोगों को ओ0पी0डी0 की सेवा उन्होंने दी है, आई0पी0डी0 की सेवा दी है । उसकी समीक्षा के आधार पर यदि कमी दिखाई पड़ेगी तो उन लोगों पर कार्रवाई भी करवाऊंगा ।

तारांकित प्रश्न सं०–1711, श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र सं०–60, रूपौली)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रूपौली प्रखंड के अंतर्गत डोभा मिलिक पंचायत में 3.5 कि०मी० 11 के0वी0 लाईन, 21 ट्रांसफार्मर तथा 8.5 कि०मी० एल०टी० लाईन का निर्माण करते हुए 70 कृषि विद्युत संबंध प्रदान किये गये है।

साथ ही रूपौली प्रखंड के ही रामपुर परिहट पंचायत में 3 कि0मी0 11 के0वी0 लाईन, 19 ट्रांसफार्मर तथा 4 कि०मी० एल०टी० लाईन का निर्माण करते हुए 62 कृषि विद्युत संबंध प्रदान किये गये है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज–II के तहत आवश्यकता अनुसार विद्युत संरचना का निर्माण करते हुए इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत संबंध देने का कार्य प्रगति पर है।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे मिला है लेकिन उत्तर में दिया गया है कि विद्युत का काम आपके रूपौली प्रखंड में हो चुका है । लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं । बार–बार जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो किसानों का हल्ला होता है कि बिजली के ऑफिस में जाता हूं तो उनका कहना होता है कि वह क्षेत्र में हैं और क्षेत्र से हल्ला होता है कि कभी यहां देखने नहीं आते हैं। साल भर, छः महीना, आठ महीना से लोग कंज्यूमर बनकर टहल रहा है लेकिन उसको बिजली और तार पोल का मुहैया नहीं कराया जा रहा है । अतः मांग करता हूं कि इसे ससमय पूरा कराने की कृपा करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सीनियर ऑफिसर को भेजकर इस काम को जल्द ही करवा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं०–1712, सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र सं०–81, अलीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के घन श्यामपुर प्रखंड अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कोर्थू संचालित है, जिसका भवन मरम्मति योग्य है एवं इस हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को निदेशित किया गया है। यहाँ पदस्थापित 02 ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य सेवायें दी जा रही है।

साथ ही कोर्थू पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोर्थू भी स्वीकृत है, किन्तु भवन के अभाव में संचालित नहीं है। इसके भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, दरभंगा से पत्रांक–409(10) दिनांक–18–02–2026 द्वारा अनुरोध किया किया है। भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रियानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोर्थू के लिये जो भी सकारात्मक उत्तर दिये गये हैं, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूं । एक छोटा सा निवेदन है कि वहां पर एक एम0बी0बी0एस डॉक्टर, क्योंकि 40 हजार लोगों की आबादी उस पर निर्भर करती है और दूसरा एक घनश्यामपुर, स्वास्थ्य केन्द्र है जिसके लिये मैंने प्रश्न भी डाला हुआ है कि वहां पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उसको ध्यान में रखते हुये डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, यह मेरी माननीय मंत्री जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या को मैं बताना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र होता है वहां पर चिकित्सक के पदस्थापना का प्रावधान नहीं होता है, वहां नर्सेज के द्वारा ही सुविधाएं दी जाती हैं और वहीं पर कोर्थू पंचायत में ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोर्थू भी स्वीकृत है । मैं माननीय सदस्या के प्रश्न के आलोक में वहां जो करवाने जा रहा हूं वह यह है कि कोर्थू में जहां ए0पी0एच0सी0 में चिकित्सक देने का प्रावधान होता है तो ए0पी0एच0सी0, कोर्थू के अंदर उसका नया भवन बनाया जाए, उसके लिये हमने वहां समाहर्त्ता को पत्र दिया है कि भूमि उपलब्ध कराएं ताकि भूमि उपलब्ध हो जाए और वहां हम ए0पी0एच0सी0 बना देंगे तो जो माननीय सदस्या की चिंता है कि वहां चिकित्सक उस पंचायत के अंदर रहकर लोगों की सेवा करें, वह कर पायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतेश कुमार सिंह ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मेरा कोई पूरक नहीं, सवाल नहीं । उपकेन्द्र में किस–किस लेवल के डॉक्टर रहेंगे ? पी0एच0सी0 में कौन रहेगा ? हमलोग भी इस समस्या को झेलते हैं । सरकार ने बहुत काम किया है । हर पंचायत तक स्वास्थ्य उप केन्द्र पहुंच गया है तो लोग वहां एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर चाहते हैं कि डॉक्टर नहीं हैं और हमलोगों को भी घेरकर इसकी शिकायत करते रहते हैं । तो एक जरा किसके लिये क्या मानव बल या डॉक्टर बनाया गया है कि इस लेवल के अस्पताल में एम0बी0बी0एस0 रहेंगे, इस लेवल में नर्स संभालेगी । इस प्रकार का विभाग में अगर कोई अधिसूचना जारी हुई है या कोई लिस्ट है तो सभी माननीय विधायक को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि हमलोग भी उस बात को रख सकें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उपलब्ध करवा दीजियेगा ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, बहुत अच्छा विषय लाया है जिवेश जी ने । हर स्तर पर कितना मानव बल रहेगा, कितनी संख्या रहेगी और उनकी विशेषज्ञता रहेगी या सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी रहेंगे, वह सब वर्णित है विभाग में । मैं सभी माननीय सदस्यों को वह उपलब्ध करवा दूंगा और स्वास्थ्य उपकेन्द्र में नर्स और सी0एच0ओ0 का ही प्रावधान है । उसके ऊपर जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है वहां से चिकित्सकों के द्वारा सेवा देने की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है और उससे आगे जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल हॉस्पीटल, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल । जो अस्पताल का ग्रेड जैसे ही ऊपर होता है, वहां वैसे ही चिकित्सकों की भी संख्या बढ़ती है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ती है । वह पूरा जो प्रावधानित है, मैं सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट करवा देता हूं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1713, श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–58, कसबा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर एवं जलालगढ़ में सामान्य प्रसव (Normal Delivery) की सुविधा उपलब्ध है । प्रसव डिलेवरी के दौरान जटिलताओं जैसे अत्यधिक रक्त स्राव, आपातकालीन शल्य चिकित्सा आदि से निपटने हेतु नजदीकी उच्चतर संस्थान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया रेफर किया जाता है । इस हेतु मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल में आई0सी0यू0 की व्यवस्था नहीं है। इसी आलोक में यह व्यवस्था पूर्णिया जिला अन्तर्गत कस्बा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ एवं श्रीनगर प्रखडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में भी नहीं है। IPHS मानको में प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य क्रेन्द्रों में आई0सी0यू0 का होना आवश्यक नहीं है ।

राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित किये जाने हेतु विभागीय राज्यादेश सं0–550 (10), दिनांक– 11.04.2025 द्वारा मानक के अनुरूप पदसृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

श्री नितेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से आशावादी हूं । पर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर से हमारे कसबा विधान सभा में नार्मल डिलिवरी के लिये तीनों प्रखंडों से करीब 12 हजार केस आए लास्ट ईयर । जिसमें से 10

परसेंट जो कम्लीकेसन्स हुये एक्सेस ब्लीडिंग के लिये रेफर किया गया । अब जलालगढ़ और श्रीनगर प्रखंड से जब रेफर किया जाता है और सदर अस्पताल पहुंचने में एक से दो घंटे मिनिमम टाइम चला जाता है क्योंकि ट्रैफिक भी है और डिस्टेंस भी है । ऐसे सिचुएशन्स में पेशेंट के लिये वह गोल्डन ऑवर होता है । वहां रेफर करने के बाद फिर बाद में उसको हायर रेफर के लिये भेज दिया जाता है । 90 परसेंट सरकार ने तो अच्छे काम किये हैं, उसके लिये सरकार को धन्यवाद । ऐसे 10 परसेंट क्रिटिकल केसेज के लिये हर प्रखंड में आई0सी0यू0 केयर, मैं समझता हूं कि यह डिफिकल्ट होगा अभी । कम से कम विधान सभा में सेंटर ऐसे प्वाइंट में आई0सी0यू0 एंड क्रिटिकल केयर का एक यूनिट क्रियेट किया जाए ताकि इवेन इमरजेंसी में भी अगर देखेंगे, हमारे यहां तकरीबन 25 हजार पेशेंट आए हैं लास्ट ईयर और एक रिक्वेस्ट माननीय मंत्री जी से है कि हमारे यहां मेडिकल कॉलेज जो बनकर तैयार है, आशिंक रूप से हैंडओवर हुआ है । पिछले एक साल से वह हैंडओवर नहीं हो रहा है । कांट्रैक्टर का कुछ इशूज है, इनको सॉल्भ करें, यह मेरा रिक्वेस्ट है ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, जवाब में अंकित है कि आई0पी0एच0एस0 के मानकों में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में आई0सी0यू0 का सुविधा होना आवश्यक नहीं है और हम सब लोग राज्य के अंदर में आई0सी0यू0 की जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वह जिला और उसके ऊपर स्तर के अस्पताल में कराते हैं । जिस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है कि ऐसे जब क्रिटिकल केसेज हो जाते हैं तो वैसे क्रिटिकल केसेज को बचाने के लिये कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाए । इसी को ध्यान में रखकर विभाग ने सभी प्रखंडों में अल्सा एंबुलेंस की व्यवस्था की है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंबुलेंस और बिहार पूरे देश में गिने हुये चार, पांच राज्यों में से एक है जिसके सभी प्रखंडों में कम से कम एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंबुलेंस है और यह वैसे ही मरीजों को प्राथमिकता पर प्रावधानित किया जाता है कि वह हायर सेंटर में मरीजों को लेकर जाए ।

श्री नितेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा था, उन पर अगर माननीय मंत्री जी कुछ बता सकें ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, वह काम चल रहा है, उसको हम दिखवा लेते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–1714, श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र सं०–152, बिहपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के बिहपुर विधानसभा अन्तर्गत बिहपुर, नारायणपुर एवं खरीक प्रखंड में कृषि कार्य हेतु RDSS परियोजना के फीडर पृथक्करण अवयव के अन्तर्गत फीडर पृथ्क्करण का कार्य एवं संबंधित विद्युत संरचना निर्माण का कार्य किया

जा रहा है साथ ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज–2 के अन्तर्गत इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने एवं आवश्यक विद्युत संरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्त बिहपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत तीनों प्रखंड में अब तक दो अदद् फीडर पृथ्क्करण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष एक अदद् फीडर पृथ्क्करण का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2026 है । साथ ही, उपर्युक्त विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडो से कृषि विद्युत संबंध हेतु कुल 1655 अदद् आवेदन प्राप्त हुए है जिसके विरूद्ध 1444 अदद् कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिये गये है शेष 211 अदद् कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य मार्च 2026 है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और विभाग ने बहुत ही गोलमटोल उत्तर दे दिया है...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैंने तो स्पष्ट पूछा है, मेरा क्षेत्र बहुत ही वैसे तो कृषि प्रधान...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के कारण कुछ दिक्कतें हुईं, जल्द ही इसको करा दिया जायेगा, मार्च तक ।

टर्न–7 / अभिनीत / 20.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स0वि0स0, श्री गौतम कृष्ण, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, बिहार समेत देशभर के विश्विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं । 2016 में हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई की मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी, 2023 में आई.आई.टी. बाम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी आदि की सांस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव

और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । यू0जी0सी0 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गयी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसके आलोक में जनवरी, 2026 में यू0जी0सी0 द्वारा इक्विटी गाईडलाइंस की घोषणा की गयी लेकिन इस गाईडलाईन को मजबूती से लागू करवाने के बजाय xxx मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया । हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है ।

विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यू0जी0सी0 गाईडलाईन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे ।

अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यू0जी0सी0 इक्विटी गाईडलाईन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं।

अध्यक्ष : xxx – इस शब्द को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । प्रोसीडिंग्स से xxx शब्द हटा दिया जाय । बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हमने कहा है । एक मिनट, एक मिनट । हमने आसन से कहा है कि प्रोसीडिंग्स से xxx शब्द हटाया जाय । बैठिए । हमने आदेश दे दिया है । हमने कहा है कि प्रोसीडिंग्स से xxx शब्द हटाया जाय ।

माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय, इस तरह की भावना..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । सरकार का उत्तर हो रहा है । बैठ जाइये, उन्होंने गलत कहा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं माननीय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : xxx शब्द हटेगा प्रोसीडिंग्स से, हटा दीजिए । चलिए, बोलिए । जाति सूचक बात नहीं आयेगी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि संविधान में विश्वास है..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए । प्लीज बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्था का अगर सम्मान करते हैं तो इस तरह की भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये प्लीज । शांति–शांति । सुनिए । सरकार को सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : क्योंकि आज किसी की भी मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राज्य की क्षति होती है । हर समाज का सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं वे संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर इस संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले, मानसिकता साफ झलकती है महोदय । हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठिए । बैठिए आप ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ये समाज के अंदर जहर घोलने वाले लोग हैं । महोदय, आज मेरे देश को कमजोर करने में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : संदीप जी, आप बैठिए । सबलोग बैठ जाइये । सरकार के द्वारा बातों को रखा जा रहा है, सुनिए ध्यान से ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : समाज के प्रति जो जहर घोलते हैं वे राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं । यह कोई समस्या है ? हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था । महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी ? मैं भी तो XXX समाज से आता हूं । महोदय, इसी मुजफ्फरपुर में रैगिंग करायी गयी, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया । मैं भी तो xxx समाज से हूं । इस मानसिकता पर प्रश्न उठना चाहिए लेकिन जातिगत भेदभाव से, ये बाबा भीमराव अम्बेदकर की जातिविहीन समाज के सपने को तार–तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं । ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं । ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विजय बाबू । प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रस्ताव रखिए । प्रस्ताव आपका है, रखिए । पढ़िए, सुनिए मत ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिए जायेंगे । शून्यकाल लिए जायेंगे ।

शून्यकाल

माननीय सदस्य श्री शंकर प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

बातें आ गयीं । बातें आ गयीं ।

माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अभिषेक रंजन ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्या श्रीमती बिनिता मेहता । माननीय सदस्य, बात आ गयी, प्लीज बैठ जाइये । आलोक बाबू, हमने साफ कहा, कोई बहस का विषय नहीं है । हमने साफ कहा है कि प्रोसीडिंग्स से XXX शब्द हटेगा । बात खत्म हो गयी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बिनिता मेहता । पढ़िए । क्यों खड़े हो रहे हैं आप ? पहले आप बैठिए ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, गोविन्दपुर प्रखण्ड के सकरी नदी में घाट नं॰–01 पर संवेदक के द्वारा खनन नियमों के खिलाफ अवैध तरीके से बालू की निकासी की जा रही है ।

अतः सरकार से मांग करती हूँ कि नियमानुसार सीमांकन तय करते हुए बालू का उठाव हो ।

अध्यक्ष : बोलिए, आलोक बाबू ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य ने किसी जाति का नाम नहीं लिया उन्होंने XXX ...

(व्यवधान)

शांत रहिए । पहले सुन लीजिए पूरी बात । XXX कहा गया । XXX कोई जाति नहीं है और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है । किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है । इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके ऐसा लगता है कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका' है । जो लोग गलत किये हैं उनलोगों को तीखा लग जा रहा है, मिर्ची लग जा रही है महोदय । इसीलिए सदन में इस तरह

की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं और इसलिए इस तरह की बातों का उपयोग करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी, बोलिए ।

(व्यवधान)

अब पढ़वा दिए । अब आप बैठिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ये जितने बैठे हैं न विपक्ष में कोई xxx समझते नहीं हैं लेकिन इनलोगों को xxx से इतनी तकलीफ है...

(व्यवधान)

सुनिए पहले । सुनिए पहले । मैं बताता हूं आपको । मैं बताता हूं सुनिए । अध्यक्ष महोदय, जिस xxx ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोल लिए न । आप बोल लिए न । आपने अपनी बातों को रख दिया, अब बैठ जाइये । सुनिए उनकी बातों को भी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जिस xxx के पॉव पखारने, तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब xxx के पॉव अपने आंसूओं से धोते हैं, जिस xxx के बिना न शादी होती है, न श्राद्ध होता है, जिस xxx ने...

(व्यवधान)

सुनिए, जिस xxx ने...

अध्यक्ष : आलोक जी, आपकी बातों को सुना गया । उनको हमने मौका दिया है । हमने मौका दिया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : जिस xxx ने भिक्षा मांगकर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय बना दिया । जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं । अध्यक्ष महोदय, इनको xxx खराब लगता है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण । गौतम जी, पढ़िए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब बैठ जाइये । सारी बातें आ गयीं । सारी बातें आ गयीं, बैठिए । हमने साफ कर दिया है । प्रोसीडिंग्स से xxx शब्द हटाया गया । आगे बढ़िए । गौतम कृष्ण जी ।

.....

xxx- आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।

.....

टर्न–8 / धिरेन्द्र / 20.02.2026

श्री गौतम कृष्ण : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली बरूना ब्रिज से समस्तीपुर–रोसड़ा होते हुए घनश्यामपुर रसियारी तक बन रही सड़क को पश्चिमी कोसी बांध, बकुनिया, हाटी, आसेय, कोसी नदी क्लोजर, नौहट्टा, बिहरा, साहुगढ़ (गोढ़ियारी) होते हुए कॉलेज चौक, मधेपुरा तक विस्तार कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा एक नंबर पर शून्यकाल था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका किस नाम से था ?

श्री शंकर प्रसाद : महोदय, शंकर प्रसाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 76 शब्द में शून्यकाल दिये हैं, 50 शब्द में देना था । आपको पढ़वायेंगे ।

श्री शंकर प्रसाद : महोदय, ठीक है ।

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड स्थित बुनियादी विद्यालय, पाटबंधी की भूमि पर बाउंड्री वॉल के अभाव में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ।

अतः विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर बाउंड्री वॉल तथा खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण कराया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शंकर प्रसाद जी, 50 शब्द में शून्यकाल देना होता है, इस बात का ध्यान रखियेगा । अपना शून्यकाल पढ़िये ।

श्री शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत सरैया में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (एस॰डी॰पी॰ओ॰) का अपना कोई निजी सरकारी भवन नहीं है । पिछले 10–12 वर्षों से विभागीय कार्य सरैया स्थित गंडक प्रोजेक्ट के अतिथि गृह में संचालित किया जा रहा है । अतिथि गृह में कार्यालय चलने के कारण आम जनता को अपने कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाई और असुविधा होती है ।

अतः पुलिस अनुमंडल कार्यालय, सरैया के लिए अविलंब एक सरकारी भवन निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अंतर्गत रायवारी महुआवा–महुई ग्राम के बीच मसान नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बताइये, आप क्या कह रही हैं ?

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल में बरहनपुर, यहां सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस जो है, वह कचरा से भरा हुआ है, वहां पर डॉक्टरों को बहुत परेशानी होती है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप लिख कर दे दीजिये ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, उसमें पब्लिक शौचालय बना दिया है तो डॉक्टरों को बहुत परेशानी होती है । महोदय, एक और मामला है, कादिरगंज आंटी स्कूल में सरकारी गाड़ी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप लिखित माननीय मंत्री जी को दे दीजिये, हो जायेगा ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, उसको हटा दिया जाय । हम स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उदय कुमार सिंह ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत शेरघाटी प्रखंड पंचायत कचौड़ी के ग्राम फजलाहा मेन सड़क से गांव होते हुए डोभी जाने वाली मेन रोड तक कच्ची रोड है, जिससे सभी ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः जनहित में उक्त सड़क के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला अन्तर्गत टिकारी प्रखंड के ग्राम सीमुआरा में स्थित ग्राम निर्माण मंडल, खादी ग्रामोद्योग समिति केन्द्र, टिकारी (कताई केन्द्र) जून, 2022 से बंद पड़ा हुआ है । इस केन्द्र के बंद होने के कारण लगभग 100 महिलाओं का रोजगार समाप्त हो गया है ।

अतः मैं मांग करता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग समिति केन्द्र पुनः चालू किया जाय ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, पचाढ़ी के छात्र जतिन गौतम की हत्या दिनांक–08.07.2025 जो रैयाम थाना काण्ड संख्या–47/2025 में दर्ज है, घटना के 06 महीना बित जाने के बाद भी आरोपी कानून के गिरफ्त से बाहर है । सदन के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुरारी मोहन झा जी, आप बैठिये ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नवादा में प्राथमिक विद्यालय, निर्मलविगहा से 02 किलोमीटर दूर मध्य विद्यालय, बरावा में चलती है। निर्मलविगहा के खाता–943, खेसरा–5143, अराजी–1.33 एकड़ जमीन उपलब्ध है ।

अतः उक्त विद्यालय को तत्काल सामुदायिक भवन निर्मलविगहा में संचालित करवाने एवं भवन निर्माण करवाने की मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको सूचित करना है कि सदन की कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से शून्यकाल की सूचनाएं अब ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। यह नई व्यवस्था सोमवार दिनांक–23 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।

उक्त तिथि से सभी माननीय सदस्य शून्यकाल की सूचना निर्धारित समय–सीमा के भीतर विधान सभा की अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल नेवा के माध्यम से ही प्रेषित करेंगे ।

इसमें नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । शून्यकाल की सूचना के संदर्भ में नियमावली के नियम पूर्ववत ही हैं । सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है ।

महत्वपूर्ण यह है कि सदन की बैठक की निर्धारित तिथि को ही शून्यकाल की सूचना ली जाएंगी । ऑफलाइन अथवा हस्तलिखित एवं भौतिक रूप में दी गई सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी । सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम यानी नेवा के माध्यम से ही ली जाएंगी । सूचनाएं यूनिकोड फॉन्ट में टंकित होनी चाहिए। 50 (पचास) शब्दों की शब्द सीमा में होनी चाहिए ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल वह अवधि है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद और सूचीबद्ध कार्य शुरू होने से पहले होती है ।

यह दोपहर 12 बजे आरंभ होती है–इसलिए इसे ''शून्यकाल'' कहा जाता है ।

इसमें जनहित के तात्कालिक और अति लोकमहत्व के विषयों को उठाना चाहिए । जिन पर तुरंत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो। इसमें यह अवश्य ध्यान रखें कि जो विषय प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका की सूचनाओं में पूछे गए हों वे शून्यकाल में न पूछे जाएं ।

आपकी शून्यकाल की सूचना के लिए सभा की निर्धारित तिथि को ठीक 09 (नौ) बजे नेवा पोर्टल खुलेगा । यह 10 (दस) बजे तक खुला रहेगा । इसमें क्रम भी स्वतः निर्धारित होता जाएगा । आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु विधान सभा सचिवालय के नेवा सेवा केन्द्र की सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं । साथ ही, अब आपको न तो सुबह–सुबह और न ही 09 (नौ) बजे सुबह सचिवालय आना पड़ेगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इस नई प्रणाली को अपना कर सदन की कार्यकुशलता में सहयोग प्रदान करेंगे ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री देवी ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या है ?

श्री जिवेश कुमार : महोदय, यह पूरा सदन आसन को बधाई देता है कि आपने इस काम को, सब कुछ ऑनलाइन था एक शून्यकाल ही बचा था तो आपने इसको कर दिया । इसके लिए पूरे सदन की ओर से आसन को बहुत–बहुत बधाई ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलांतर्गत चकाई प्रखण्ड में निर्माणाधीन ग्रामीण पथों के पक्कीकरण भलुआ से पहड़िया, माधोपुर से कांसराइडी, परतापपुर से बाबूलाल के घर तक तथा पेटार पहाड़ी से चड़री एवं सोना प्रखण्ड के बन्दर मारा से भेलुआ विशुनपुरा से भलशुकिया आदि के कार्य घटिया किस्म के सामग्री एवं मानक के विपरीत किया गया है । संवेदक एवं अभियंता पर कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करती हूँ ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रभुनाथनगर, उमानगर, शक्तिनगर, दहियावांटोला और टांडी में अत्यधिक वर्षा के कारण गंभीर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे लोग घरों में फंसे रहते हैं और आवागमन बाधित हो जाता है ।

अतः सड़क, नाला निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था वर्षा से पहले सुनिश्चित करने की मांग करती हूँ ।

श्री राम चन्द्र सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधान सभा में अम्बा ईचरूआ पंचायत के ईचरूआ में मृत बागमती नदी पर आर॰सी॰सी॰ पुल बनवाना बहुत जरूरी है जो जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है । इसलिए इस पुल को जल्द बनवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी अंचल अंतर्गत मंगलपुर वितरणी पर दर्जनों संकीर्ण पुल नहर निर्माण के समय से ही निर्मित है । जिनमें चौड़ाई की कमी होने से पुल की दीवार हमेशा क्षतिग्रस्त रहती है । जानमाल का खतरा बना रहता है ।

मैं सदन के माध्यम से तमाम पुलों के चौड़ीकरण की मांग करता हूँ ।

श्री प्रो॰ नगेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जनकपुर रोड नगर परिषद से एस॰एच॰–52 एवं एस॰एच॰–87 पर भारी वाहन के आवागमन से जाम एवं दुर्घटनाएं होते रही हैं मैं उक्त जनकपुर रोड नगर परिषद अंतर्गत नये बाईपास सड़क की प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

टर्न–9 / अंजली / 20.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर तथा सदन की सहमति हो, तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जाएंगी । माननीय सदस्या, सुश्री मैथिली ठाकुर जी की सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री जी का जवाब होगा ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथ उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सुश्री मैथिली ठाकुर, श्री आनन्द मिश्र एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अर्जुन एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है जिसकी छाल का आयुर्वेदिक एवं आधुनिक औषधि पद्धतियों में हृदय रोगों सहित विभिन्न व्याधियों के उपचार में व्यापक उपयोग होता है । विशेषकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं औषधीय संसाधन के रूप में है । बिहार राज्य औषधीय पादप बोर्ड राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्द्धन, वैज्ञानिक, कटाई, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित है । अर्जुन छाल के संबंध में यह भी दृष्टिपथ में रखना आवश्यक होगा कि इसके दोहन में जैव विविधता संरक्षण वन अधिनियमों तथा वैज्ञानिक मानकों का पूर्णतः पालन हो । इस संबंध में आवश्यकतानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर, व्यावहारिक एवं विधि सम्मत कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि रोजगार सृजन के साथ–साथ राज्य में हर्बल मेडिसीन के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके । मैं माननीय सदस्या को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा मैंने जवाब में बोला है, तीनों विभाग के साथ को–ऑर्डिनेशन करके अर्जुन पौधे का जो छाल है, उसका सदुपयोग भी हो और उससे उत्तर बिहार के किसानों को आर्थिक संवर्द्धन भी हो, आर्थिक लाभ भी हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कुछ बोलना है क्या ?

सुश्री मैथिली ठाकुर : जी महोदय ।

अध्यक्ष : बोल लीजिए ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आपने इसके ऊपर विचार किया और मैं बस यह रिक्वेस्ट करूंगी कि अलीनगर विधान सभा से इसकी शुरुआत हो और मैं खुद बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड हूं कि यह काम शुरू हो जाए और रोजगार में वृद्धि हो और युवा जो राह भटक रहे हैं, उनको काम करने के लिए मिले ताकि वे सभी लोग व्यस्त होकर काम में लग जाएं और इससे बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ॰ सुनील कुमार ।

डॉ॰ सुनील कुमार, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अड़तालीस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

————————————

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जर्जर विद्यालयों का भवन निर्माण, अतिरिक्त कमरा का निर्माण तथा छात्र–छात्राओं की ज्यादा उपस्थिति के कारण कमरा बनाने एवं जीर्णोद्धार या मरम्मती आदि के लिए अच्छी खासी शिक्षा विभाग से प्रत्येक जिला में राशि आवंटित की जाती है, परंतु प्रधानाध्यापक एवं

जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिली–भगत के कारण मनमाने ढंग से कार्य कराया जा रहा है । जहाँ जर्जर विद्यालय के नवनिर्माण की जरूरत है, वहाँ पूर राशि खर्च नहीं की जाती है और जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ प्रभावित होने के कारण राशि खर्च कर दी जाती है । लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है और जनता के प्रति जवाबदेह है ।

अतः शिक्षा विभाग से स्वीकृत राशि को विधायकगण की अनुशंसा पर विद्यालयों में कार्य कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, अररिया में भी इसी तरह का मामला है ।

अध्यक्ष : आ गई बात । सरकार का उत्तर सुन लीजिए ।

श्री आबिदुर रहमान : यह पूरे बिहार में है ।

अध्यक्ष : पूरे बिहार की बात उन्होंने की है । डॉ॰ सुनील कुमार जी ने पूरे बिहार की बात की है । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : पहले सुनिएगा तब न कि बिना सुने हुए...

अध्यक्ष : पहले सरकार का उत्तर सुन लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित सरकारी विद्यालयों का मुख्यालय सहित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुश्रवण किए जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । छात्र–छात्राओं के साथ–साथ, शिक्षक, अभिभावक के साथ भी, शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार लगातार विद्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों के कारण आमजनों में राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है । जिसकी स्वीकृति माननीय सदस्य के द्वारा भी की गई है । राज्य में जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण, अतिरिक्त कमरों के निर्माण, जीर्णोद्धार या मरम्मती आदि की बात है, इसके लिए विभाग द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 2425 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है । साथ ही, राशि के आलोक में निविदा के माध्यम से संवेदकों का चयन कर विद्यालय के आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है । जहां तक प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत के कारण मनमाने ढंग से कार्य कराने का प्रश्न है, इस संबंध में अंकित करना है कि योजनाओं का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाती है ।

अंकनीय है कि विभाग द्वारा विभिनन अर्द्ध–सरकारी पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, विधान परिषद एवं लोकसभा, राज्यसभा में राज्य के निर्वाचित मनोनीत सदस्यों से उनके क्षेत्राधीन 5 प्राथमिक एवं 5 माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार मरम्मती हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त अनुरोध के उपरांत माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध अनुशंसा, अनुशंसित विद्यालयों की सूची बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जाता है । जिसमें उक्त संस्था के द्वारा कुल 1918 अनुशंसित विद्यालयों में से 488 विद्यालय ऐसे हैं जहां जीर्णोद्धार एवं मरम्मती की आवश्यकता नहीं है । शेष 1430 विद्यालयों के 1386 विद्यालयों में जीर्णोद्धार एवं मरम्मती कार्य किया जा चुका है तथा 44 में कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा । समय–समय पर माननीय सदस्यों के द्वारा विद्यालयों के आधारभूत संरचना से संबंधित अनुशंसा प्राप्त होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ॰ सुनील जी ।

डॉ॰ सुनील कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कराया जाता, तो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे लाने की जरूरत नहीं थी, विधायकों की अनुशंसा को कतई मान्य नहीं होता है । मैं 20 वर्षों से ऊपर से विधायक हूं । रहुई मेरा प्रखंड है, रहुई मुख्यालय में रहुई उच्च विद्यालय में इतनी हालत खराब है कि वहां कि बच्चियों को बेपर्दा होकर शौच जाना पड़ता है । संडे को, रविवार को अपनी राशि से 58 लाख रुपया लगाकर उसकी चहारदीवारी का शुभांरभ करने वाला हूं । अगर सरकार ध्यान देती, अगर शिक्षा विभाग ध्यान देता, तो विधायकों को अपनी राशि नहीं देनी पड़ती । मैं आपको बताना चाहता हूं जवाहर कन्या विद्यालय, बिहार शरीफ में हमारी राशि से वहां कमरे बनाए गए हैं । बड़ी पहाड़ी उच्च विद्यालय, स्मार्ट सिटी अगर नहीं होता तो विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं होता, शिक्षा विभाग जितना जर्जर विद्यालय है उसमें पैसे नहीं देती है, जिन विद्यालयों में साठ–गांठ हो जाता है वहां पैसे देती है ।

(क्रमशः)

टर्न–10 / पुलकित / 20.02.2026

(क्रमशः)

डॉ0 सुनील कुमार : इसलिए हमारा स्पष्ट सरकार से आग्रह हैं कि हम विधायकों की अनुशंसा पर, हमसे ज्यादा जानकार भी कोई नहीं होता है । हम वहां से चुनाव लड़ते हैं, एक–एक विद्यालय की स्थिति को जानते हैं । इसीलिए हम विधायकों की अनुशंसा पर ही विद्यालय में कमरे निर्माण हों, उसकी मरम्मती हो, एजेंसी जो भी हो । एजेंसी से मुझे कोई लेना–देना नहीं है । लेकिन हम विधायकों

की अनुशंसा पर होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, विधायकों की जो मंशा है, आपने देखा होगा इस ध्यानाकर्षण में 50 विधायकों ने सहमति दी है और मुझे लगता है पूरा विधान सभा इस बात से, पूरा सदन इस बात से सहमत है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है । क्या आप लोग सहमत हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारकिशोर जी बोल रहे हैं । सुनिए, सबकी बात सुन ली जाएगी । अनिल जी, आपका भी नम्बर आयेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में दो भवन विहीन विद्यालय का कमरा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अनुशंसा करके बनाया हैं । लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो भवन का निर्माण होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया । इसलिए निश्चित तौर पर पूरे सदन ने, हम सबों ने हस्ताक्षर किया है और माननीय विधायकों से विमर्श करके करना है, कोई हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि हम लोग स्वयं करने वाले हैं । यह सरकार को इस बात से सहमत होना चाहिए । इसके लिए हम सब ध्यानाकृष्ट कर रहे हैं।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2425 करोड़ रुपया इन्होंने 2024–25 में रख–रखाव, उपस्कर, अन्य चीजों पर खर्चा किया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि निविदा के माध्यम से किया गया है । मैं चुनौती देता हूँ मंत्री जी को, इस मामले की जांच करा लें । किसी भी जिले में, कहीं भी अब इधर में जब ये बातें प्रकाश में आई हैं तो कुछ शुभारंभ किया गया है । लेकिन उसके पहले जो भी किया गया वह डी0ई0ओ0, डी0पी0ओ0, स्थापना और कंसर्न इंजीनियर के द्वारा सारी राशि का बंदरबांट किया गया है। मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ माननीय मंत्री महोदय से । क्या एक कमेटी विधान सभा की बनाकर जांच कराने का विचार रखते हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रायः आप भी सहमत होंगे जैसा हम अपने अनुभव से कहें कि जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या कोई अन्य विद्यालयों में राशि खर्च होती है, उसकी विधायकों को जानकारी भी नहीं होती है । किसी विद्यालय की मेरी नजर में क्या प्राथमिकता है, और डी0एम0 की अध्यक्षता में अगर कमिटी है, तो डी0एम0 का फीडबैक मैकेनिज्म भी तो वही है जो हम लोगों की भावना है या तो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति हो जाए या जैसे मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, कहीं ना कहीं विधायक की भूमिका उसके चयन में हो । साथ ही साथ विभाग जो कार्य कर रहा है, उसकी सूचना भी विधायकों को नहीं मिलती है, जानकारी नहीं रहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री की बात सुन लीजिए, अब समय भी हो रहा है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, पूरा सदन चिंतित है और सरकार भी चिंतित है । माननीय सदस्य को स्पष्ट

रूप से उत्तर भी हमने दिया है । महोदय, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटी बनी हुई है, आज ही निर्देश दिया जाएगा जिलाधिकारी को ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिए, प्लीज हल्ला मत कीजिए । सुनिए पूरी बात को ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : प्रमोद जी, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं, आप मंत्री भी रहे हैं। आज ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाएगा कि हर हालत में माननीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देकर भवन निर्माण की कार्रवाई करें । आज ही निर्देश जारी किया जाएगा ।

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है । सदन की सहमति से इन्हें लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है ।

<u>पढ़ीं हुई मानी गयी शेष शून्यकाल की सूचनाएँ</u>

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड मधुबनी, भीतहां, ठकराहां एवं पिपरासी गंडक किनारे स्थित है। जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर इन क्षेत्रों में किसान खेती हेतु नदी नाव से आने–जाने के समय अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं।

मैं सरकार से मधुबनी प्रखंड में अविलंब एस०डी०आर०एफ० टीम की स्थायी तैनाती की मांग करती हूं ।

श्री भरत बिन्द : कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, जबकि जिले के अन्य प्रखंडों के खरवार जाति को यह सुविधा प्राप्त है।

अतः रामपुर प्रखंड के खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर मुशहरनियाँ पंचायत के मुशहरनियाँ गाँव होकर हरदी नदी बहती है। किसानों को सिंचाई के लिए स्लुईस गेट की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से परिहार प्रखंड के मानिकपुर मुशहरनियाँ गाँव में हरदी नदी पर सिंचाई हेतु एक स्लुईस गेट निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री मो० सरवर आलम : किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज और कोचाधामन में फौजी कैंप के लिए गरीब किसानों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है। इससे हजारों परिवारों का चूल्हा बुझ जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि देश की सुरक्षा और किसान की रोटी दोनों का खयाल रखते हुए इस कैंप को किसी गैर–आबादी वाली जमीन पर बनाया जाए।

श्री शुभानंद मुकेश : राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अंगिका भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे अंगिका भाषी क्षेत्रों में इस विषय को पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों का अभाव है।

अतः आगामी टी0आर0ई0–4 में अंगिका शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री रोमित कुमार : राजगीर नेचर सफारी का गेट नं0–2 जेठियन बुद्ध मार्ग पर स्थित है। जेठियन की 300 एकड़ भूमि से सफारी बनी है। सरकार से मांग है कि गेट शीघ्र खोला जाए, जिससे गया, उत्तर बिहार के पर्यटक जाम से बचकर सीधे पहुंचे तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिले।

श्री संदीप सौरभ : राज्य के माध्यमिक, उच्च–माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली नियोजत शिक्षकों के साथ एक ही नियमावली से हुई, और इन्होंने सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके बावजूद घर से 200–400 किमी दूर पदस्थापित पुस्तकालयाध्यक्षों को स्थानांतरण की सुविधा नही दी गई है।

पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानांतरण शुरू करने की मांग करता हूं।

श्री बीरेन्द्र कुमार : रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र के डाकबंगला स्थित विश्वकर्मा चौक से सोनबार चक के मध्य बूढ़ी गंडक पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल बनवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री गुलाम सरवर : पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखण्ड के उप–स्वास्थ केंद्र असजा मोबैय्या का भवन निर्माण आपके कार्यकाल में कराया गया है। उक्त भवन अभी तक हस्तांतरित नहीं हुआ है तथा पूरी तरह जर्जर हो चुका है।

उक्त स्वास्थ्य भवन को ध्वस्त कराकर नया भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्री महेश पासवान : अगिआंव विधान सभा के अंतर्गत गड़हनी प्रखण्ड में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित है। लेकिन वर्षों बाद भी खेल स्टेडियम बना नहीं है। जिसके अभाव में युवाओं की प्रतिभा प्रभावित हो रही है।

अतः बिहार सरकार से जनहित में शीघ्र खेल स्टेडियम निर्माण की मांग करता हूं।

श्री रणविजय साहू : समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का भवन नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित है।

अतः जनहित में शाहपुर पटोरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का भवन निर्माण पटोरी नगर परिषद वार्ड सं०–19 अन्तर्गत अवस्थित कृषि फार्म हाउस के जमीन पर कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड सोनमा पंचायत स्थित 24 एकड़ की भूमि फैले वॉरी चौर तलाब में प्रतिवर्ष भौगोलिक प्रवासी पक्षी यथा लालसर, अधिंगा, साईबेरियन सारस, टिटहरी, गुंजन पक्षी, रोजी पेरिकन आदि का प्रवास रहता है।

अतः उक्त तालाब को जल जीवन हरियाली योजना के तहत पार्क निर्माण के साथ सुसज्जित कराने की मांग करता हूं ।

श्री राकेश रंजन : भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड के कमरियाँव पंचायत के जादोपुर गाँव के दलित टोला में जाने का रास्ता नहीं है। जमीन निजी होने के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जमीन अधिग्रहण कर दलित टोला से पोखरा नहर तक सड़क निर्माण कराया जाए।

श्री अरूण सिंह : पटना जिला के फुलवारी शरीफ–नगर परिषद के पदाधिकारी एव संवेदक के लापरवाहियों के कारण दिनांक–14.02.2026 को नगर परिषद् अंतर्गत इशापुर राय चौक स्थित 02 वर्षीय बच्ची–खदिजा की खुले नालों में गिरकर मौत हो गई हैं। मैं वैसे लापरवाह पदाधिकारी सहित संवेदक पर जाँचोपरांत कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

श्री राजेश कुमार मंडल : रेल मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार पंडासराय, बेला, चट्टीचौक, कंगवा चुनाभट्टी एवं दिल्लीमोड़ में ओवरब्रिज निर्माण कार्य बहुत धीमा होने से जनसमुदाय को आवागमन में कठिनाईयाँ होती है। इनमें दोनार ओवरब्रिज दो अनुमंडल (बिरौल, बेनीपुर) के पाँच विधान सभा दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ा बौराम एवं कुशेश्वर स्थान की जनताओं को शहर आने–जाने का मुख्य मार्ग है । जहाँ प्रायः जाम लगा रहता है।

अतः मैं सरकार से दोनार सहित सभी ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : शिवहर जिले में उच्च शिक्षा व्यवस्था अत्यंत कमजोर है। एकमात्र डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है, पी0जी0 शिक्षा उपलब्ध नहीं है तथा महिला डिग्री कॉलेज का अभाव है। सरकार से डिग्री कॉलेज विस्तार कर पी0जी0 पाठ्यक्रम शुरू करने एवं महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग करती हूं ।

श्री विमल राजवंशी : रजौली विधान सभा अंतर्गत प्रमुख बजार सिरदता, लौंद, बिजुविगहा, सीतामढ़ी, मेसकौर प्रखण्ड, बरदाहा मोड़, मुरहेना, धमनी चौक, तारगीर, अमावां, कालीमंडप हरदिया, पदमौल एवं अकड़ी बाजा सहित कई स्थान है, जो अंधेरे से कूप है। मैं सरकार से अतिशीघ्र हाई मास्क लाईट लगाने की मांग करता हूं।

श्रीमती सोनम रानी : सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखण्ड के परसागढ़ी द0 के फसियाकोठी ग्रामीणहाट का डाक काफी दिनों से नहीं हो रहा है। जो सरकार के आय का एकमात्र साधन डाक नहीं होने से अतिक्रमण कर आवासीय घर बना लिया है।

अतः फसियाकोठी ग्रामीणहाट को अतिक्रमण मुक्त तथा डाक करवाने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री इन्द्रदेव सिंह : सिवान जिलान्तर्गत प्रखण्ड बड़हरिया में गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्टेडियम का कार्य लगभग 2009 से लंबित है, जिससे खिलाड़ियों एवं छात्रों को खेलकूद में काफी परेशानी होती है।

अतः स्टेडियम के कार्य को पूर्ण कराने की मांग करता हूं।

श्री अमरेन्द्र कुमार : औरंगाबाद जिला के देवकुण्ड थाना के थाना अध्यक्ष मनीष कुमार द्वारा थाना क्षेत्र के बंधवा ग्राम निवासी तेतरी देवी, पति रणधीर राजवंशी से दलित होने के कारण दुर्व्यवहार किया गया। मैं थाना प्रभारी मनीष कुमार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : राज्य के रसोइया, सेविका, सहायिका, आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय दैनिक मजदूरों के मजदूरी से भी कम है।

अतः मैं सरकार से उक्त सभी स्कीम वर्करों का मानदेय 21000/– रुपये करने की मांग करता हूं।

श्री मंजीत कुमार सिंह : गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखण्ड के रूपनछाप में शिवमंदिर के बगल में 1991 में निर्मित पुल नदी के कटाव में विलीन होने से आवागमन में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए रूपनछाप में उसी स्थल पर नए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : बिहार राज्य के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य के मानदेय को सम्मानजनक रूप से बढ़ाते हुए उनके पेंशन की व्यवस्था लागू करने एवं उन्हें आर्म्स का लाईसेन्स दिलाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री पुरन लाल टुडू : बांका जिला के बौंसी प्रखण्ड अन्तर्गत सांगा पंचायत में भूरभरी नदी है, जो झारखण्ड राज्य की सीमा के मुख्य मार्ग से सटा हुआ है, नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण जनता एवं मरीजों को आवागमन में कठिनाई होती है, भूरभूरी नदी में पुल बनाने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड में पहाड़ पर अवस्थित उमंगेश्वरी माता मंदिर जो पर्यटक स्थल घोषित है, दर्शनार्थियों को पहाड़ पर चढ़ने में कठिनाई होती है। पूर्व मुख्यमंत्री, श्री जीतन राम मांझी द्वारा इसी कठिनाईयों के मद्देनजर रोप–वे निर्माण की घोषणा की गयी थी। मंदिर पर दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु रोप–वे निर्माण की मांग करता हूं।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखण्ड अंतर्गत बेल डूमरवाना में अवस्थित रेलवे फाटक के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है ।

अतः सरकार नगर परिषद, बैरगनिया में अवस्थित रेलवे फाटक को हटा कर सड़क ऊपरी पारपथ (आर0ओ0बी0) बनाकर जाम की समस्या से निजात दिलाए।

श्रीमती कविता देवी : कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत फलका प्रखण्ड के पोठिया बाजार से डूमर जाने वाली सड़क पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हैं, जिससे जल जमाव की समस्या होती हैं।

अतः सरकार से उक्त सड़क के दोनों ओर लगभग 500 फीट लंबा नाला का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : गयाजी के गुरूआ गुरारू, परैया में प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे किया गया है, पूर्व में किये गए सर्वे को ही पुनः बिना गरीब दलित परिवारों का नाम जोड़े भेज दिये जाने से बहुत सारे परिवार वंचित हो गये है, सरकार से मांग करता हूँ कि कोई भी जरूरतमंद परिवार आवास से वंचित न हो।

श्रीमती संगीता देवी : बलरामपुर विधान सभा अंतर्गत बारसोई एवं बलरामपुर प्रखंड के कई हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर नहीं होने से आम जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं।

अतः सभी केन्द्रों पर शीघ्र डॉक्टरों की तैनाती की मांग करती हूं।

श्री अमित कुमार : बेलसंड में मनुषमारा नदी के भोरहा से बसौल पुल के बीच भारी जलकुंभी जमा होने से प्रवाह रूक गया है। इससे सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न है, जिससे किसानों का कृषि कार्य पूरी तरह बाधित है। मैं सरकार से शीघ्र नदी की सफाई और जल निकासी की मांग करता हूं।

श्री सुजीत कुमार : मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर के महाराणा प्रताप चौक के समीप खुले में बकरों का वध कर मांस बिक्री की जा रही है। आसपास, विद्यालय, अस्पताल व आवासीय क्षेत्र होने से बच्चों और आमजन को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार तत्काल रोक लगाकर लाइसेंस युक्त एवं स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

श्री राज कुमार राय : समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखण्ड के पी०एस०पी० उच्च विद्यालय की 5.6 एकड़ जमीन प्रखण्ड मुख्यालय निकट उपलब्ध है। जिसका खतियान, नक्शा भी शिक्षा विभाग के नाम से बना हुआ है।

अतः जनहित में उक्त उपलब्ध जमीन पर ही डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : गयाजी जिलान्तर्गत मुक्ति धाम विष्णुपद, गयाजी में चौबीसों घंटे हिन्दु रीति–रिवाज से शवदाह किया जाता है। रबर डैम बनने से नदी झील का आकार ले चुकी है। शवदाह गृह का अभाव है। परिजनों को इंतजार करना पड़ता है। मैं और शवदाह गृह बनाने हेतु सदन से मांग करती हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं में कुछ समय काम करने के बाद हटाये गए अतिथि शिक्षकों को पुनः वापस काम पर लाने के साथ–साथ नई बहालियों में अनुभव का लाभ देने की मांग करता हूं ।

श्री बबलू कुमार : खगड़िया में गैर–मजरूआ खास, बकाश्त एवं टोपो लैंड की राजस्व रसीद निर्गत करने तथा इससे संबंधित जमीन का खाता–खेसरा अप टू डेट

करने की मांग सरकार से करता हूँ। जिससे कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रीमती मनोरमा देवी : गयाजी नगर निगम अंतर्गत प्राचीन शक्ति पीठ मंगला गौड़ी स्थान में मूलभूत सुविधा का घोर अभाव सहित परिसर, भवन जर्जर है। जिससे श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है।

अतः मैं सरकार से उक्त शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार कराने की मांग सदन के माध्यम से करती हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : हिन्दुओं और तैतीस करोड़ देवी–देवताओं को अंगीकार करने वाली कामधेनु की तरह जीवनदायनी गौ माता से सबों को अमृत समान दूध, औषधी के रूप में गोबर–गौमूत्र प्राप्त होता है । गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बिहार में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से शहरी स्वरूप जैसे स्वच्छ व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, बैंक, बाजार जैसे सुविधा उपलब्ध हो पाएगा ।

अतः सरकार से मेजरगंज को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग करता हूं।

श्री रोहित पाण्डेय : भागलपुर नगर निगम एवं अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मियों/स्वच्छता योद्धाओं को अत्यंत कम मानदेय प्राप्त हो रहा है, जो जीवन–निर्वाह हेतु अपर्याप्त है । अनेक स्वीकृत पद भी रिक्त है।

अतः मै सरकार से मानदेय पुनरीक्षण एवं पात्र कर्मियों के नियमितीकरण की शीघ्र व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / हेमन्त / 20.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।
अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज गृह विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल = 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, गृह विभाग। अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20132,86,69,000 / – (बीस हजार एक सौ बत्तीस करोड़ छियासी लाख उनहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री मो0 कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री मो0 कमरूल होदा जी का प्रस्ताव प्रथम है।

अतएव, माननीय सदस्य श्री मो0 कमरूल होदा जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अखतरूल ईमान जी।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सतीश कुमार सिंह यादव।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की माँग 10/– रुपये से घटायी जाय।''

अध्यक्ष : श्री मनोज विश्वास। आपका समय चार मिनट है।

श्री मनोज विश्वास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से गृह विभाग से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसकी प्रगति की नींव होती है। यदि नागरिक सुरक्षा महसूस नहीं करे, तो विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे गृह मंत्री जी ने अभी गृह विभाग की मांग पेश की है। अमूमन जो मुख्य विपक्षी दल होते हैं, वह कटौती का प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि शायद संसदीय इतिहास में यह पहली बार होगा कि गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती प्रस्ताव मुख्य विपक्षी दल नहीं देकर, बल्कि एक निर्दलीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव लाये हैं और..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये न।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप अपनी पार्टी का नाम बता दीजिए।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : राज्य पार्टी के...

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, राष्ट्रीय पार्टी है।

अध्यक्ष : हां ठीक है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उतना हम सुधार कर लेते हैं। सतीश जी जिस भी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन यह तो सच्चाई है कि उस पार्टी के आप अकेले सदस्य हैं। यह तो सच्चाई है। ऐसी पार्टी जिसके मात्र एक सदस्य सदन में हैं, वह कटौती प्रस्ताव लाये हैं और हमारी दूसरी पार्टी के सदस्य इसके समर्थन में

खड़े हैं। महोदय, देखिएगा कि सोशल मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया, अनेक हमारे विपक्षी नेताओं के बयान गृह विभाग के कार्य कलाप के संबंध में, विधि व्यवस्था के संबंध में आए दिन भरे रहते हैं। लेकिन क्या यह संसदीय प्रणाली की गंभीरता है कि जब सदन, जो सबसे उपयुक्त स्थल होता है, यह किसी सरकार की उपलब्धियों या कमियों, जो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं, उसकी चर्चा करने की जो सबसे उपयुक्त जगह है, वहां पर मुख्य विपक्षी दल ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। हमें तो ये लगता है कि कहीं सरकार के कार्यकलाप से, गृह विभाग के कार्यकलाप से, मुख्य विपक्षी दल संतुष्ट तो नहीं है ?

अध्यक्ष : श्री मनोज विश्वास जी।

(व्यवधान)

अब बात आ गयी है। आप बोलिये न।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय संसदीय मंत्री ने आरोप लगाया है, तो एक मिनट तो दीजिएगा न।

अध्यक्ष : उन्होंने सुझाव दिया है, आरोप नहीं लगाया है। आप अपने समय पर बोलियेगा न। आपको बोलने के लिए समय मिलेगा।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सर्वजीत जी, सिर्फ आप इतना सुधार कर लीजिए कि हमने आरोप नहीं लगाया है। हमने, जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको बयान किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा। 18 मिनट का समय है, उस समय बोलियेगा। आप उस समय बोलियेगा, आपको हम मौका देंगे।

श्री मनोज विश्वास : सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, गठबंधन की सरकार इधर भी है और उधर भी है। उनकी भी सरकार गठबंधन से चल रही है और हम लोग भी गठबंधन में हैं। आपस में हम लोगों ने बैठकर तय किया कि कटौती प्रस्ताव कौन लायेंगे और...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, चूंकि माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है और मैंने इनकी बातों को गंभीरता से लिया है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है और महिला अत्याचार आप नहीं रोक पा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग मिलकर आपके विरोध में बोलने के लिए खड़े होते हैं।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सिर्फ एक बात, जो सर्वजीत जी ने कही कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का विपक्ष भी है, लेकिन यह सदन और यह सत्र, पूरे सत्र काल में साक्षी है कि जितने विभागों की मांग आई हैं, आप ही के दल के एक हमारे नौजवान साथी, राहुल जी ने बिना किसी दूसरे विपक्षी दल की परवाह किए हुए सभी पर कटौती प्रस्ताव डाला था और सब पर यही प्रस्ताव कर रहे थे। इसलिए, यह मुख्य विपक्षी दल का विपक्षी जो गठबंधन है, उसके जो दल हैं, उनके प्रति और असंवेदनशीलता का द्योतक है।

अध्यक्ष : श्री मनोज विश्वास जी।

श्री मनोज विश्वास : सर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था उस राज्य की नींव होती है। यदि नागरिक सुरक्षा महसूस नहीं करें, तो विकास की कोई योजना सफल नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में टोका–टोकी नहीं करें।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, गवर्नर और बिहार पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी अपराध साइबर क्राइम के माध्यम से बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। महोदय, हर थाना में इसकी नियुक्ति की जाय। साइबर की बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं। सर, तीसरा है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, यह हम लोगों के प्रशासन की मिलीभगत से शराब का इतना बड़ा कारोबार होता है। हम लोग सीमांचल, बॉर्डर एरिया से आते हैं, जोगबनी का बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग हैं, वहां बहुत ज्यादा शराब की तस्करी होती है और सूखा नशा की तस्करी होती है। सर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर, फारबिसगंज व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हमको लगता है कि फारबिसगंज, जहां से हम चुनकर आए हैं, वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हमेशा शहर में जाम की समस्या रहती है। हम गृह मंत्री से निवेदन करेंगे कि एक ट्रैफिक पुलिस का थाना वहां होना जरूरी है। सर, अररिया जिला में जो गश्ती की गाड़ी होती है, हर जगह गश्ती की गाड़ी खराब पड़ी हुई है। गश्ती की गाड़ी नहीं रहने के कारण, कहीं से अगर कोई घटना की सूचना मिलती है, तो प्रशासन नहीं पहुंच पाता है। सर, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर, एक और महत्वपूर्ण विषय है कि फारबिसगंज जनसंख्या के दृष्टिकोण से या जिस भी दृष्टिकोण से हमारा फारबिसगंज महत्वपूर्ण जगह है। सर, वहां पर 31 पंचायत और दो नगर हैं, तो वहां पर एक नया ब्लॉक बनाने का, जो सिमराहा, रेणु जी जो साहित्यकार थे, उनकी जगह पर एक नया प्रखंड बनाने की मांग गृहमंत्री जी से करता हूं। दूसरा सर, हम लोग पुलिस जिला बनाने के लिए फारबिसगंज के लिए, आप तमाम लोगों को धन्यवाद देंगे कि फारबिसगंज को पुलिस जिला घोषित करने की कृपा करें। मंत्री जी, फारबिसगंज को पुलिस जिला घोषित

करने का, फारबिसगंज व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सर, उस पर भी ध्यान दिया जाए। तीसरा विषय है, जो हमारी युवा पीढ़ी अभी गलत शराब और सूखा नशा की तरफ जा रही है। सर, वहां पर अलग से, जो हमारे यहां नए एस0पी0 साहब गए हैं, अच्छे लोग हैं, सर, बॉर्डर एरिया में पहल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उससे वह रुक सकती है। धन्यवाद सर।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की आय व्यय में सम्मिलित अनुदनों की मांगें, गृह विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग। इनके समर्थन में मैं खड़ा हूं। महोदय, खड़ा हूं, तो साहब जाफरी के शेर के साथ मैं इन लोगों का स्वागत भी करना चाहूंगा। इन लोगों को यह सब शेर–शायरी पसंद है। महोदय, आपके माध्यम से हम इन लोगों के शान में एक शेर पढ़ना चाहते हैं कि

''तू इधर–उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा,
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।''

महोदय, जब भी विधानसभा में चर्चा होती है, तो 1990 से 2005 की बात और 2005 से 2025 तक की बात, यह तो एकदम लाजिमी है।

(क्रमशः)

टर्न–12 / संगीता / 20.02.2026

....क्रमश....

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, जब भी विधान सभा में चर्चा होती है तो 1990 से 2005 की बात और 2005 से 2025 तक की बात, यह तो एकदम लाजिमी है । अगर हम अपना इतिहास नहीं खंगालेंगे तो स्वर्णिम भविष्य कैसे बनायेंगे, इसीलिए आज के दिन गृह विभाग पर बोलने के लिए, मैं सबसे पहले आपका बहुत–बहुत आभारी हूं, साथ में एन0डी0ए0 की सरकार का, जिन्होंने बहुत अच्छे काम करके एक बहुत ही निर्णायक बिहार में लोगों के मन में ये विश्वास जगाया है कि अब कानून का राज है, अब अपराधियों का राज नहीं है । महोदय, मैं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारे उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, हमारे दूसरे उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी को और पूरे मंत्रिमंडल का मैं आभारी हूं, जिन्होंने बिहार की जनता के मन में यह विश्वास पैदा किया है कि बिहार में अब कानून का राज है, अब अपराधी किसी मंत्री के यहां नहीं शरण लेता है, अपराधियों का जगह या तो जेल में है या फिर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : और नहीं तो अपराधियों के लिए जय श्रीराम है, यह बात सबके ध्यान में है । महोदय, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी तो चारों तरफ हाहाकार था और ऐसा हाहाकार था, लगता नहीं था कि अब बिहार पटरी पर आएगा, नारा था, एक नेता के द्वारा नारा था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है कि हमारा 13 करोड़ परिवार और विकसित हो बिहार, यह नारा हमारे नीतीश कुमार जी का है और इनका नारा था, हमारा परिवार विकसित परिवार, नारा था इनका और इसी को लेकर ये चलाया करते थे शासन और इसीलिए जनता ने यहां एक कोने में इनको बिठा दिया । महोदय, जब...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे माननीय सदस्य नहीं बोलें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, ये लोग कभी कानून को मानते नहीं हैं । ये अपनी बात कह लेते हैं और दूसरे की सुनते नहीं हैं, हम तो आंकड़ा लेकर खड़ा हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अनीता जी, बैठकर बिना अनुमति के नहीं बोलें । बैठकर कोई भी नहीं बोलें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब जाकर जमाना बदलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बदल के दिखाया और आज बढ़ता बिहार और आज बिहार जो ए0आई0 में जाकर अपना पहचान बना रहा है, ये बिहार है महोदय ।

महोदय, थोड़ा सा इन लोगों का जरा लालू चालीसा के बारे में थोड़ा बता देते हैं महोदय । 1990 से 2005 के बीच और हम क्या कहें हम तो एक घटना आंख के सामने देखे हैं । महोदय, एक बच्चा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आई0पी0गुप्ता जी, जब चल रहा है भाषण तो क्रॉस करने से पहले ध्यान रखना चाहिए था, भविष्य में ऐसा नहीं करें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सॉरी, सॉरी, सॉरी अध्यक्ष महोदय ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, ये कन्फ्यूज हैं कि ये विपक्ष में हैं कि सत्ता पक्ष में हैं...

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं कन्फ्यूज नहीं हूं...

अध्यक्ष : बैठ जाएं प्लीज ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं एक दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने जा रहा था, देखा कि एक बच्चा जोर–जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था दो रुपया में चालीसा ले लो, दो रुपया में चालीसा ले लो, हम यह देखते–देखते चले गए पूजा करने, जब लौटे तो देखे एक बुढ़िया अम्मा उसी बच्चे से झगड़ा कर रही थी, मैंने उस अम्मा से पूछा कि क्यों लड़ रही हो तो उसने कहा बेटा, इसने कहा दो रुपया में चालीसा दे रहा हूं, मैंने चालीसा समझकर दो रुपया

दे दिया, मुझे देना था इसको हनुमान चालीसा, इसने दे दिया लालू चालीसा, अब महोदय, जब मैंने उस बच्चे को डांटा तो उसने कहा, आपके हनुमान जी ने क्या किया है, केवल एक लंका ही तो जलाई है, हमारे लालू जी ने पूरा बिहार जला दिया, इसलिए लालू चालीसा पढ़ना चाहिए । महोदय, इनके राज्य में 32 हजार से अधिक अपहरण हुए । हमको याद है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी मैदान में आकर और वहां उन्होंने कहा था किसलय को किसने छुपाया ? यह बात बिहार के 13 करोड़ लोगों के कान में गई, यह इनके समय में हुआ करता था तो महोदय, 1990 से 2005 के बीच 32 हजार से अधिक अपहरण, हत्या तो कहना ही नहीं है महोदय, लेकिन आज...

(व्यवधान)

हम वह भी बताते हैं आप चिन्ता मत करिए, एक–एक पोल खोलेंगे आपलोगों का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ कर आपस में बात नहीं करें । आपको मौका मिलेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, 18 हजार से अधिक हत्याएं गरीबों की की गईं, 100 से ऊपर नरसंहार हुए, मैं एक–एक नरसंहार का नाम लूंगा, 100 से अधिक नरसंहार हुए, कोई बता तो दे कि माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में कहां चले गये ये नरसंहार करने वाले लोग, आज वही बिहार बुद्ध का बिहार बन करके बैठा है, आज वही बिहार जैन का बिहार है महोदय, आज वही बिहार राजेन्द्र बाबू का बिहार है इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है । महोदय, चुनावी हिंसा में 50 पुलिस वालों की हत्या, अब आप बताइए महोदय, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था तो पोटा कानून लागू हुआ, जैसे ही 2004 के बाद ये लोग आ गए, तुरंत पोटा कानून हटा दिया, पता नहीं इन लोगों को आतंकवादियों से क्या–क्या उनके प्रति इनका क्या भाव है, जो कड़ा कानून लाती है एन0डी0ए0, जब ये आते हैं तो हटा देते हैं । महोदय, आज हम कहना चाहेंगे इस बिहार में अगर बिहार का इतिहास कलंकित हुआ तो एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में कलंकित हुआ, एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी के लिए सोफा उठाकर लाए गए, गाड़ियों को खींच कर लाया गया और जो रक्षक होता है...

(व्यवधान)

वह भक्षक बनकर खड़ा था, रक्षक और भक्षक में अंतर करने की स्थिति नहीं थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नाम नहीं ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

किसी का नाम इन्होंने नहीं लिया है ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं । माननीय सदस्य बैठिए, किसी का नाम नहीं लिया है...

श्री मिथिलेश तिवारी : बिहार की बात कर रहे है, बिहार के ऊपर भी आते हैं घबड़ाइए नहीं...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय, एक मिनट...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए सरकार खड़ी है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : सदन शांति और गंभीरता से सुनने का जगह है और सदन में जब आरोप लगाया जाता है, अगर जो आप उसका प्रतिवाद करते हैं तो बड़े जिम्मेवार माननीय सदस्य हैं, अनुभवी भी हैं, राज्य के बड़े मंदिर से लेकर, देश के बड़े मंदिर तक बैठे हैं । महोदय, ये कहते हैं कि गलत आरोप है तो क्या शपथ आप लेकर कह सकते हैं कि वे जो बोल रहे हैं वह गलत है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, क्या वे शपथ लेकर बोल सकते हैं कि वे सही बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महोदय, मैं शपथ लेता हूं...

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : यह बिल्कुल गलत है महोदय, बिल्कुल गलत है और इस तरह की बयानबाजी व्यक्तिगत आक्षेप सदन में नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, 17 माह में जब इनकी सरकार कुछ दिन के लिए नीतीश बाबू इनके साथ चले गए थे तो 17 महीने में 2023 में 3.54 लाख अपराध दर्ज हुए, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और उसी को देखकर बिहार की जनता फिर कांप गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों से हमेशा के लिए टाटा–बाय–बाय कर दिया इसीलिए उसी से परेशान हैं ।

...क्रमश...

टर्न–13 / यानपति / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इनके समय में पुलिस की यह स्थिति थी महोदय । नरसंहार में जो लोग शामिल होते थे, उनके साक्ष्य के आरोप में उनको बरी कर दिया जाता था महोदय । क्योंकि पुलिस सरकार के इशारे पर काम

करती थी । आई0पी0सी0 का मतलब, एक नेता के आई0पी0सी0 के बराबर हो गया था महोदय । महोदय, 18 मार्च, 1999, आलोक जी कह रहे थे, मैं तो उस खानदान से जन्म लिया हूं कि हमारा, मैं आपको अपना परिचय बताता हूं, हमारे घर में 10 आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 ऑफिसर हैं । मैं जानता हूं कि कानून का मतलब क्या होता है और इसलिए आज मैं आपको कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, 18 मार्च, 1999...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी बैठ जाइये, मौका मिलेगा, बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : संस्कृत में समझाते हैं आपको, संस्कृत में समझाते हैं, बैठिए,

''मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्,
आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः ।''

यह हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे देश के शास्त्रों में लिखा है महोदय । महोदय, सेनारी की घटना तो सबको याद होगी, 34 लोगों की हत्या हुई थी महोदय, उस समय यह कह सकते हैं क्या लालू जी सत्ता में नहीं थे, यह कह सकते हैं क्या राबड़ी जी सत्ता में नहीं थीं, महोदय, 25 जनवरी, 1999 जहानाबाद के शंकर बिघा में 22 दलितों की हत्या हुई थी, 1999 में कौन सत्ता में था महोदय । महोदय, 1996, भोजपुर जिला के बथानी टोला नरसंहार महोदय, 22 लोगों की हत्या हुई थी महोदय, गया जिले के बारा नरसंहार 12 फरवरी, 1992...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, 25 लोगों की हत्या हुई, औरंगाबाद जिले के मियापुर में 26 जून, 2000 को 35 दलितों की हत्या हुई महोदय, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, 1997 में जहानाबाद जिले में 58 लोगों की हत्या हुई महोदय, जिसमें 27 महिलाएं शामिल थीं महोदय । 1990 से 2005 के बीच महोदय तीन सौ से चार सौ दलित लोग हिंसक घटनाओं के शिकार हुए महोदय । महोदय...

(व्यवधान)

अब हम आपको बताना चाहते हैं महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आप बोलियेगा । आपकी पार्टी को समय मिलेगा तो बोलियेगा। आपके दल को समय निर्धारित है, उस समय बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, अब हम इनको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार को कितना प्रेम है । गांधी जी ने जब अंतिम सांस ली थी महोदय तो हे राम कहकर गांधी जी इस लोक को छोड़कर गए थे और इसीलिए मोदी जी ने

जीरामजी कार्यक्रम चलाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया है महोदय । महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग कृपया अपने आसन पर बैठ जायं । आलोक बाबू, आपस में बात नहीं करें । आपके दल को समय है 18 मिनट, बोलियेगा । मौका मिलेगा, बोलियेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, इस देश में लंबे समय तक सैकड़ों सालों तक, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया महोदय, फिर भी हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बची तो मंदिरों के कारण बची महोदय और आज हमारी सरकार धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, हम अपने गृह मंत्री जी को बधाई देंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति की नहीं बोलें । प्लीज बैठिए । बैठ जाइये । आपको मौका मिलेगा बोलने का । आपको भी मौका मिलेगा बोलने के लिए । कृपया बैठ जायं । कृपया बीच में नहीं खड़े हों । किसी के भाषण में नहीं खड़ा होना चाहिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में, समावेशी शासन में सबका साथ सबका विकास...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : और न्याय के साथ विकास के साथ महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठिए न । आपको मौका मिलेगा तो बोलियेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : हमारी ये बहन चंपा विश्वास का नाम नहीं सुनी हैं महोदय और इसीलिए खड़ा होकर बोल रही हैं महोदय, एक आई0ए0एस0 की पत्नी के घर में, एक आई0ए0एस0 के घर में घुसकर, महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य होते थे महोदय और उसको संरक्षण बिहार की सरकार देती थी महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, आज महिलाओं के लिए हमारी सरकार...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है ।

(व्यवधान)

कृपया हल्ला नहीं करें । बैठ जाइये । बिना अनुमति के नहीं बोलने का प्रावधान है । बैठ जाइये । आप नई सदस्य हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, आज हम बधाई देंगे अपने गृह मंत्री जी को कि उन्होंने...

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : कब्रिस्तानों के साथ–साथ मंदिरों की घेराबंदी के लिए भी प्रावधान किया है और मंदिरों की चहारदीवारी के साथ–साथ हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति को भी बचाने का काम किया है । महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार सिंह ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, एक मिनट महोदय । अब जरा हम अपने क्षेत्र की कुछ बात कह दें। महोदय, हम माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं

(व्यवधान)

समस्या नहीं है । समाधान सब समस्या का हो गया है। सुनिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग क्यों बोल रहे हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, हमारे गृह मंत्री जी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, कहते हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर आ गया, जबकि वह कह चुके हैं कि हमारा कोई बुलडोजर नहीं है, वह कानूनी बुलडोजर है । फिर भी ये लोग कांपते रहते हैं । महोदय, हम कहना चाहेंगे अपने माननीय गृह मंत्री महोदय जी को कि माननीय गृह मंत्री जी, हम जब 15 से 20 विधायक थे, 15 से 20 के बीच तो हमने सरकार से आग्रह किया था, एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय हमारे यहां सिद्धवलिया में बनाने का, हम सरकार को बधाई देते हैं कि सरकार ने एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय बना दिया है, लेकिन वह माननीय श्रवण बाबू के विभाग की वह बिल्डिंग है जिसमें एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय चलता है और वह खाली है, चूंकि वहां से ब्लॉक ट्रांसफर हो गया कहीं महोदय, तो हम आग्रह करेंगे माननीय गृह मंत्री जी से कि वह ग्रामीण विकास से भवन लेकर और उसको परमानेंट एस0डी0पी0ओ0 के लिए कर दिया जाय । राजापट्टी में थाना खोलने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है लेकिन अगले एक–दो महीने में खुल जायं चूंकि दो–दो पुल हैं महोदय ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिंह ।

श्री मिथिलेश तिवारी : और महोदय, बिहार में उत्तर प्रदेश की भांति पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना हो महोदय । पुलिस कमिश्नरेट बन जाने से ये भूमि विवाद का निपटारा करने में बहुत सुविधा होगी । इतना ही कहता हुआ, आपने मुझे सुना और सभी माननीय सदस्यों का आभार करता हुआ और एक बार फिर से नीतीश कुमार जी की जय–जयकार करता हुआ और एन0डी0ए0 सरकार की जय जयकार करता हुआ, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिंह । सात मिनट है ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा बोलने के लिए । आपके दल का समय 18 मिनट का है । आलोक जी, हर बात में खड़ा होने की जरूरत नहीं है । हम बुलवायेंगे इस बार, पहले इनका होने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : कि आपने हमें गृह विभाग की अनुदान मांगों के पक्ष में...

(व्यवधान)

और विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने का अवसर दिया है । महोदय, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिनकी कृपा से मैं इस सदन का सदस्य बना और पहली बार मुझे गृह विभाग पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय वित्त मंत्री–सह ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी, विधान सभा में जनता दल यू0 के सचेतक–सह माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी तथा बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण तथा इस सदन में उपस्थित पक्ष एवं विपक्ष के सभी विधायकगण, आप सभी को दिल की गहराईयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही साथ मैं रफिगंज की देव तुल्य जनता जनार्दन का चरण स्पर्श करता हूं कि मुझ पर भरोसा कर के मुझे बिहार विधान सभा का सदस्य बनने का आर्शीवाद दिया है । महोदय, मैं इस सदन में बोलने से पहले आज विपक्ष के लोगों को किसी भी बात पर इतनी मिर्ची लग रही है कि ये बोलने नहीं दे रहे हैं । एक शेर अकबर इलाहाबादी का है उसे पढ़कर सुनाता हूं महोदय कि,

''हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।''

सदन की कार्यवाही आगे बढ़े उसके पहले मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के उस बयान की कड़ी निंदा करता हूं जो उन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के बारे में एक ऐसा शब्द अचेत और कठपुतली कहा है । इनको अपने भविष्य में जाना चाहिए और याद करना चाहिए जब उनकी माता मुख्यमंत्री थीं तो उस समय वो सिर्फ दस्तखत करती थीं और फैसला कोई और करता था, वह उनको याद नहीं है । हमारे विकास पुरूष मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, यह एक अशोभनीय शब्द है । मैं उनसे कहता हूं कि इस शब्द को वापस लेते हुए मांफी मांगें सदन में आकर के ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / मुकुल / 20.02.2026

क्रमशः

श्री प्रमोद कुमार सिंह : और वह याद करें कि अपनी कठपुतली जैसी जो सरकार चल रही थी, मुखिया उनकी माता थी और शासन कोई और करता था । महोदय, मैं यहां पर एक बात जरूरत उद्धृत करना चाहूंगा कि आज बिहार नक्सल की समस्या से मुक्त हो चुका है । महोदय, मैं उस जिला से आता हूं जहां नक्सलियों का तांडव होते रहा है, आप जानते हैं हमारे बगल के जिला के हैं । औरंगाबाद का इतिहास रहा है कि वहां पर बड़े–बड़े नरसंहार हुए और उस नरसंहार के जो जन्मदाता थे महोदय, इनके शासनकाल में जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनको बुलाकर के विजिलेंस का मंत्री बना दिया गया महोदय । जिन्होंने दलेलचक बघौरा जैसा कांड, मियांपुर दलितों का नरसंहार और दरमिया, दलेलचक बघौरा, मियांपुर जैसे हमारे जिलों में इतना बड़ा–बड़ा नरसंहार हुआ और उनको विजिलेंस का मंत्री बनाने के बाद, अभी कह रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कि उस समय एफ0आई0आर0 बैठकर के डिल होता था तो जब विजिलेंस का जिनके ऊपर 100–100 नरसंहारों का आरोप हो और वह विजिलेंस के मंत्री बन जाएं, वहां पर शासन और गृह विभाग क्या कर सकता है, कानून क्या कर सकता है महोदय ? महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए गृह विभाग को 20 हजार 132 करोड़ 86 लाख 69 हजार से अधिक रुपये आवंटन राज्य के कुल 3.47 लाख करोड़ के बजट का एक बड़ा हिस्सा है, जो दर्शाता है कि सरकार के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है । अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग किसी राज्य का रीढ़ होता है । यदि घर सुरक्षित है, तभी विकास की बातें शोभा देती हैं । विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां बहुत सी बातें कहीं, उन्हें सुनकर मुझे एक शेर याद आता है –

''फाइलों में दर्ज है कि अमन का दौर है,
मगर उसकी नजर में हर तरफ बस शोर है ।''

महोदय, ये वही लोग हैं, जिन्होंने बिहार को उस दौर में धकेला था जब सुरक्षा शब्द केवल शब्दकोश में मिलता था, धरातल पर नहीं, आज हमारी सरकार न्याय के साथ विकास और कानून के राज को चरितार्थ कर रही है । अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 का यह बजट केवल पुलिसकर्मियों के वेतन का बजट नहीं है, यह स्मार्ट पुलिसिंग का ब्लूप्रिंट है । आज बिहार के सभी 1000 से अधिक थाने सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन हो चुके हैं । डायल–112, 15 से 20 मिनट में फोन करने के बाद पुलिस किसी भी समस्या की जगह पर पहुंच जाती है । सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस ग्रिड केवल पटना में ही नहीं, बल्कि बिहार के हर निगम और संवेदनशील चौक–चौराहों पर हाई–डेफिनेशन कैमरों का जाल बिछाया गया है यह हमारी सरकार की देन है।

महोदय, फॉरेंसिक लैब जांच में तेजी लाने के लिए हर प्रमंडल स्तर पर आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की गयी है । महोदय, स्पीडी ट्रायल की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है । महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात तो सब करते हैं, लेकिन उसे जमीन पर हमारी सरकार ने उतारा है । आज बिहार देश का वह गौरवशाली राज्य है महोदय जहां पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 35 प्रतिशत है । आज थानों में जाइए, तो वहां महिला हेल्प डेस्क पर हमारी बेटियां वर्दी पहनकर न्याय कर रही हैं । यह देखकर गांव की आम महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है । महोदय, साईबर अपराध की बात अभी कर रहे थे, साईबर अपराध के मामले में हमारी सरकार इतना सजग है कि दुनिया बदल रही है, अपराध का तरीका बदल रहा है तो हमारी पुलिस भी बदल रही है और हमने हर जिले में साईबर थाने खोले हैं और 2026–27 के बजट में साईबर सेल को और अधिक एडवांस सॉफ्टवेयर देने का प्रावधान किया गया है, सरकार ने ऐसी रखी है महोदय । आज नशा मुक्ति और मद्यनिषेध.....

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट का समय दिया जाए । महोदय, आज समाज का हर वर्ग उत्थान कर रहा है । महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ हमारी समस्या है, रफीगंज विधान सभा के अंतर्गत भदवा बाजार जो मुख्यालय से 17 कि0मी0 है और रफीगंज थाना से 15 कि0मी0 की दूरी पर है, वहां आये दिन अपराध की घटनाएं आती रहती हैं । महोदय, वहां पर एक पुलिस चौकी खोलने का मैं मांग करता हूं और तीन प्रखंडों का वहां पर बाजार है बराही बाजार जो पौथू थाना के अंतर्गत आता है महोदय, जो रफीगंज थाना से करीब 21 कि0मी0 और पौथू थाना से 17 कि0मी0 की दूरी पर है, वह बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है महोदय, वहां करीब–करीब 30 से 40, 50 गांवों के लोगों का बाजार है और वह दूरी है थाना से, इसलिए वहां भी मैं निवेदन करता हूं कि एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए । महोदय, मैं आप सबों को लास्ट में एक बात कहता हूं कि ये जो आज हमारी सरकार है कि–

''चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गयी होंगी,
यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का,
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन के रहनुमाई का।''

जय जदयू, जय बिहार, जय सूर्य भगवान ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, आज सुबह से ही देख रहा हूं कि सदन में कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं जिनकी सदन में उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, जाति सूचक, जाति और वर्ग में अंतर होता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गृह विभाग पर बोलिए न ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इस बात को बताया जा चुका है, उसके बावजूद इस तरह की बातें सदन में.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज का विषय गृह विभाग है, उस पर आप बोलिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सामाजिक परिवर्तन का दौर था 2005 से पहले और 1990 के बाद का दौर और सामाजिक परिवर्तन एक क्रांति थी और क्रांति शांति से नहीं आती है, क्रांति कहीं न कहीं किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को जंगल राज बताकर बार–बार सत्तापक्ष के लोग इस पर टिप्पणी करते हैं ।

(व्यवधान)

कांग्रेस के दौर को, कांग्रेस के 50 वर्षों के दौर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1857 के आंदोलन के वर्षगांठ के अवसर पर कहा था कि कांग्रेस के 50 वर्षों में देश में विकास नहीं हुआ, यह कहना बेईमानी होगी और पुरुषार्थ के विरुद्ध होगा । इस तरह की बातें बार–बार सदन में.....

अध्यक्ष : श्री राहुल कुमार । माननीय सदस्य, आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह वाजपेयी जी की भावना के विरुद्ध है और पता नहीं किनको मानने वाले लोग हैं ये लोग, महात्मा गांधी का नाम लेंगे लेकिन उनके हत्यारों की भी मूर्ति लगा देंगे, कन्फ्यूज करना चाहते हैं पूरे देश को कि ये किसके पक्ष में हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री राहुल कुमार । राहुल जी, क्या आप नहीं बोलेंगे ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज की मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में और सरकार की मांग के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं बोलूं उसके पहले बस एक शेर रखना चाहता हूं–

''देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें,
ढूंढ़ोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा।''

महोदय, आज मोटा–मोटी व्यवस्था बिहार में ऐसी ही है । हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह व्यवस्था खराब चल रही है लेकिन हर जगह इनको गुलजार दिख रहा है, समस्या समझ में आती है । महोदय, कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार चल रही हो, किसी की भी सरकार हो, वह इकबाल से चलता है और अगर सरकार के इकबाल को बुलंदी पर पहुंचाने का काम करता है तो एक मात्र विभाग है गृह विभाग, जिसमें पुलिस के लोग जो सारे अधिकारी होते हैं वे लोग काम करते हैं लेकिन आज क्या है, बिहार की

जो व्यवस्था है पुलिस की, चाणक्य के समय की व्यवस्था है महोदय, मौर्यकालीन व्यवस्था है बिहार में जो पुलिस की व्यवस्था चल रही है और आज हमारे मंत्री हैं अपने आपको मौर्य के ही वंशज कहते हैं तो इनके ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ती है, जब ये गृह मंत्री बने थे, जब जदयू से उन्होंने छिना था इस विभाग को तो लोगों में एक आशा जगी थी कि बिहार में एक इन्डीपेंडेंट विभाग काम करेगा, हरेक व्यवस्था काम करेगी लेकिन इनकी जिम्मेवारी तो बढ़ी, लेकिन आज लोगों में महोदय निराशा आ गयी है । लोगों ने सोचा था कि क्राइम के ग्राफ घटेंगे, लोगों के अंदर में एक विश्वास जगेगा लेकिन व्यवस्था उस ढंग से काम नहीं कर सकी । आप देखते हैं महोदय डाटा की बात आप कीजिए तब आप देखेंगे कि क्राइम का ग्राफ लगातार 2005 के बाद, 2010 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कंविक्शन का रेट है, वह लगातार गिरता जा रहा है और 2013–14 के पास आप आयेंगे तो देखेंगे कि दोनों एक हुआ था और उसके बाद से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और जो कंविक्शन का रेट वह लगातार गिर रहा है, महोदय आज ऐसी व्यवस्था बिहार में चल रही है । धारणा आप समझ सकते हैं महोदय,

क्रमशः

टर्न–15 / सुरज / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री राहुल कुमार : महोदय, इनके शुरू के समय में कुछ कानून व्यवस्था में काम हुआ था । लेकिन आप सिर्फ शुरू की व्यवस्था पर लगातार 20 और 21 साल की सरकार आप नहीं चला सकते हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी । एक आंसू भी हुकूमत के लिये खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समुन्द्र होना । यहां बिहार में हर जिले में, मैं जिले का नाम क्या लूं हर जिला का कोई न कोई व्यवस्था । जहानाबाद में आप देखिये नीट बच्ची के साथ क्या हुआ ? उसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई, किसी ने आज तक आवाज तक नहीं सुनी । औरंगाबाद में ही तीन दलित बच्चियां घर से गायब हो गयीं, आज तक किसी ने नहीं देखा । महोदय, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था में सकारात्मक काम करे । कोई नेता हो, चाहे किसी भी दल का हो, किसी की भी सरकार हो, सारे लोग चाहते हैं कि शांति–व्यवस्था से काम हो । कोई नहीं चाहता है कि उसके समय में अशांति फैले । लेकिन अगर हम अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे, अगर हम कनविक्शन रेट नहीं बढ़ायेंगे तो व्यवस्था बिगड़ती है और शुतुरमुर्ग की तरह सिर्फ बालु में मुंह गिरा लेने से कुछ नहीं होगा, आपको सच्चाई सुननी होगी, आपको उसके ऊपर एक्ट करना होगा । महोदय, आप देखिये लगातार गुंजन खेमका का हत्याकांड, आप देखिये गोपाल खेमका का हत्याकांड । क्या होता है बेटा मरता है, बाप मर जाता है, आज कहां है कनविक्शन ? आप उसी तरह देखिये जो सहरसा में

चौमिन बेचने वाले की वसूली के लिये हत्या कर दी गयी । बक्सर में पप्पु साह की हत्या कर दी गयी, छोटे–छोटे व्यापारी हैं इनकी हत्या कर दी जा रही है । उसी तरह चकाई में एक घटना हुई, चकाई में बमबारी की घटना कुछ दिनों पहले हुई है । क्या हुआ है हर जगह ? जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हम उसकी सराहना करते हैं । जहानाबाद में हाल में एक बच्ची गायब हुई थी, पुलिस ने बहुत तत्परता से तीन दिन के अंदर वह बनारस से लेकर आये थे, हमने उनकी सराहना की थी । लेकिन आज फिर तीन दिन पहले तीन बच्चियां गायब हो गयीं हैं उसी जहानाबाद से, उसकी कोई खोज–खबर नहीं है । लगातार हमलोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको इस चीज को देखना होगा कि यह व्यवस्था जा कहां रही है ? महोदय, राज्य के जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, अच्छे पुलिस पदाधिकरी आपके पास हैं चाहे डी0जी0पी0 हो, डी0जी0 हों कुंदन कृष्णन के रूप में हैं, विनय बाबू के रूप में हैं । लेकिन अगर आप उन पर लगाम लगाकर रखेंगे, काम करने नहीं देंगे सिर्फ आंकड़ों के खेल में जायेंगे, सिर्फ अपनी सरकार की छवि बचाने की तरफ जायेंगे तो काम नहीं होगा और यही व्यवस्था आप देख रहे हैं । आपको शराबबंदी की समीक्षा की बात कहते हैं तो आपलोगों को बुरा लगता है लेकिन आपको देखना चाहिये कि 10 वर्ष हो गये हैं, 10 वर्ष में आपने क्या खोया, क्या पाया ? आपने जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की थी उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं और आज तमाम व्यवस्था में एक सूखा नशा घुस गया । शराब के एक पैरलल इकोनॉमी, जो सरकार के समकक्ष खड़ी हुई है, जो लगभग एक लाख करोड़ रुपये की है, वह सरकार के सामने खड़ी है, जो सरकार को मुंह चिढ़ा रही है । आज यह व्यवस्था खड़ी है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं सूखा ड्रग्स का कारोबार । आज एन0डी0पी0एस0 एक्ट हमलोगों के सामने है, कहां है ? उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिये । आज हर जिले में, हर पंचायत में, हर जगह में आप देखिये की सूखा नशा का कारोबार हो रहा है । सूखा नशा का करोबारी दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है और यह एक दिन हमलोगों के बीच में समस्या खड़ी होगी । जिस तरह से आज पंजाब सूखा नशा के लिये वहां की असेंबली में हंगामा होता है, बिहार में भी बहुत दिन दूर नहीं है और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसी के चलते लूट, छिनतई, रेप जैसी घटनाएं, नाबालिग बच्चियों के साथ, एक साल की बच्ची, डेढ़ साल की बच्ची, ढ़ाई साल की बच्ची, चार साल की बच्ची । क्या हो रहा है ? आप सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं कह सकते हैं, नवीनगर का देखना चाहिये, आपको नीट छात्रा के साथ क्या हुआ देखना चाहिये ? आप एक घटना के बारे में कहकर जिम्मेवारी से आप नहीं भाग सकते हैं । देखिये, हमलोग सभी यहां हैं हम सभी को एक बात समझना चाहिये कि आज कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर हैं लेकिन जहां की बात कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी कहां थे उस समय, पता

कीजिये । सच्चाई से आपको बात रखनी चाहिये और इस तरह से टीका–टिप्पणी करने से नहीं होगा क्योंकि सवाल तो सबसे पूछा जायेगा ।

महोदय, क्या हो गया है पुलिस को जो हमलोग मोटिवेशन देख रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्या हो रहा है ? दौड़ा–दौड़ा कर माफिया उनको पीट रहा है । कहीं बालू घाट पर पीट रहा है, कोई कहीं पीट रहा है । यह तो हम सबके लिये चिंता का विषय है कि लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं । कल उनको पीट रहे हैं, कल आपको, हमको पीटेंगे । जब माफिया बढ़ेगा तो होगा क्या? यही सब होगा । इस पर हमलोगों को लगाम लगाने के लिये काम करना चाहिये । कार्रवाई के नाम पर देख लीजिये एफ0आई0आर0 कर देते हैं, जितने लोग हैं चिन्हित करके आप अननोन के नाम पर किसी को चिन्हित करके एफ0आई0आर0 कर देते हैं कि ये लोग शामिल थे लेकिन देखा है आपने कि यह हो क्यूं रहा है ? आप वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाइये, जो रिटायर पदाधिकारी हैं उनकी टीम बनाइये, पता कीजिये कि इसके पीछे जड़ में क्या है ? रूट काउज के पीछे जाइये और जड़ में कौन लोग हैं पता कीजिये और कार्रवाई कीजिये तो समझ में आता है लेकिन आप ऐसे ही जो किये जा रहे हैं ।

महोदय, हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, मैं खुद भी वैसे परिवार से आता हूं मेरे दादा स्वयं सिपाही थे, मेरे नाना भी सिपाही थे तो हम उनकी बात को समझते हैं । उनके कल्याण के लिये हमलोग क्या कर रहे हैं । ठीक बात है मॉडर्नाइजेशन के लिये आपलोग काम कर रहे हैं । आज भी एक सिपाही को साईकिल अलाउंस मिलता है, कोलोनियल टाइम का साईकिल आज भी चल रहा है । मोटरसाईकिल पर लोग चल रहे हैं, मोटरसाईकिल अलाउंस आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसको । आप किसी भी थाने में जाइये छत टपक रहा है, तो शौचालय की साफ व्यवस्था नहीं है, जहां वह डयूटी कर रहे हैं वहां क्या व्यवस्था चल रही है । इन सब चीजों को व्यवस्थित कीजिये । ऐसे तो नहीं चलेगा । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी इस चीज को समझ भी पायेंगे । पुलिसकर्मियों को निःशुल्क आवासन के नाम पर दैनिक विराम भत्ता से 25 परसेंट की कटौती की जा रही है । एक बैरक में, एक रूम में या कहीं भी व्यवस्था मंदिर में, गुरूद्धारा में, स्कूल में वे लोग रहते हैं, उनका 25 परसेंट कटौती किया जा रहा है और यह व्यवस्था 2021 से लागू किया जा रहा है। क्यों कटौती कर रहे हैं ? आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं उसके बाद कटौती कर रहे हैं । इन छोटी–छोटी चीजों को देखना चाहिये । एक तरफ जहां आप इतना खर्चा कर रहे हैं और इन छोटी–छोटी चीजों में कटौती कर रहे हैं। पहले बी0एम0पी0 था, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस । सभी लोगों की सुरक्षा में भी लगे हुये हैं । आप 2011 बैच के सिपाहियों को जो जिला बल से थे उनको आपने पी0टी0सी0 करा दिया लेकिन बाकी जो सशस्त्र पुलिस के

लोग थे, उनका अभी तक प्रमोशन, ग्रेड–पे नहीं हुआ है । वह 2008 से वहीं पर खड़े हैं जहां वह पहले खड़े थे । कुछ तो महोदय आपको समीक्षा करके करना चाहिये ।

महोदय हमलोग देखते हैं कि सिपाही का आजकल जो रिक्रूटमेंट हो रहा है । आप देखिये हमारा मानना है कि सिपाही को पहले तो एक तंदुरूस्त और बुलंद होना चाहिये । आप पहले व्यवस्था कीजिये कि पहले उनका फिजिकल टेस्ट हो फिर उसके बाद आप उसमें रिटेन एग्जाम लीजिये । अभी हाल के अखबार में छपा हुआ था कि सिपाहियों के अंदर बी0पी0, ब्लड शुगर, आंख में कमजोरी । इतना न कड़ा परीक्षा आप ले रहे हैं कि वह सब बीमारी का शिकार हो जा रहा है । जब तक वह लोग नौकरी में आता है तब तक आधा बीमारी में उसका आंख ही खराब हो जा रहा है तो वह कर क्या पायेगा ? उसकी अलग से व्यवस्था करनी चाहिये । महोदय, पहले फिजिकल टेस्ट हो उसके बाद रिटेन टेस्ट हो ।

महोदय, आप देख रहे हैं कि सारे लोग अपने बच्चों के लिये परेशान हैं, वैसे ही परेशान वे लोग भी होते होंगे । आपको एक व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो । आपका जहां पर पुलिस लाईन है वहां पर अच्छे स्कूल खुले हों, जहां पर वे अपने बच्चों का दाखिला करा सकें । सारे लोग परेशान रहते हैं , वह अपने परिवार को रख सकें, उनके आवासन की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो तो ऐसी व्यवस्था हमलोगों को करना चाहिये ।

महोदय, नित्य दिन नये–नये अपराध के तरीके, अपराधी शातिर होते हैं, उनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, यह हम मानते हैं और नित्य दिन वे नये–नये तरीके ढुंढते हैं । आज साइबर अपराध किस ढंग से बढ़ गया है । तो हमलोगो ंको साइबर अपराध के एक स्पेशल यूनिट का गठन करना चाहिये, जिसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रडेड लोग भी हों । क्योंकि यह एक ऐसा काम है कि जब तक टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड लोग नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है । अलग से आपको इसमें एक विशेष यूनिट रखना चाहिये जो साइबर अपराध पर काम करे । साथ में इसमें बैंकों को भी क्योंकि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं, वह सभी बैंक से संबंधित हो रहे हैं । बैंक के पदाधिकारी को भी इसमें चिन्हित कीजिये क्योंकि बैंक के मिलीभगत के बिना ये डेटा कहां से चला जाता है कि आपका किस बैंक में खाता है, बैंक के अधिकारी भी मिले होते हैं तो इस पर जब विशेष गहन हो तो बैंकों के साथ भी गहन चिंता करनी चाहिये कि साइबर अपराध बढ़ कहां से रहा है ।

महोदय, महिला आपने इतनी भर्ती कर लिया, बहुत अच्छी बात है । लेकिन जहां उनको ड्यूटी मिल रहा है उनको वहां शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं । एक निर्देश जारी होना चाहिये कि महिलाओं की ड्यूटी वहीं होगी

जहां उनको शौचालय की व्यवस्था है और अनहाइजेनिक चीजें जो मैं इस सदन में नहीं कह सकता हूं लेकिन जो हमारी महिला सदस्या हैं वे इस बात को समझ सकती हैं । जब तक यह व्यवस्था नहीं हो आप महिला को ड्यूटी नहीं करा सकते हैं, उनको परेशानी होती है ।

महोदय, सभी लोग यहां हैं जिनकी सुरक्षा में लोग लगे हुये हैं अधिकारी, जज, एम0एल0ए0, एम0पी0 सारे लोग । मैं एक विशेष आग्रह भी करूंगा कि अंगरक्षक के लिये एक अलग से यूनिट बनाये ताकि जो नित्य दिन जो समस्या होती है कोई अंगरक्षक किसी का किसी जिला में, किसी का किसी जिला में, कोई कहीं, इसकी समस्या खत्म हो ।

महोदय, नित्य दिन बिहार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप सिर्फ पुरानी बातों को याद करके जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं । यह घटना क्यों हो रही है ? इसके कारण को आप नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं । आप सिर्फ आंकड़ों के खेल के पीछे आपने आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आंकड़ों में भी जाइये कि आपका जो गैप है, आपका जो सैंक्शन पोस्ट है और जितने पुलिसकर्मी आपके पास अवेलेवल हैं उसका परसेंटेज क्या है ? क्या वह परसेंटेज बढ़ा है, वह गैप बढ़ा है या गैप घटा है ? इन सब चीजों को देखना होगा ।

महोदय, हमलोग नित्य दिन गांव में, देहात में जाते हैं । हम देखते हैं मोटरसाईकिल, ट्रैक्टर, समरसेबल, बिजली विभाग का ही ढ़ेरों सामान चोरी हो जाता है इन सब चीजों पर पुलिस बल को अपना विशेष ध्यान देना चाहिये ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 20.02.2026

...क्रमशः....

श्री राहुल कुमार : महोदय, दारू तो खैर मैं कह रहा हूँ कि दारू और बालू में जो लोग संलिप्त हैं, सारे लोगों को मालूम है, एक तो पुलिस को इससे अलग करना चाहिए और जो लोग हैं उन्हें चिन्हित कर के जो भी संपत्ति है, उसको सरकार को जब्त करना चाहिए । जब तक आप मैसेज नहीं देंगे तब तक कुछ होना नहीं है । महोदय, हमने अलग से बताया एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट के बारे में, एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट में प्रावधान है हमारे राज्य को उसमें पहले से सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से नशा का कारोबार बढ़ रहा है महोदय, आप कह रहे थे कि संरक्षण नहीं है, कैसे नहीं अपराधियों को संरक्षण है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, समय आपका समाप्त हो गया ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं टेबल पर रखना चाहता हूँ, यह घोसी थाना की घटना है, केस नं॰–21 / 2021, इस घटना में एक बच्चा, जिसका नाम गिरजेश कुमार था, उम्र–22 साल, पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है । अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम–सह–जांच पदाधिकारी जो थे, उन्होंने साफ लिख

कर दिया कि इस पदाधिकारी को दंडित करने के लिए लेकिन ये आज की डेट में डी॰एस॰पी॰ बन कर बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, 18 मिनट है, आप देख लीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी नाम आये हैं, करिश्मा जी का भी नाम आया है । आलोक जी पहले दो मिनट बोल चुके हैं ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, इन सब चीजों को देख कर, महोदय, इसको मैं टेबल पर रख देता हूँ और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और काम करे । साथ ही, एक लास्ट है महोदय । एक और एफ॰आई॰आर॰ नं॰–68/2026, दिनांक–22.01.2026 है, यह हमारे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दे दीजिये । राजू तिवारी जी, आपका 07 मिनट समय है।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करते हुए गोविंदगंज की जनता को, जनता के आशीर्वाद से और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद करते हुए आज गृह विभाग के अनुदान की मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है । विभाग की ईमारत तभी खड़ी होती है, जब सुरक्षा की नींव मजबूत हो जाती है । आज बिहार में जो कानून का राज दिखाई देता है वह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है । महोदय, अभी मैं सुन रहा था, गृह विभाग के प्रति हमारे विपक्ष के लोग कितने जागरूक हैं ? अभी आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महागठबंधन जो नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में है वह कटौती प्रस्ताव मूव ही नहीं किये, और नहीं तो मूव किये बहुजन समाजवादी पार्टी के एकलौते विधायक और उनको भी बोलें कि ये भी हमारे गठबंधन में हैं जबकि उन्होंने खड़ा हो कर स्पष्ट कह दिया कि हम अलग से लड़े थे और हमारे यहां आर॰जे॰डी॰ तीसरे नंबर पर थी तो यह इनका दिखाता है कि कानून के प्रति कितना इनका सम्मान और कितना इनका क्या है । अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ जो वे बोले हैं । अध्यक्ष महोदय, तो....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आपके नेता जो बोले हैं कि ये हमारे गठबंधन के साथी हैं, उस पर मैं बोला हूँ, आपके गठबंधन से वे थोड़े ही न लड़े थे और उन्होंने खुद

बोला है कि हम अकेले लड़े थे । सत्य नहीं सुनते हैं, दिक्कत यह है कि ये खड़े हो जाते हैं, समय मेरा बर्बाद करते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, बैठ जाएं ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कानून का मजाक उड़ाना और....

(व्यवधान)

बैठिये, महोदय, ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं और इनके बारे में भी हम बता देते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, ये हमारे नेता की कृपा से पहली बार सदन में आयें, कई बार बोल चुके हैं । कानून का मजाक उड़ाना और बिहार के, देश के महापुरुषों का अपमान करना इनकी फितरत है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । महोदय, मैं चंद लाईन सुशासन के राज में बोलना चाहता हूँ–

''कानून की लौ से अंधेरे को मिटाया हमने,
जो डर का सौदा करते थे उन्हें समझाया हमने,
जिसके दौर में सड़कों पर खौफ का पहरा था,
आज उसी बिहार में भरोसा लौटाया हमने ।''

महोदय, आज...

(व्यवधान)

अब देखिये, बीचे में ही बोलती हैं । महिला हैं, आदरणीय हैं । अध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान हमारे साथी माननीय विधायक सर्वजीत जी ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में कहा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अनीता जी, बैठे–बैठे मत बोलिये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि आज बिजली चारों तरफ है और पोस्टमार्टम बिजली की, आज उन्होंने इसी सदन में बोला है कि वह दौर था जब ढिबरी और लालटेन में पोस्टमार्टम होता था, इसी सदन में उन्होंने स्वीकार किया, ये अंदर से स्वीकार करते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, बैठिये । बिना अनुमति के मत बोलिये। माननीय सदस्य श्री संदीप जी, आपको मौका मिलेगा, बैठिये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, ये इनकी फितरत है, ये लोग गलबजिया करते हैं, ये लोग सिर्फ गलबजिया करते हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, बैठ जाएं । सर्वजीत बाबू, हर बात पर खड़े मत होइये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, गलबजिया में इनसे कोई जीत नहीं सकता है चूंकि ये लोग, तो महोदय, इस तरह से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये । सभी दलों को मौका दिया जा रहा है ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आज गृह विभाग के आंकड़े बताते हैं कि स्पीडि ट्रायल के माध्यम से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अनीता जी, शांति बनाये रखिये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, 23 हजार अपराधियों को सजा दी गई । हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, सब चीज में । हाँ, घटना घटती है, सरकार इसके लिए, घटना घटती है, हमारी सरकार उसका उद्‌भेदन भी तुरंत करती है, कोई बचता नहीं है इस राज में, ये नीतीश कुमार के सुशासन का राज है, इसमें कोई अपराधी बच नहीं सकता है । इन लोगों के राज में क्या होता था, यह बताने की आवश्कता नहीं है । आज चाहे भ्रष्टाचार पदाधिकारी भी हमारे पकड़े जाते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ती है, उनकी संपत्ति भी जब्त करती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणविजय जी, सुनना चाहिए, आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, तो कानून सब के लिए है । कानून का कभी ये लोग मान–सम्मान तो किये नहीं तो इसके ऊपर नहीं जाना है । आज सभी थानों को सुसज्जित किया है, गाड़ी से, उनके भवन से, पुलिस वालों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार कर रही है । आज राज्य में पुलिस बल का कुल स्वीकृत बल है 02 लाख 29 हजार से अधिक है जबकि फरवरी, 2026 माह में, 01 लाख 25 हजार पुलिस कर्मी कार्यरत थे, राज्य सरकार ने सभी पुलिस बल को मजबूत किया है और सभी अपराधियों के खिलाफ तो पुलिस पड़ी रहती है, उनको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता । महोदय, सीधे मैं चाहता हूँ, आज लगभग एक हजार ज्यादा थाने बन गए हैं तो ये कानून का राज स्थापित है, सुशासन का राज स्थापित है । मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले पुलिस की कमी थी, अपराध ज्यादा था । आज पुलिस मजबूत है और अपराध नियंत्रण में है । एक चीज साईबर में मैं अपने मंत्री जी को कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे विधान सभा में छठ के दरम्यान कुछ बाहर के लोग आये थे और उन्होंने खरीदारी की, साइबर क्राईम में मेरा अपना सुझाव होगा कि जो खरीदारी किया और उसके बाद वहां पर उसके एकाउंट में मुकदमा लग गया तो मुकदमा लगने के बाद क्या हुआ कि जहां–जहां खरीदारी किया था, सब के एकाउंट को बंद कर दिया गया और साइबर वालों के यहां हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, दुकानदार छोटे–छोटे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि साइबर में अपना आवेदन भी दिया लेकिन आवेदन के बाद आज तक पता करने पर पता चलता है कि

मेल साइबर के डी॰एस॰पी॰ कर दिए हैं लेकिन वहां से कुछ नहीं, उनका एकाउंट बंद है इसलिए थोड़ा, मैं अपने मंत्री जी से, अपने पदाधिकारियों से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं आखिर में एक बात और बोलना चाहता हूँ । सुशासन के राज में निश्चित रूप से अपराध ही हमलोगों की इच्छाशक्ति, आज चुनाव में हमलोग जीत कर आये हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज सुशासन का राज है । आज भी लोग उस दौर को याद कर कांपने लगते हैं महोदय। आखिर में एक चंद लाईन है–

''सत्ता नहीं सेवा है, ये सोच हमारी है
सुरक्षित हर नागरिक हो, ये जिम्मेदारी हमारी है,
गृह विभाग की मेहनत का नतीजा देखो,
आज बिहार की बदलती हुई तस्वीर हमारी है ।''

महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं समर्थन करता हूँ इसका ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

(व्यवधान)

हर बात में, इस पर चर्चा मत कीजिये, बहुत विषय आ गया है । बोलने दीजिये। नाम पुकार दिये हैं । प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग पर चर्चा है और जिस तरीके से बिहार में पिछले कई महीनों से छोटी बच्चियों के साथ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संदीप सौरभ जी, आप बोलिये । संदीप सौरभ जी, आप जारी रखिये । आलोक जी, आपसे आग्रह है, आप वरीय सदस्य हैं हर बात पर खड़े मत होइये ।

टर्न–17 / अंजली / 20.02.2026

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से बिहार में छोटी बच्चियों के साथ हिंसा, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हमें लगता है कि केवल वह कानून का मामला नहीं है, बल्कि देश की सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं और उनके जो आइकॉन है उनकी पूरी विचारधारा, पूरी बनावट उस तरह की है । देश के प्रधानमंत्री के गुरू, वे खुद कहते हैं कि गोलवलकर जी हैं । बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, पेज नंबर–104 में, उसमें लिखा हुआ है, आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण और पुरुषों के वर्चस्व से उनकी मुक्ति का बड़ा शोर है । इस तरह जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद की तरह एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है । महोदय, हमें लगता है कि पुरुषों की बराबरी करना, एक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ना, क्या यह कारण है देश के अंदर, बिहार के अंदर छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हत्या, बलात्कार की

घटना होना । महोदय, एक बड़ी घटना हुई है अभी दुनिया के मानचित्र में, जेफरी एपस्टीन, उनकी फाइल लीक हुई और वह सब जगह पब्लिक हो गया, दुनिया में बड़ा हाहाकार है । देश के दो शीर्ष व्यक्ति...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, आधा मिनट समय दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार । श्री अजय कुमार ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, देश के पेट्रोलियम मंत्री...

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार जी नहीं हैं ।

श्री संदीप सौरभ : देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी उनका....

अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, यह कोई बात नहीं है । सरकार को पसंद नहीं है तो वह बात नहीं कहेंगे...

अध्यक्ष : समय निर्धारित है संदीप जी ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, तीन घंटे का डिबेट चलेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समझदार हैं । एक मिनट समय था, वह पूरा हो गया । अजय बाबू, बोलिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, आधा मिनट समय दिया जाए ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अजय बाबू नहीं बोलना चाहते हैं, तो बता दें । श्री आई0पी0 गुप्ता ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर में जो है उसको लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बोल दीजिए । आप शुरू कीजिए । हो गया । बोल लिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, गृह विभाग के कटौती पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी दोनों पक्ष से जब बोला जाता है, खासकर उधर से, तो वर्ष 2005 से पहले की चर्चा करते हैं, आज चर्चा हमें क्या करना है ? हमें तो चर्चा करना है पीछे पांच साल में हमने क्या किया या फिर 2005 से लेकर आज तक क्या किया और जब उस पर हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं, वर्ष 2015 में किनकी सरकार थी एन0डी0ए0 की सरकार थी, 2025 तक एन0डी0ए0 की सरकार थी और एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट क्या कहती है, वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक में 80 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई । सवाल इस पर होना चाहिए, इस पर चर्चा किए बिना आप इधर–उधर भटक रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस पर विमर्श करना चाहिए कि अदालत की लंबी प्रक्रिया कितनी है कि आप किसी अपराधी को सजा नहीं दिला पाते । मैं कोट करना चाहता हूं कि एक केस नंबर–13/2002 हमारी पार्टी के एक बड़े नेता रामनाथ महतो की

हत्या हुई थी, आज कितने साल हो गए, 24 साल हो गए, अभी तक उनके सभी अपराधी को ट्रायल नहीं कराई है सरकार, यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह एन0डी0ए0 गवर्नमेंट जो आज 20 साल से है इनकी जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ । आई0पी0 गुप्ता जी ।

श्री अजय कुमार : मैं आपसे सिर्फ तीस सेकंड ले रहा हूं । मैं आपको कह रहा हूं साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम का एफ0आई0आर0 करने में बहुत पेंचीदगी है और उसका उद्‌भेदन करना और भी ज्यादा पेंचीदा है । आज जिस तरीके से नक्सल समस्या के बारे में कह रहे हैं कि समाप्त हो गया, नक्सल समस्या ऐसे होगा ? जब तक बेरोजगारी रहेगी...

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता जी ।

श्री अजय कुमार : जब तक भुखमरी रहेगी और जान लीजिए, तब तक जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर शोषण रहेगा नक्सल की समस्या बनी रहेगी, इसको आप नहीं रोक सकते ।

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,...

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये कह रहे हैं कि ऐसे समाप्त हो जाएगी, तो चुनौती दे रहे हैं, कुछ मानसिकता से स्पष्ट नहीं हो रही है महोदय । महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता जी । आप अपना भाषण जारी रखिए । समय मात्र एक मिनट है, ध्यान रखिएगा ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर, सामने गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं । यह कहानी है उस बच्ची की, जिसको 3 मई को उसके घर से उठाकर मक्का के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे, 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसकी मोटरसाइकिल को पकड़कर गांव वाला वहीं रखता है और भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यू0डी0 केस बना देती है, उस लड़की को फिर दूसरे दिन आकर मार देता है और आत्महत्या की शक्ल देता है । उसकी गलती सिर्फ यह है कि वह एक तंतवा की बेटी थी, उसकी गलती है कि उसके मां–बाप गरीब हैं, उसकी गलती यह है कि उसके मां–बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते । मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डी0जी0पी0 साहब के यहां, एस0पी0 साहब के यहां कहां–कहां चिट्ठियां नहीं लिखी हुजूर, आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, यह कहानी उस रिपा की नहीं है जो 15 वर्ष की थी, पता नहीं कितने बच्चे होंगे । आज मुझे लगता है कि मैं तंतवा में जन्म लेकर गुनाह किया है । हुजूर, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह

मंत्री जी । वह मेरे घर पर आकर परसों इतना रो रही थी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए हुजूर ।

अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए । श्री सतीश कुमार सिंह यादव ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता, आदरणीय बहन मायावती जी का एवं रामगढ़ की देवतुल्य जनता का और महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश की मात्र छः राष्ट्र पार्टियों में से एक राष्ट्र पार्टी है और हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी देश में आयरन लेडी के नाम से विख्यात हैं और हमने चुनाव न एन0डी0ए0 के साथ, न महागठबंधन के साथ हमारी पार्टी अकेले अपना चुनाव लड़ी थी ।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । महोदय, काउंटिंग के दिन रात को 11 बजे हमें प्रमाणपत्र मिला, उसके पहले वहां पर मोहनिया थाना केस संख्या–926/25 में 151 लोगों पर नामजद और 1000 अज्ञात और दूसरा, मोहनिया केस संख्या–927 में 197 लोगों को ज्ञात और 1000 अज्ञात और उसी तरह दुर्गावती थाना में उसी दिन 355/25 में 50 लोग अज्ञात और 200 लगभग हमारे क्षेत्र के नौजवानों के 400 लोगों के नामजद और 2200 लोगों का अज्ञात एफ0आई0आर0 है ।

अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें । श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, एक मिनट दिया जाए । इसमें अधिकतर पढ़ने वाले लड़के हैं । महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लड़कों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, रात के अंधेरे में पुलिस ने सिर्फ यह कहकर कि सी0सी0फुटेज से इन लोगों को लोकेट किया गया है । मात्र 10–12 घंटे में पुलिस ने, उसमें मेरे जो काउंटिंग एजेंट थे, जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में थे उनके नाम से भी एफ0आई0आर0 दर्ज है ।

अध्यक्ष : सारी बातें आ गईं । श्रीमती ज्योति देवी । अब बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : मैं आग्रह करूंगा कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक विधायक...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : ज्योति जी, बैठ जाइए, मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये कटौती प्रस्ताव के मूवर हैं, ये भी एक नई परंपरा हो गई कि प्रस्ताव हम अभी मूव कर दिए और इनको बोलने का पूरा समय उसी समय आपको देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रस्ताव अभी मूव कर लें और बोलेंगे उस समय । इनको तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए । उसमें भी बार–बार कह रहे हैं बहुजन समाजवादी

पार्टी के हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं और कट मोशन के मूवर हैं, इनका आज जो कटौती प्रस्ताव पर विमर्श है, वह इन्हीं के प्रस्ताव पर विमर्श हो रहा है, इनको तो शुरू में ही विस्तार से बोलना चाहिए था । हम तो सिर्फ आपके ही मदद में बोल रहे हैं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, नए–नए हैं, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है ।

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि बाराचट्टी के दलित, बाहुल्य, पहाड़ी क्षेत्र एवं वंचित क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रतिनिधि बनकर 2026–27 के बजट पर गृह विभाग एवं विनियोग विधेयक पर अपनी बात कहना चाह रही हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग का बजट केवल पुलिस की संख्या भवनों का हिसाब नहीं होता, यह तय करता है कि गरीब कितनी जल्दी न्याय पाएगा, आदिवासी कितनी निर्भयता से थाने जाएगा और दलित महिला कितनी सुरक्षित महसूस करेगी । नियुक्ति, बेरोजगार युवाओं को अवसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में यह स्पष्ट दिखता है कि सरकार ने सुरक्षा और रोजगार दोनों को साथ–साथ देखा है । गृह विभाग में पिछले 2 वर्षों में 37931 पदों पर नियुक्ति पूरी हो चुकी है । 26859 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और आगामी वित्तीय वर्ष में 25134 नए पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है । यह आंकड़े खासकर ग्रामीण, दलित और आदिवासी युवाओं की उम्मीद का संदेश है, क्योंकि पुलिस बल में भर्त्ती उनके लिए सम्मानजनक रोजगार का बड़ा माध्यम है । थाना सृजन दूर–दराज क्षेत्रों तक कानून की पहुंच माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होती है थाने की दूरी ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / पुलकित / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती ज्योति देवी : इस बजट के अंतर्गत राज्य में 260 ओ0पी0 को थाना बनाया गया है, 24 रेल ओ0पी0 को रेल थाना बनाया गया है, और 44 नए साइबर थाना और 28 नए यातायात थाना सृजित किए गए हैं । यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, यह पहाड़, पठार और जंगल में बसे लोगों तक कानून को पहुंचाने का प्रयास है ।

पुलिस भवन और सम्मानजनक पुलिस सुरक्षित समाज– माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस तभी संवेदनशील बनती है जब उनकी अपनी कार्य स्थिति मानवीय हो । इस बजट में थाना भवन, महिला थाना, थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सह आवास, महिला एवं जवान बैरक, तथा पटना में ई0आर0एस0एस0 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली भवन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है । यह निवेश सीधे–सीधे सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

डायल 112 ई0आर0एस0एस0 गरीब की पहली पुकार– माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गरीब के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है डायल 112 । अब तक 51 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सहायता पहुंचाई गई है। यह प्रतिदिन औसतन 6,000 कॉल त्वरित कार्रवाई हो रही है । 4.30 लाख से अधिक मामले महिला घरेलू हिंसा और बच्चों से जुड़े हुए हैं । महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ, पुलिस की अनगिनत अच्छी नीतियां हैं, अच्छी कार्यशैली है काम करने की, जिससे समाज अपना सुरक्षित है । मैं केवल अपने माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे जवान जिनकी भी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको सम्मानजनक जगह मिले, उनके रहन–सहन की अच्छी व्यवस्था हो । जहां भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उनकी दुर्दशा अच्छी नहीं रहती है । हमारे विपक्ष के भाई भी कह रहे थे कि जब भी हम लोग देखते हैं तो उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो मानिए कि वे हमारे परिवार के ही अंग हैं, उन पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग पर मैं बहुत सारी बातें लिखकर लाई थीं, लेकिन मेरा तो बोलने का आपने समय बांधा है, इसलिए मैं इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना देने के लिए आग्रह करती हूँ ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार सिंह ।

श्रीमती ज्योति देवी : दूसरा चीज महोदय, थोड़ा सा समय दिया जाए । मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहती हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में मैंने एक तारांकित प्रश्न डाला था, हमारे गृह मंत्री जी का जवाब आया कि हमारे गांव में विकट परिस्थिति है कि सेना के द्वारा गोला गिराए जाते हैं, उसमें गंतव्य तक जवाब मिला, गंतव्य पर ही गिरता है । लेकिन मैं अपने गृह मंत्री जी से आदर सहित आग्रह करना चाहती हूँ कि आपको जिन्होंने भी यह सूचना दी है, वह गलत दी है । उदाहरण के स्वरूप हम कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष : अब समाप्त करियें ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, हम यही कहना चाहते हैं उदाहरण के स्वरूप कि जो भी है, हम इसमें साक्ष्य सब दिए हुए हैं, अगर जो गलत रिपोर्ट गृह विभाग से संबंधित दिये हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, एक बात और कहना चाहती हूं इन्होंने कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, जरूर ।

श्री आलोक कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकार के गृह विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बोलने के लिए

खड़ा हुआ हूँ । मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । इस बजट में गृह विभाग के माध्यम से कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

बिहार का सबसे बड़ा परिवर्तन भय से विश्वास तक – माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार ने पिछले दो दशकों में सबसे बड़ा बदलाव सड़क या भवन में नहीं, बल्कि सुरक्षा और शासन के माहौल में देखा है ।

वर्ष 2005 के पहले का बिहार – अपराध का बोलबाला, अपहरण उद्योग, महिलाओं का असुरक्षित जीवन और आम नागरिक का डर । वह समय था जब लोग कहते थे शाम होते ही घर लौट जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज बिहार बदल चुका है । आज बिहार में सरकार का संदेश स्पष्ट है, कानून का राज है, अपराध का नहीं । यह परिवर्तन एन0डी0ए0 सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । आज पूरे बिहार की तरफ से और दिनारा विधान सभा की भगवानरूपी जनता की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और एक सदन के माध्यम से आपके आदेशानुसार गीता का श्लोक मुझे याद आया –

''परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।''

सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्म वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आप जैसे सम्राट प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं ।

माननीय गृह मंत्री जी, आपको विपक्ष के द्वारा जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया, वह बहुत ही गलत था । आज बिहार में अतिक्रमण की जहां भी व्यवस्था थी, आपके माध्यम से बहुत ही शहर मुक्त हुए हैं और बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हर गांव में एक क्रांति लाई है–डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज डायल 112 नागरिकों के लिए सुरक्षा की नई गारंटी बन चुका है । अब तक लाखों लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई गई है । अब तो गांवों में कहीं वाद–विवाद कोई झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति के पास 112 नंबर रहता है और डायल करके तुरंत फोन करते हैं और तुरंत वहां पुलिस पहुंचती है । महिलाओं और बच्चों की सड़क दुर्घटनाओं में यह सेवा जीवन रक्षक साबित हो रही है । यह दिखाता है कि बिहार अब रिएक्टिव नहीं, प्रो–एक्टिव पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है ।

महिला सुरक्षा और सशक्त सुरक्षा की पहल– माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, यह सामाजिक सम्मान का विषय है । इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष सशक्त सुरक्षा

पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अकेले महिलाओं तक तेज सहायता पहुंचाना है । यह नए बिहार की संवेदनशील सरकार का परिचायक है ।

फॉरेंसिक और न्यायिक प्रणाली को मजबूती– माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध पर नियंत्रण केवल पुलिस से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जांच और न्यायिक मजबूती से होता है । इस दिशा में राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफ0एस0एल0) भवनों का निर्माण, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कैंपस की स्वीकृति, यह कदम बिहार को अपराध जांच में नई क्षमता देंगे ।

भर्ती और पुलिस बल का विस्तार– माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में हजारों पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है और आगे भी प्रस्तावित है । साथ ही नए थानों का निर्माण, साइबर थाना विस्तार, पुलिस भवनों का आधुनिकीकरण, यह सब राज्य सुरक्षा को मजबूती करेगा ।

मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रत्येक थाना स्तर पर रिस्पांस टाइम ऑडिट लागू हो ताकि डायल 112 जैसी सेवाएं तेज और प्रभावी बनें । साइबर अपराधी बढ़ रहे हैं, इसलिए हर जिले में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को और मजबूत किया जाए । महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला हेल्प डेस्क को पंचायत स्तर तक ओवररीच के रूप में बढ़ाया जाए ।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अंत में, समापन में मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि मेरे क्षेत्र दिनारा विधानसभा में मां भलनी भवानी धाम है, वहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं और कई वहां शादी भी होता है, तो वहां एक ओ0पी0 की व्यवस्था की जाए । दूसरी, मेरा मांग है कि रोहतास जिले में विक्रमगंज में अवैध बूचड़खाना को तुरंत बंद करा दिया जाए । जब हम लोग रोड से गुजरते हैं, तो गौ माता, जिसको गौ माता हम लोग बोलते हैं, सामने बांधकर और उसकी हत्या होती है । इसलिए अवैध बूचड़खाना को रोहतास में, विक्रमगंज में तुरंत बंद कर दिया जाए ।

अंत में मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से, गृह विभाग की अनुदान मांगों पर समर्थन करता हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री आनन्द मिश्र ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह विभाग के 2026 बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर देने हेतु आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, द्वेय उपमुख्यमंत्री जी का, हमारे सचेतक जी तथा सदन को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, साथ ही, अपनी बक्सर की जनता के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में गृह विभाग के बजट अनुदान के समर्थन में खड़ा होते हुए मैं केवल एक विधायक के रूप में नहीं,

बल्कि उस वर्दी के अनुभव के साथ बोल रहा हूँ जिसने आई0पी0एस0 ऑफिसर के रूप में कानूनी व्यवस्था संभाली थी । संकट में लोगों की आंखों में भय भी देखा है और न्याय मिलने के बाद उन्हीं आंखों में विश्वास भी देखा है । आज जन प्रतिनिधि के रूप में उसी व्यवस्था को नीति के स्तर पर सशक्त होते देख रहा हूँ ।

(क्रमशः)

टर्न–19 / हेमन्त / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री आनन्द मिश्र : महोदय, मेरे पास दोनों दृष्टिकोण हैं, पुलिस का भी और जनता का भी। इसलिए जब मैं इस गृह बजट को देखता हूं, तो मुझे यह सिर्फ दस्तावेज नहीं लगता, यह 13 करोड़ बिहारवासियों के विश्वास की सुरक्षा का संकल्प प्रतीत होता है।

अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में होता है, दुर्घटना, अपराध, हिंसा या हेल्पलेसनेस, तब वह सबसे पहले पुलिस या मेडिकल सेवाओं की ओर ही देखता है। इसलिए इन दोनों सेवाओं में संवेदनशीलता, पेशेवरता, करुणा और निष्पक्ष आचरण अनिवार्य गुण हैं। कानून की कठोरता और मानवीय व्यवहार का संतुलन ही शायद सच्ची पुलिसिंग की पहचान है। महोदय, यह बजट बिहार पुलिस को मॉडर्न और अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई0आर0एस0एस0 112, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज का विस्तार, वूमेन सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पुलिसिंग, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सिक्योरिटी को गवर्नेंस का मूल आधार मानती है। यह बजट सुनिश्चित करते दिखता है कि "Crime is evolving, police must evolve faster." आज अपराध का स्वरूप बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, ड्रोन सर्विलियंस, ब्लॉकचेन एविडेंस मैनेजमेंट, स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे टूल्स पुलिसिंग को नई दिशा तय करते दिख रहे हैं। इसलिए ट्रेनिंग, ड्रिल, टर्न आउट और इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को भी उसी गति से विकसित करना होगा और यह बजट इसी दिशा में एक मजबूत पहल है।

अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में पुलिसिंग की कई प्रभावी पहल अब देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा एंटी माफिया ऑपरेशंस के माध्यम से संगठित अपराध के विरुद्ध स्पष्ट संदेश है। गुजरात ने टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप की जवाबदेही बढ़ाई। आसाम जैसे इनसर्जेंसी अफेक्टेड राज्य तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों में इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग

और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के जरिए कठिन परिस्थितियों में भी शांति स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए बिहार पुलिस भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है और यह बजट इन्हीं इनिशिएटिव्स को समर्थन और बढ़ावा देता हुआ समझ में आ रहा है। महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक तो है ही, साथ ही, महिला थाना, फ्रंट लाइन पर महिला अधिकारी, पेट्रोलिंग से लेकर नेतृत्व तक सक्रिय सहभागिता। आज बिहार की बेटियां सुरक्षा की पहचान बन चुकी हैं। वे सुरक्षा की सिर्फ मांग नहीं कर रही, बल्कि स्वयं सुरक्षा का नेतृत्व कर रही हैं। यह बदलाव दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सकारात्मक और दृढ़ नेतृत्व की सराहना करता हूं जिनके मार्गदर्शन में पुलिसिंग में यह सशक्त परिवर्तन संभव होता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, मैं इस सदन से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस ने अतीत में भी नक्सलिज्म, संगठित हिंसक गुटों और तथाकथित दबंग प्रवृत्तियों जैसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसलिए उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें सकारात्मक समर्थन दें, संसाधन दें और जनहित में उनके कार्यों को सशक्त करें। इतिहास यह भी बताता है कि गलत राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक शिथिलता ने ही उस दौर को जन्म दिया जिसे अनफॉर्चुनेटली आज जंगल राज कहा जा रहा है। इसलिए आज हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को परिवर्तन में साझेदार बनाएं। उन्हें पुरानी जड़ हो चुकी कार्यप्रणाली से सीमित न रखें, बल्कि बिहार के रूपांतरण में अग्रिम शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का भी अवसर दें। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रांग पुलिस, जब मैं भी था, तब स्ट्रॉन्गली करता था, तो लोग कहते थे, पुलिस स्टेट बन रहा है। तो ऐसा है नहीं। स्ट्रांग पुलिस का अर्थ कभी भी पुलिस स्टेट नहीं होता। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो नागरिक की संरक्षक हो, भय का कारण नहीं। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, ''परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्।'' ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल और नॉलेज ऑफ लॉ जितने आवश्यक हैं, शायद उतने ही जरूरी अब सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कम्युनिकेशन और सिटीजन इंटरेक्शन भी हैं। कंसाइंसियस पुलिस, यानी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करना, यह आज की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब, इस बात पर ध्यान दें, इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब अवैध ताकतें कानून को चुनौती दें, तब पुलिस को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस

के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है और यह बजट इन सब बातों के लिए पथ–प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है।

(इस अवसर पर सभापति, श्रीमती ज्योति देवी ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, बिहार पुलिस को ऐसे अधिकारी चाहिए, जो हैं भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें। जो अपने अधीनस्थों से अधिक परिश्रम करने का साहस रखें और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोरल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हों। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना और संरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति – ये केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिस कर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं, बल्कि सर्विस से है। Police is not a job, Police is a service. यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देना चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं, जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। ए0आई0 ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। हम सब इस परिवर्तन के सहभागी हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस टीम का हिस्सा हैं, जो बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। यह 20,132 करोड़ का गृह बजट इसी नए युग की तैयारी का उद्घोष है।

माननीय सभापति महोदया, आज हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। क्राइम फ्री बिहार, सेफ बिहार, कॉन्फिडेंट बिहार, जनता का राज, सुशासन का मॉडल और न्याय आधारित व्यवस्था। इसी दिशा में यह गृह बजट एक सशक्त और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं, हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस बजट का समर्थन करें। यह किसी एक दल का बजट नहीं है। यह हर किसान, हर मजदूर, हर छात्र और हर मां–बहन की सुरक्षा का

बजट है। मजबूत गृह बजट पुलिस की ताकत नहीं, यह जनता की सुरक्षा की गारंटी है। मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा, दो–चार सजेशंस देने के लिए कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वह फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वह फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहां आकर किसी का पी0एस0ओ0 बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है, वैसा स्पेशलाइज कैडर, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, स्पेशलाइज ब्रांच को प्रमोट किया जाए, मुझे लगता है पुलिस और बेहतर उसमें काम कर पाएगी। साथ ही, मैं चाहूंगा एक बात और नजर में लाने की, माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो एफआईआर होती हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना, ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता है। लड़का बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वह पुलिस की परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन थी, उसने उस पर एक एफआईआर कर दी। तो हमें लगता है कि एक बार इसको एज ए पॉलिसी लेवल पर हमें देखना चाहिए कि FIR should not be a reason for stoping someone to join. उसके बाद अगर वह चार्जशीट होता है, ट्रायल पर जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पर डिसमिस कर सकते हैं। जरूरत होने पर उसकी पुरानी सारी रिकवरी भी कर सकते हैं। इस पर काइंडली ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि ये जो हमारे जुरिस्डिक्शन है कि एक प्रखंड का जुरिस्डिक्शन, सर्कल का जुरिस्डिक्शन, थाने का जुरिस्डिक्शन, वह एक साथ मैच नहीं करता और इसके लिए जमीन पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस पर भी कहीं न कहीं जुरिस्डिक्शन को एक साथ लाने की मुझे जरूरत लगती है। इसके साथ मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जब भी आता जाता रहता हूं सरदार पटेल भवन के सामने से, वहां तिरंगा के लिए एक बहुत बड़ा पोल गड़ा हुआ है और उस पर तिरंगा नहीं दिखता। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि उस पर तिरंगा हो, सरदार पटेल भवन की भी वह शान बढ़ाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आने–जाने वाले जितने युवा हैं, जो पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्या करिश्मा जी।

श्रीमती करिश्मा : सभापति महोदय, धन्यवाद। जब हम बिहार की बात करते हैं, तो प्रायः मैंने देखा है सत्ता पक्ष के लोग अतिशयोक्तियों में, अलंकारों में एक सुनहरा

भविष्य या पता नहीं पास्ट क्या, कहीं कोई तथ्य नहीं होता। ये बात करते हैं नर संहारों की। वह कौन सी सरकार है जिसने साक्ष्य के अभाव में उन दरिंदों को छोड़ दिया ? तो पुलिसिंग का मतलब ये नहीं, उसका एक मेजर पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। वह कौन–सी सरकार है जिसने उन दरिंदों को, नर संहार के दोषियों को छोड़ दिया ? साक्ष्य का अभाव क्या होता है ? आपका पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था ? आपने क्या किया ? आप सरकार में थे, आप सत्ता में थे, तो आपने क्या किया ? मैं कोई रिटोरिक बात नहीं करूंगी। मैं अतिशयोक्तियों और मैं अलंकारों में बात नहीं करूंगी। मैं धरातल की सच्चाई पर बात करूंगी।

(क्रमशः)

टर्न–20 / संगीता / 20.02.2026

...क्रमशः...

श्रीमती करिश्मा : सभापति महोदया, एक रिपोर्ट आयी है, India Justice Report 2025 में । मैं कुछ उसके डेटा पेश करूंगी क्योंकि मुझे धरातल पर रहना पसंद है । States per capita spend on police per person, जो हमारा राज्य है, जो पुलिस विभाग है वह per person कितना खर्च है तो उसमें Bihar ranks last among large and mid-sized states, अभी मैं जो भी डेटा कोट करूंगी, वह अठारह mid and Large sized states उनकी रैंकिंग है, उसके आधार पर मैं डेटा पेश कर रही हूं आप सभी के सामने । अगर ट्रेनिंग बजट यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारा जो बजट है, प्रावधान है पुलिस के लिए, होम डिपार्टमेंट के लिए उसमें Bihar ranks second last among sixteen large and mid-sized states with score of 1.08, आप सोचिए हमारा कितना डेसिमल परफॉर्मेंस है ? Bihar ranks eleventh among eighteen mid in large sized states in constable vacancy, कॉन्सटेबल वैकेंसी की भी बात करें तो उसमें 18 राज्यों में बिहार का पोजिशन eleventh है । अगर हम बिहार की बात करें, तो out of eighteen States Bihar ranks seventeenth out of eighteenth, that is second last ...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : कृपया एक मिनट में समाप्त करें । अब आपके पास एक मिनट समय है ।

श्रीमती करिश्मा : in officers vacancy in civil and DARP. Bihar ranks second last in administrative staff vacancy in forensics, Scientific staff जैसे हमारी एक माननीय सदस्य ने भी की forensics की बात की तो Scientific state vacancy in forensics Bihar उसमें भी सेकेंड लास्ट है बिहार । Percentage of schedule caste officers against reserved quota Bihar उसमें भी

sixteenth Position पर है तो कहां पर है सबका साथ और सबका विकास ? Population per civil police जो हम सर्व करते हैं उसमें Bihar ranks lowest at the bottom. वह खड़ा है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपका समय हो गया ।

श्रीमती करिश्मा : और जब हम बात करते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : श्री रितुराज जी, श्री रितुराज जी अपना पक्ष रखें ।

श्रीमती करिश्मा : श्री चिराग पासवान जी ने पता नहीं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : श्री रितुराज जी ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही साथ मैं आसन का और एन0डी0ए0 की वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं । बिहार की महान जनता और घोसी की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि आज मैं उनकी आवाज बनकर सदन के पटल पर अपनी बात को सरकार की तरफ से रख सकूं । महोदया, मगर उससे पहले मैं एक गंभीर विषय पर बोलना चाहता हूं कि सदन में सिर्फ सरकार का ही नहीं, विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और सबसे पहले यहां पर बैठे हुए सभी विधायकगण भी कई दिनों से यह बात जानना चाह रहे होंगे कि आज इतना महत्वपूर्ण विषय है और हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं गायब हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : कृपया दो से तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री रितुराज कुमार : महोदया, पिछले 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम काल रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है क्योंकि उससे पहले बिहार की सुरक्षा व्यवस्था या तो गैर–प्रशासनिक या गैर–प्रशासनिक सरकारी माध्यमों से होती थी । ऐसा लगता था कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पटना सचिवालय और पुलिस थानों के बाहर से चलती थी । सभापति महोदय, आज मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं क्योंकि समय की मांग है, विपक्ष के लोगों की याददाश्त को वापस लायी जाए । हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बोला तो उसका उत्तर सुनने के भी तैयार रहें । इनका जो इतिहास रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है...

(व्यवधान)

सुन लीजिए पहले । इस विचारधारा का एक हिंसक रूप ने समाज को कैसा वैमनस्य फैलाया था, ये शब्दों में पिरोना आसान नहीं है और ऐसे ही यहां नहीं रूके हैं, आज भी कई कॉलेज के कैंपसों में डफली बजाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बात–बात पर ये लोग आरक्षण...

(व्यवधान)

सर, आप ही कह रहे थे कि ऑर्डर होना चाहिए, आप ही कल कह रहे थे ऑर्डर होना चाहिए सदन में...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य आप थोड़ा धैर्य रखें, अपने समय में ही बात करें। बोलने दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री रितुराज कुमार : बात–बात पर ये लोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए, उनको बोलने दीजिए ।

श्री रितुराज कुमार : सुन लीजिए, वह भी सुन लीजिए क्यों बोल रहे हैं । बात–बात पर आपलोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला था तो आपने किन लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाया था । आज हमारे मुख्यमंत्री को जब मौका मिला तो उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को मंत्री बनाया...

(व्यवधान)

और जब इन्हें और इनकी योग्यता पर बात आती है तो 40–40 साल डफली बजाते हुए कैंपस में पी0एच0डी0 करते हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बिहार में विकास की जो रेखा मुख्यमंत्री जी ने खिंची है...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आप अपने समय में बोलें । बीच में बैठकर नहीं बोलिए ।

श्री रितुराज कुमार : विपक्ष के लोग जब विपक्ष में नहीं सरकार में थे तो एक ही शब्द पूरे बिहार में गूंजता था विकास के नाम पर वह था कास्ट, न शिक्षा थी, न सुरक्षा था, न सड़कें थीं, न पानी था, कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं थी इनके समय में...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : बीच में मत बोलिए । माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

श्री रितुराज कुमार : महोदय, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं । मैंने जो महसूस किया बचपन में, 90 के दशक में...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य देखिए, आप पुराने सदस्य हैं, आपको अगर कटाक्ष करना है तो बाद में करिए ।

श्री रितुराज कुमार : महोदय, आज विपक्ष का नाम सुनकर वोटर्स क्यों डर जाते हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : उनको बोलने दीजिए ।

श्री रितुराज कुमार : कहते हैं कुछ भी हो जाएगा हम इनको वोट नहीं दे सकते हैं, हमारा रूह कांपता है...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : कृपया उनको बोलने दीजिए । आप बोलिए, इधर–उधर ध्यान नहीं दीजिए, सीधा आसन की तरफ ध्यान दीजिए ।

श्री रितुराज कुमार : सुन लीजिए, सुन लीजिए, आज तक इन्होंने एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया । किसी भी विकास परियोजना में सकारात्मक सहयोग भी नहीं किया है केवल आलोचना करना जानते हैं क्योंकि जिम्मेवारी इनके ऊपर जब आती है तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

श्री रितुराज कुमार : सभापति महोदया, बिहार अब 90 के दशक वाला बिहार नहीं है, यह नया बिहार है, जहां किसान सम्मान चाहता है, वह अवसर चाहता है...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आप अपनी बारी में बोलिए न ।

श्री रितुराज कुमार : महिला सुरक्षा चाहती है, स्वाभिमान चाहती है और जब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता है तो इनके पेट में दर्द होता है, ये कहते हैं कि सरकार घूस दे रही है, सरकार वोट चोरी कर रही है, जहानाबाद में क्या हुआ, आप गए थे, आप गए थे...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें । अपनी बात समाप्त करें ।

(व्यवधान)

कृपया हल्ला मत करिए । आप अपनी बात को समाप्त करिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती संगीता देवी, अपनी बात को रखिए ।

(व्यवधान)

आपलोग बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदया, मैंने कल भी कहा था...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्यगण, पूरी दुनिया आप सबको देख रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । आपको भी कह रहे हैं कि जो भी बात करें, आसन की तरफ देखिए, इधर–उधर करके हाथ मत फैलाइए । संगीता देवी, अपना पक्ष रखें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदया, कल भी मैंने सदन में कहा था कि जो पहली बार माननीय सदस्य जीतकर आए हैं, उनको बोलने दिया जाए, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष हों, वे सरकार की तरफ से उत्तर नहीं दे रहे हैं तो जब सरकार उत्तर देगी और सरकार अगर उत्तर देने में कुछ कमी उनको लगती है, गलत लगता है तो प्वाइंटआउट कर सकते हैं और ये पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, इनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि नए माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बार–बार खड़ा होकर, बिना नियम के, बिना कानून के, बिना कार्य संचालन नियमावली के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अपनी गरिमा को मत गिराइए, आपका बहुत गरिमा है, आपके बारे में बहुत अच्छी सोच है लोगों की लेकिन आप बार–बार खड़ा होइएगा तो आप माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

हास्य के पात्र बन जाइएगा और मुझे मालूम है कि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं लेकिन दो–दो मिनट में उठिएगा और बैठे–बैठे बोलिएगा तो इस तरह के सवाल करके अपना जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर आप उसपर...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपको अनुमति मिला है ? आप खड़ा होकर बोल रहे हैं, अनुमति नहीं मिला, बैठ जाइए । अनुमति नहीं मिला तो नहीं बोलना है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : चाहते हैं, तो पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि पहली बार जो जीतकर आए हैं वे माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करें, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, यही अनुरोध करना चाहते हैं ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्या संगीता जी, आप बोलिए आपका दो मिनट समय है ।

टर्न–21 / यानपति / 20.02.2026

श्रीमती संगीता देवी : सभापति महोदया, मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को धन्यवाद देती हूं और अपने 65 बलरामपुर की जनता को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आज मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया । माननीय सभापति महोदया, मैं आज इस गरिमामयी सदन में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के बजट की अनुदान की मांगों का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदया, किसी भी सभ्य समाज और प्रगतिशील राज्य की पहली पहचान उसकी कानून व्यवस्था होती है । बिना सुरक्षा विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । सरकार का यह केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि बिहार के

13 करोड़ नागरिकों को भयमुक्त वातावरण देने का एक ठोस संकल्प पत्र है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । उनके नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और सुशासन को एक नई मजबूती मिली है और साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आभार व्यक्त करती हूं । गृह विभाग के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण को सख्ती से लागू करने तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बजट की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बिहार को एक नई दिशा देगी । पुलिस वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत थानों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, नये थाना भवनों का निर्माण तथा पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवास की व्यवस्था इनके मनोबल को और ऊंचा करेगी जिससे कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त बनेगी । आज आपराधिक तत्व जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस के आधुनिकीकरण और स्मार्ट पुलिसिंग अत्याधुनिक हथियार, वाहन एवं संचार उपकरणों के लिए किया गया है । आवंटन अत्यंत सराहनीय है । साथ ही बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल ठगी पर नियंत्रण करने के लिए पतरी जिले एवं अनुमंडल में साइबर थानों को सशक्त बनाना सरकार की जिम्मेदारी है ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : कृपया आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह । कृपया दो–तीन मिनट में अपनी बात को रखें ।

श्रीमती संगीता देवी : एक मिनट महोदया । लेकिन मैं विपक्ष के नेताओं को...

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : आदरणीया सभापति महोदया, मैं आसन का और अपने कल्याणपुर विधान सभा की महान जनता का सादर साधुवाद और धन्यवाद करता हूं । साथ–साथ बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी का भी बहुत–बहुत साधुवाद करता हूं । पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन इस समय चूंकि आपने समय कम दिया है तो कुछ बिंदुओं की तरफ मैं गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आदरणीय विनय बाबू का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिले में कठवलिया जो मेरे विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अंतर्गत है वहां विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, विराट रामायण मंदिर जहां पिछले दिन 17.01.2026 को सभी माननीय वहां पर उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, सम्राट जी भी थे, विनय बाबू भी थे, ये सब लोग वहां उपस्थित थे और वहां करीब–करीब पांच लाख की भीड़ थी और प्रतिदिन वहां 25–30 हजार से कम लोग सामान्य दिनों में भी नहीं रहते हैं । पिछले दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि थी, बहुत भीड़ थी ।

मैंने सरकार से डिमांड किया था कि वहां एक स्थायी थाना बना दिया जाय, वहां एक चौकी तो बना लेकिन विनय बाबू से भी आग्रह करना चाहता हूं चूंकि यहां वह भी उपस्थित हैं कि वहां थाना की आवश्यकता है, रोड भी जाम रह रहा है । मंत्री जी से भी कह रहा हूं भीड़ काफी हो रही है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वहां थाना की स्थापना की जाय । स्थायी थाना की स्थापना की जाय । और जो मंदिर है, जो लगभग 150 एकड़ के दायरे में बन रहा है उसकी घेराबंदी की आवश्यकता है तो मैं आदरणीय गृह मंत्री, सम्राट चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि उस मंदिर की घेराबंदी करा दी जाय ताकि जो राष्ट्रीय धरोहर बन रहा है, जो मंदिर बिहार में बन रहा है और बिहार के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने नाम को स्थापित करेगा उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है । मैं पूर्वी चंपारण जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा चूंकि पूर्वी चंपारण जिला इस राज्य का पटना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है । लगभग 90 लाख से अधिक आबादी आज के दिन में पूर्वी चंपारण में है और एक एस0पी0 साहब उसको कंट्रोल कर रहे हैं । तो मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप वहां एक सिटी एस0पी0 और एक ग्रामीण एस0पी0 का पद सृजित करके उस जिले को कम से कम दो पुलिस का पोस्ट दीजिए ताकि वहां की विधि–व्यवस्था को संधारित करने में, बाकी भी काम करने में, थाना को कंट्रोल करने में और पब्लिक को मिलने–जुलने में वहां सुविधा हो सके। महोदया, मैं पुलिस विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि हमलोग जब थाने में जाते हैं, मेरे अपने कल्याणपुर थाना सहित बिहार के कई थानों को जब आप देखते हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : एक मिनट महोदया, एक सुझाव देना चाहता हूं कि थाना जो कबाड़ की स्थिति में हो गई है, आपने आदर्श थाना बना दिया है लेकिन जो पूर्ति करते हैं, जो सामान को लाते हैं पकड़कर, गाड़ी रखते हैं, उसको रखने की जगह नहीं है । सारे थाना का चेहरा खराब है, आप अलग कहीं व्यवस्था करिए । अलग कर घेराबंदी करिए और पुलिस लगाकर उसकी रखवाली करिए, साथ–साथ मेरे क्षेत्र में पूरन छपरा एक जगह है जो चकिया कल्याणपुर और केसरिया थाना से 25–30 कि0मी0 की दूरी पर है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य, श्री वशिष्ठ सिंह जी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : वहां पर थाना बनाने का आपसे आग्रह करता हूं । मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । आपने मुझे समय दिया बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री वशिष्ठ सिंह : सभापति महोदया, मैं आसन का आभार प्रकट करता हूं । महोदया...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपके पास दो से तीन मिनट समय है ।

श्री वशिष्ठ सिंह : अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री महोदय का, सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं । गृह विभाग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं । बिहार जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में आया तबसे लेकर आजतक बिहार में सुशासन का राज चल रहा है । न्याय के साथ विकास हो रहा है और कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । महोदया, जब बिहार में महिलाओं को पुलिस की वैकेंसी निकालने की जब बातें आई तो हम जैसे लोग सोच रहे थे कि सिविल में महिलाओं की भर्ती हो रही है वह तो बात अच्छी लग रही है लेकिन पुलिस में भर्ती होकर महिला हाथ में हथियार लेकर कैसे काम करेंगी । हमलोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा था लेकिन जब बहाली हुई और बहाली के उपरांत जब बिहार की बेटियां अपने हाथ में हथियार लेकर रातभर सड़क पर और क्षेत्र में दौरा करती रहीं और हमलोग चैन की नींद सोते रहे यह नीतीश कुमार जी की सोच जो है उस सोच को मैं सलाम करता हूं, उनके विचार को मैं सलाम करता हूं महोदय । महोदय, पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है । राहुल शर्मा जी माननीय सदस्य बोल रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे । हमलोग वो पुलिस भी देखें हैं जिनकी कमर से नीचे वर्दी खिसकते जाता था और जीप पर बैठकर कम चलते थे, जीप को ठेलने में पुलिस विभाग के कर्मी लगे हुए थे और पुलिस लगी हुई थी । उस शासन को भी हमलोगों ने देखा है राहुल जी और राहुल जी हमारे नेता ने जो काम किया है बिहार को चलाने में और बिहार को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मैं समझता हूं कि उनका जो विजन है शायद आपके नेता कभी सोच नहीं सकते हैं । हमारे नेता ने क्या नहीं किया, हमारे शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी नरसंहार नहीं हुआ और आप के समय में 118 नरसंहार हुआ, 130 दंगे हुए, 2600 लोगों की मौत हुई । क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं होता था और आज ये बदलाव हमलोगों के पक्ष में हुआ है । हमारे नेता...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : अब आप समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदया, एक मिनट । हमारे लोग स्वाभिमान रैली करते थे और आपकी पार्टी के नेता लाठी में तेल पिलाने की रैली करते थे...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी । आपका दो से तीन मिनट समय है ।

श्री वशिष्ठ सिंह : और हमारे नेता बिहार को चलाना चाहते हैं, दोनों नेताओं में ये फर्क है।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदया, आज मैं गृह विभाग सहित अन्य मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं । जिस दौर में अपराध सत्ता का निर्माण था वह दौर बिहार के लिए सबसे बड़ा अपमान था । 2005 से पहले का बिहार बाहुबली, बाहुबल का बिहार था और इस सच्चाई से कोई इनकार

नहीं कर सकता । आज मैं इस सदन में खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहता हूं बिहार अब बदल चुका है, बिहार अब झुकता नहीं, बिहार अब डर से नहीं, कानून से चलता है । वह दौर गया जब व्यवस्था पर सवाल उठते थे, वह दौर गया जब अपराधियों का मनोबल ऊंचा था, आज स्पष्ट संदेश है कानून से ऊपर कोई नहीं । महोदया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की देख–रेख में गृह विभाग ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार निर्णय लेती है और निर्णय लेकर पीछे नहीं हटती है । यह सरकार समझौते की नहीं संकल्प की सरकार है । यह सरकार संरक्षण की नहीं, कार्रवाई की सरकार है । एक शायरी से आपको बताना चाहते हैं जो अपराध से टकराए वही असली सरकार है, गृह विभाग की सख्ती से बदल रहा बिहार है । न झुकेगा कानून, न रुकेगी विकास की रफ्तार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुरक्षित है परिवार ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / मुकुल / 20.02.2026

क्रमशः

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदया, 2005 से पहले के बिहार में एक ऐसी सरकार थी, जिसमें कानून का नहीं एक परिवार का राज था । जहां अपहरणकर्ताओं व अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था, थाने अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान थे । आम आदमी न्याय की नहीं, अपनी जान बचाने के लिए सोचता था, शाम 6 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था । महोदया, उस समय गृह विभाग नाम की कोई चीज नहीं थी, बस सत्ता के इशारे पर चलने वाली व्यवस्था थी । कुर्सी बचाने के सौदे हुए, कानून के साथ और बिहार जलता रहा अपराध की आग के साथ । अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग केवल पुलिस नहीं है, यह हर मां की नींद की शांति है, यह हर बेटी की सुरक्षा है, यह हर व्यापारी के विश्वास की नींव है, यह हर युवा के भविष्य की गारंटी है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जब कानून मजबूत होता है तभी उद्योग आता है, तभी निवेश आता है, तभी रोजगार आता है । आज बिहार में निवेश इसलिए आ रहा है, क्योंकि व्यवस्था मजबूत है । अध्यक्ष महोदय, आज अपराधियों पर सीधी कार्रवाई हो रही है, पुलिस को राजनैतिक गुलामी से आजादी मिली है, फास्ट्रैक कोर्ट चला कर जल्दी न्याय हो रहा है, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है । कुछ लोग कहते हैं अपराध हो रहे हैं, मैं कहता हूं हां घटनाएं होती हैं, लेकिन फर्क देखिए पहले घटना दबती थी, आज गिरफ्तारी होती है । अध्यक्ष महोदय, पहले एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में डर लगता था, आज पुलिस खुद कार्रवाई

करती है । पहले अपराधी सत्ता के करीब बैठते थे, आज अपराधी जेल के करीब बैठते हैं । अध्यक्ष महोदय, इन पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहता हूं –

''जो सवाल उठाते हैं, पहले आईना देख लें,
जिनके राज में अंधेरा था, वह उजाला सीख लें।
अब कानून से खिलवाड़ किसी का काम नहीं,
गृह विभाग जाग रहा है, ये कोई आम बात नहीं ।
दृढ़संकल्प, सख्त कार्रवाई, स्पष्ट है सरकार की तैयारी,
सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है धरती हमारी ।''

अध्यक्ष : केदार बाबू, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सरकार ने बहुत ठोस कदम सब उठाए हैं, पुलिस आधुनिकीकरण, नई भर्तियां, 112 इमरजेंसी सेवा, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर क्राइम यूनिट... .

अध्यक्ष : केदार जी, कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : ड्रग्स और माफिया के खिलाफ विशेष अभियान ।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : इस तरह पूरा बिहार सुरक्षित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा में.....

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा जो सदन में कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में हम बोलने के लिए खड़ा हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है और बिहार की सरकार ने 20 वर्षों में कीर्तिमान स्थापित की है और जो गृह विभाग का आज सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है अध्यक्ष महोदय वह बजट ऐतिहासिक है, इस मामले में ऐतिहासिक है महोदय जहां गृह विभाग का बजट 2004–05 में मात्र 2 हजार 642 करोड़ था महोदय आज आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में 2026–27 में गृह विभाग का बजट महोदय 20 हजार 132 करोड़ 86 लाख 59 हजार हो गया है । महोदय, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत के आसपास गृह विभाग के बजट में सरकार ने वृद्धि करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में न्याय यात्रा करते रहें और न्याय यात्रा करने का मकसद क्या था महोदय कि एक समय बिहार के अंदर जंगल राज था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस जंगल राज की समाप्ति के लिए राज्य के हर जिले में गये और उनका मकसद था बिहार को भय मुक्त वातावरण से बिहार की जनता को बचाना था । अध्यक्ष महोदय, हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति जिन्होंने न्याय यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता का विश्वास उन्होंने जीतने का काम किया और बिहार की जनता का भी आभार

प्रकट करते हैं कि 24 नवंबर, 2025 को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी ने एक संकल्प लिया था इस बिहार के अंदर और उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे और सुशासन के साथ हम शासन स्थापित करके बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, लगातार 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है । महोदय, पहले क्या स्थिति थी, 2005 के पहले और यह मैं नहीं कहता महोदय उस समय एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट थी महोदय 1990 से 2005 के बीच में एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि बिहार टॉप क्राइम स्टेट था महोदय और बिहार में अगर कोई एक उद्योग चलता था तो उस उद्योग का नाम किडनैपिंग उद्योग बिहार में चलता था । महोदय, उस समय के शासन में सुशासन शब्द का नाम नहीं था लेकिन उस समय केवल अगर बिहार में हत्या, अपराध, बलात्कार की घटनाएं घटित होती थीं महोदय और यही नहीं इस बात को जनता आज तक भूल नहीं पाई है । हम यह कहना चाहते हैं, कई माननीय सदस्य अपने डाटा को प्रस्तुत कर रहे थे । महोदय, 2004–05 से लेकर और ये 2025, एन0सी0आर0बी0 ने यह डाटा में दिया है, तुलना किया है महोदय कि संज्ञेय अपराध के मामले में, हत्या में 2004 की तुलना में बिहार में 34 प्रतिशत की कमी आयी है, डकैती में 87 प्रतिशत की कमी आयी महोदय, लूट में 47 प्रतिशत की कमी आयी, दंगा में महोदय 73 प्रतिशत की कमी आयी, फिरौती और अपहरण में महोदय 86 प्रतिशत की कमी आयी । मार, डकैती में 69 प्रतिशत की कमी आयी और 28 प्रतिशत बैंक डकैती, 97 प्रतिशत बैंक लूट में, 89 परसेंट जो है वह अपराध में कमी आयी है । महोदय, एक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के समय में मात्र 42 हजार पुलिस की बहाली हुई थी और उस समय अपराध, अपराधी पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आये महोदय, जहां बिहार में 42 हजार पुलिसों की संख्या थी वहां 1 लाख 10 हजार नियुक्ति उन्होंने किया है और 2 लाख 29 हजार नियुक्ति करने की हमारी सरकार की मंशा है । अध्यक्ष महोदय, बिहार में कानून का राज हमने स्थापित करने का काम किया है । महोदय, हम विशेषकर यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता के दल समय में मात्र 3 प्रतिशत महिलाएं पुलिस बल में थीं और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महोदय 2016 में उन्होंने 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण दिया और आज महोदय हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाओं की संख्या है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की इजाजत दी, हम तो कई अपराधों की चर्चा करना चाहते हैं, जैसे सिवान में तेजाब कांड हुए थे किस तरह से दो लोगों को तेजाब में डालकर मारा गया था और कई नक्सली घटनाओं का भी हम जिक्र करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हो रहा है इसलिए मैं बैठ रहा हूं । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : ए0आई0एम0आई0एम0 का नाम पुकारा गया था, लेकिन वे उस समय उपस्थित थे नहीं । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस समय हमने नाम पुकारा था, अब आप बैठ जाइये ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया और कई माननीय सदस्यों ने आज गृह विभाग के विषय पर चर्चा की और न पक्ष ने यह साबित ही किया कि हम न ही रहेंगे, लेकिन मैं राजद को धन्यवाद देता हूं जो विजय बाबू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो रोज ट्वीट करती है, सुबह होगा तो पहला ट्वीट राष्ट्रीय जनता दल यही करती है और इतने गंभीर मुद्दों पर कोई कटौती प्रस्ताव तक नहीं दिया इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है राजद के लिए और आप सोचिए कि जिस तरह बिहार में लगातार आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पिछले 20 वर्षों में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, बिहार आगे बढ़ा, बिहार की व्यवस्था बदली और आज पुलिसिंग के साथ–साथ जनता के सहयोग के लिए भी पुलिस खड़ी है और अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि लगातार 112 की चर्चा लगातार कई माननीय सदस्यों ने की, 112 के माध्यम से लाखों लोगों को चाहे वह अग्निकांड से जुड़ा मामला हो, हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो या किसी तरह की अप्रत्याशित घटना हो उससे सीधा लाभ,

क्रमशः

टर्न–23 / सुरज / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : और लगभग आप समझिये घरेलू हिंसा महिला और बच्चों के विरूद्ध लगभग साढ़े चार लाख मामले आयें, जिसका निष्पादन बिहार की पुलिस ने करने का काम किया और इसकी संख्या लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से लगातार इस विभाग को रखे हुये थे और आज भी एकदम गलतफहमी में कोई मत रहिये नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली

सरकार है, सबके मुखिया नीतीश कुमार हैं । दायित्व जरूर बदलता है, हमारा दायित्व तो जरूर बदल गया कि मैं वित्त मंत्री से गृहमंत्री हूं लेकिन नेता नीतीश कुमार हैं, आखिरी डिसीजन नीतीश कुमार जी का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। कोई गलतफहमी में हैं तो गलतफहमी में रहने दीजिये । पूरी तरह सरकार एकजुट होकर काम करती है और इसका फल लोगों ने देखा । बिहार की जनता को इतना भरोसा हुआ लगातार लोगों ने गठबंधन के दौर को देखा है और आज देखिये 2025 के चुनाव में पूरी तरह एन0डी0ए0 जब एकजुट रहा तो बिहार की जनता ने 202 सीट देने का काम किया । पिछली बार तो कुछ गलतियों से इन लोगों को कुछ सीट मिल गया था और एक बार नीतीश जी की कृपा से कुछ सीटें मिल गयी थी । मैं जानता हूं ये लोग तो 22 पर थे, मैं 22 का भी सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं और इनके नेता लालू प्रसाद जी को भी पूर्ण रूप से जानता हूं, कोई गलतफहमी में मत रहियेगा । बिहार की जनता सबको जानती है । आज बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि अपराध । मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अपराध में जो सिर्फ गिरफ्तारी हुई आज के तारीख में आप समझिये कि हत्या के मामले में, डकैती के मामले में लगभग सात हजार लोगों की गिरफ्तारी करने का काम बिहार की सरकार ने किया । लगभग ढ़ाई हजार से अधिक लोगों को लूट कांड में गिरफ्तार करने का काम किया । पुलिस पर जो हमला किया 2700 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसको जवाब भी देने का काम बिहार की पुलिस ने किया है, किसी को छोड़ा नहीं है । कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता है आज बिहार से । आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं ? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहां दोमत है । बिहार में सुशासन नहीं था, हमलोग साथ में भी काम किये, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में काम किये । 1994 में ये इसलिये ये अलग हुये कि सत्ता के द्वारा सुशासन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिये अलग हुये । इसलिये सब अलग किसलिये होते हैं क्योंकि जब सत्ता के केन्द्र में बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित नहीं करता है तो लोगों को अलग भी होना पड़ता है । ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है । पूरे 2025 में 03 लाख 86 हजार 380 लोगों की गिरफ्तारी हुई है । पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है । आज मैं गृहमंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इको सिस्टम बनाया है कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है । मैं भी गृहमंत्री हूं, हमारे डी0जी0पी0 यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, कोई हमलोगों का हस्तक्षेप नहीं है । कहीं हमको किसी थाना में जाते हुये नहीं देखा होगा आपलोगों ने । मैं जाना भी नहीं चाहता हूं । पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया है और आज देखिये लगातार कार्रवाई

हो रही है। एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पायी और वह आदमी दो घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है और कहता है कि हम तो बीमार हो गये । अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पीटल में जाना पसंद करता है, यह स्थिति है बिहार में । आप समझ लीजिये बिहार कैसे बदल चुका है । ये सिर्फ गलतबयानी करते हैं । मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान है, कहा कि बहुत आपलोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं । आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछ कर गये और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं एकदम जाना चहिये । पॉलिटिकल कार्यकर्त्ता स्वाभिक है कोई घटना होगी तो जायेंगे । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा । मैंने कहा आप नाम बताइये और प्रूफ दीजिये 24 घंटे के अंदर बेउर के जेल में बंद करूंगा । यह कहां से, कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं ? आपको जवाब देना पड़ेगा, आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिये, बताना चाहिये । पुलिस तो कार्रवाई के लिये खड़ी है । पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और न छोड़ने देना है, यही सुशासन है ।

बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा है । आज यह मौका मिला है । इस बार तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश दिया है सात निश्चय पार्ट–3 में हमलोगों को विशेष तौर पर आदेश किया कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिये कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं लग पायी है, मैं रोड़ बनाते रह गया, बिजली पहुंचाते रह गया, गांव में बेसिक नीड पहुंचाते रह गया, गांव में, पंचायतों में स्कूल खोलते रह गया अगला पांच साल डेडिकेडेट तौर पर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिये व्यवस्था कीजिये और सुशासन स्थापित कीजिये । सुशासन का जैसे ही राज होगा पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ा हा जायेगी और मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आगे के दिनों में हमलोगों ने जो एस0टी0एफ0 की पूरी व्यवस्था खड़ा की है । अब तो प्रमंडल से लेकर जिला स्तर पर हमलोग एस0टी0एफ0 को लेकर जा रहे है। । पहले हेडक्वार्टर में होता था और यहां से कार्रवाई होती थी और हम पूरे प्रदेश को मॉनिटरिंग करने का काम करते थे । आप देखते होंगे ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है जहां स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं, उनकी गिरफ्तारी प्रत्येक तीन दिन, चार दिन पर करने का काम कर रहे हैं और आजादी के बाद जितनी गिरफ्तारी 2005 तक हुई है उतनी गिरफ्तारी तो पिछले तीन वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है इसलिये लगातार आगे भी कार्रवाई किया जा रहा है । पुलिस सेनेटाइज करने के लिये हमलोगों ने तय किया कि सभी थाने में हमारे एस0पी0 जायेंगे और आरक्षी अधीक्षक जाकर वहां जनता दरबार लगायेंगे

। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश था कि आप सभी जिलाधिकारी से लेकर जो भी ऑफिसर हो, टॉप टू बॉटम चाहे ए0एसी0एस0 के पदाधिकारी हों या नीचे एक थाना का कर्मचारी हो, सबको कहा गया कि जनता दरबार लगाना है और दो दिन लगाने की व्यवस्था की । मैंने तो पुलिस विभाग से पूरा रिपोर्टिंग कंसेप्ट खड़ा किया । मैंने रिपोर्ट मंगाने का काम शुरू किया । जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं एस0पी0 उनके बीच का रिपोर्ट मंगाकर थाना में जो वह जा रहे हैं कितने मामले का निष्पादन हो रहा है, कितने लोग आये थे सबकी समीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है । इसलिये अध्यक्ष जी सिर्फ बोल देने से शासन नहीं चलता है । सरकार इकबाल है, नीतीश कुमार जी ने जो इकबाल खड़ा किया है, उसको बिहार की जनता लगतार देखने का काम कर रही है । आगे भी मैं बताना चाहता हूं बुनियादी ढ़ांचा के बारे में । आज सी0आई0डी0, वह सी0आई0डी0 नहीं है जो कागज मांगती थी, कार्बन कॉपी मांगती थी । आज लगातार बिहार में इसकी पूरी व्यवस्था बदली है । आज चाहे वह सी0आई0डी0 हो, एस0बी0यू0 हो, एस0टी0एफ0 हो, ई0ओ0यू0 हो या प्रोबिशन का डिपार्टमेंट हो । ये पूरी तरह एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज पूरी तरह व्यवस्था खड़ा किया है और अब तो हमलोग आगे बढ़ चुके हैं । अभी मैं गया था ए0आई0 के सबमिट में दिल्ली और मैंने जो देखा ए0आई0 को यदि पॉजिटिवली राज्य सरकार के पदाधिकारी इसको आगे बढ़ायेंगे और जिसकी कल्पना हमलोग नीचे कर रहे हैं ये पूरा मैकनिज्म, पूरी तरह एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके नीचे ए0आई0 के माध्यम से हम पूरी तरह जनता को सुविधा देने का काम कर सकेंगे । इस ए0आई0 का भी पूरा लाभ लेने का काम पूरी सरकार करेगी । अभी कुछ साथी कह रहे थे कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होता है । मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि अब तो यह व्यवस्था है कि ई–एफ0आई0आर0 का मामला हो या एन0सी0आर0बी0 के माध्यम से एफ0आई0आर0 हो या किसी बड़े पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / धिरेन्द्र / 20.02.2026

....क्रमशः....

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आपको जानकार खुशी होगी कि जितने आवेदन आयें, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आयें, उसमें 96.16 परसेंट सही पाये गये और एफ॰आई॰आर॰ दर्ज करने का काम किया गया । यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है लेकिन लोग चिंता करते हैं, आज के तारीख में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को रख चुके हैं, कृपया बैठिये । आपको मौका मिला था ना । माननीय मंत्री, आप जारी रखिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जिन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, उनको चिंता है । आज पूरी तरह...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको समय दिया गया था, अपनी बातों को आपने रखा है। कृपया बैठ जाएं, शांति बनाये रखें । आपको समय दिया गया था, कृपया बैठ जाएं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यहां पर अभी, माननीय सदस्यों को जाना ही है, (इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए) हम माननीय सदस्य, इन लोगों को जाना ही है महोदय, क्योंकि ये लोग कोई गंभीर नहीं हैं, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय जी, शांति रखें ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये लोग सुशासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं । बिहार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे, यहां प्वाइंट टू प्वाइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं । महोदय, आज यह जान लीजिये, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27 हजार लोगों के लिए जो हमारे सिपाही साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थानों में किया गया । इसके साथ–साथ लगभग जो महिला सिपाही हैं, उनके लिए भी लगभग 159 यूनिट बनाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ–साथ लगभग 1279 यूनिट और भी महिला सिपाहियों के लिए बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है तो आप समझिये कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है और आज की तारीख में जिस तरह सेंट्रलाईज मॉनिटरिंग सिस्टम (सी॰एम॰एस॰) के माध्यम से जो एस॰टी॰एफ॰ के द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा, इसको और आगे व्यवस्थित करने का काम किया जायेगा, जिसके माध्यम से हम थाने का मॉनिटरिंग और अच्छे ढंग से करने का काम कर सकेंगे । इसके साथ–साथ जिलों में 968 थाने को ऑनलाइन सी॰सी॰टी॰एन॰एस॰ नेटवर्क से जोड़ा गया तथा इसके अतिरिक्त 343 थाने ओ॰पी॰ को सी॰सी॰टी॰एन॰एस॰ से आच्छादित नहीं हैं जिसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है । आगे विशेष तौर पर जो एस॰एस॰जी॰ का विशेष बल है हमारे पास, उसको भी सेंटरिंग करने का काम, उसमें बम निरोधक दस्ता का पूरी व्यवस्था करने का काम सरकार कर रही है । आगे भी वर्ष 2025–26 में आपने देखा वित्तीय वर्ष में, पुलिस थाना सर्विलांसिंग परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 1212

थानों में कार्यरत सी॰सी॰टी॰वी॰ को ऑनलाइन किया गया और इसके साथ–साथ 176 थाने के सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरों का अधिष्ठापन डैसबोर्ड निर्माण भविष्य में नये थाने के सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । आगे भी कई चीजों को आपने देखा होगा कि नेशनल साइबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से 1930 से, राज्य के सभी जिलों 24x7 पूर्ण रूप से कार्यरत किया गया है जो साइबर अपराध को देख रहा है और इन लोगों ने चिंता जाहिर की कि साइबर अपराध पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राईम के मामले में लगभग 01 लाख 33 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 54 परसेंट जो लोग थे उनकी राशि को होल्ड किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया गया और आप देखिये, जो फ्रॉड हुए पैसे वह लगभग 517 करोड़ रुपया का इसमें होल्ड करने का काम किया गया, उसमें से कई लोगों को इसका पैसा भी रिसिव करा दिया गया और आगे इसकी कार्रवाई चल रही है लेकिन आप देखेंगे कि कई लोगों ने यह चिंता की कि आगे कार्रवाई और कैसे बढ़ते रहे । हमलोगों ने साइबर अपराध के बाद, अभी सोशल मीडिया पर भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम शुरू किया गया है लेकिन क्षमता निर्माण और कौशल विकास, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग का काम बिहार की पुलिस कर रही है । अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में इसकी पूरी व्यवस्था की, अभी लगभग 1200 से अधिक हमारे एस॰आई॰ के जवान थे उनको पासआउट करने का काम किया गया और आगे भी जो लोग, जिस भी मामले में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो पुलिस के सैक्टर हैं चाहे वह साइबर अपराध हो, चाहे वह कौशल विकास का मामला हो या क्षमता निर्माण का मामला हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको हमलोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अभी सबसे बड़ा है कि फॉरेंसिक लैब, ये सभी जिलों में देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और अब तो चलंत फॉरेंसिक लैब के तौर पर हमारा प्रत्येक जिला यूनिट पर हमारी गाड़ी उपलब्ध है, कहीं कोई घटना घटती है, तुरंत हमारी पुलिस वहां पर एफ॰एस॰एल॰ की टीम को लेकर उसके पूरे चीजों को रिपोर्टिंग करने का काम करती है । अभी दो दिन पहले जो अंतिम हमारे यहां उग्रवादी के तौर पर हमारे यहां थे, उस अपराधी को पकड़कर उनके जो हथियार थे, उनको सीज किया गया और आज 143 इनामी उग्रवाद अपराधी थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, उसमें लगभग 2722 कारतूस बरामद किये गए, 174 डेटोनेटर बरामद किए गए, 135 बारूदी सुरंग के जो कैन थे, बम थे, उसको बरामद किए गए । आज मैं यह घोषणा कर सकता हूँ बिहार विधान सभा के अंदर कि अब बिहार में कोई नक्सलिज्म, कोई नक्सलिज्म का अपराधी नहीं बचा । आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय

प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार अब उग्रवादी से मुक्त हो गया, यह सबसे बड़ा मैसेज बिहार की जनता के लिए जा रहा है । हमारे यहां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां बी॰एम॰पी॰–1, बी॰एम॰पी॰–2 से लेकर अब बी॰एम॰पी॰–19, बी॰एम॰पी॰–20 तक हम पहुँचने का काम कर रहे हैं । इसके साथ–साथ इनका विशेष आग्रह था, निर्देश था कि आप बिहार के जो इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी सुरक्षा देने का काम किया जाय तो बिहार की सरकार ने तय किया है कि दो बटालियन हमलोग बनायेंगे, जिसका नाम बी॰आई॰एस॰एफ॰ के तौर पर दो नया बटालियन हम बिहार में इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड करने का काम करेंगे और आगे भी कई जगह पर इसको बनाने का काम किया जा रहा है, कई जगह सेना जमीन उपलब्ध कराने के लिए डिमांड उनलोगों ने किया है, उसको भी हमलोग उपलब्ध करा रहे हैं । कई जगह बी॰एम॰पी॰ जो हमारा विशेष बी॰एस॰ए॰पी॰ है उसके लिए हमलोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं । इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है । वर्ष 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में होमगार्ड के लिए विशेष तौर पर 15 हजार होमगार्ड के सलेक्शन करने का काम किया गया और आगे भी, जिसमें से 11,438 लोगों का नामांकन हो चुका है और आगे भी हमलोग, क्योंकि आगे अभी पुलिस बल में भी भर्ती करना है, आगे सैफ के जवान को भी भर्ती करना है और आगे गृह रक्षकों को भी भर्ती करना है । इन तीनों को यदि जोड़ा जाय, सिर्फ पुलिस बल में तो लगभग 31 हजार पुलिस बल की भर्ती करने का काम श्री नीतीश कुमार की सरकार करेगी और इस बार सैफ के जवान में, जो सैफ के जवान हमलोग प्रयोग करते थे विशेष तौर पर नक्सल के इलाके में, इस बार हमलोगों ने उसमें भी मोडिफाई करने का काम किया है कि इस बार जो हमारे पारा मिलिट्री के फोर्सेज हैं क्योंकि 17 हजार लोग नहीं मिल पाते थे तो पुलिस मुख्यालय का आग्रह था कि सरकार इस पर निर्णय ले तो इस बार 17 हजार सैफ जवान में हमलोग पारा मिलिट्री के जवानों को भी मौका देंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे । इसके साथ–साथ 13.5 हजार गृह रक्षकों को और अधिक जो हमारे लोग हैं वर्ष 2026–27 में उनका भी सलेक्शन करने का काम बिहार की सरकार करेगी ।

....क्रमशः....

टर्न–25 / अंजली / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अकेले होम डिपार्टमेंट है जो लगभग 60 हजार लोगों को अगले वित्तीय वर्ष में सब को नौकरी या सेलेक्शन करने काम करेगी अध्यक्ष

महोदय । इसलिए बिहार मजबूत हो, आर्थिक रूप से विकास तभी होगा, जब हम सुरक्षित रहेंगे और होमगार्ड के लोगों को लगातार चिंता रहती थी कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, नीतीश कुमार जी ने उसको भी बढ़ाने का काम किया । जहां मात्र 774 रुपया उनको प्राप्त होता था, आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया । इसके साथ–साथ, कई जगहों पर इसके लिए समादेष्टा कार्यालय के नए भवन बनाने का काम किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा । सबसे बड़ी चिंता रहती थी फायर की, मार्च, अप्रैल और मई के महीने होते हैं इसमें सबसे ज्यादा अग्निकांड की संभावना होती रहती है, तो इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगहों पर इसकी पूरी व्यवस्था खड़ी की, लगभग 45 अनुमंडलों में इसके लिए ऑफिसर प्रतिनियुक्त किए गए, 19 जिलों में इसकी व्यवस्था की गई, यह पूरी संरचना खड़ी की और एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप, जो कैसे अग्नि से लोगों को बचाना है, अग्निकांड से कैसे बचाकर निकालना है, उसके लिए भी बिहार में पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहटा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार में किया गया है और हमलोगों ने सी0आई0एस0एफ0 के साथ एम0ओ0यू0 साइन किया, जो लगातार स्किल ट्रेनिंग देने का काम कर रही है, हमारे अग्निशमन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको पूर्ण रूप से हम व्यवस्थित और एक तरह से स्किल्ड करने का काम किया जा रहा है । इसके साथ–साथ, अब हमलोगों ने टारगेट किया है कि ए0आई0 बेस्ड फायर प्रोडक्शन ऑटोमेशन फेज–2 को लागू करने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से आग की जो घटना है, उसकी पूर्व से चेतावनी कैसे मिल सकती है, किस इलाके में इस तरह के आंधी–तूफान की स्थिति है, इमरजेंसी इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम, फायर इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम किया जाएगा, इसकी पूरी संरचना की जा रही है । उसी तरह कारा के क्षेत्र में, जेल जहां से ये लोग हुकूमत चलाते थे अध्यक्ष जी । राष्ट्रीय जनता दल का पूरा हुकूमत ही जेल से चलती थी और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो इसकी पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया । आज जेल के अंदर लगातार छापामारी की जाती है, कार्रवाई की जा रही है, जेल के अंदर कौन बंद है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की जा रही है । अब तो हमलोग सभी जेलों में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा से सबको ऑनलाइन चेकिंग करने का काम किया जाएगा । कौन मिलने आया, कौन गया और कौन अपराधी से मिलता है इसकी भी जानकारी सरकार के पास होगी, यह पूरी व्यवस्था करने का काम किया जाएगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : और ई–प्रिजन का मामला, ई–मुलाकाती की व्यवस्था की गई । अब यह पूरी व्यवस्था ई–प्रिजन को ई–मुलाकाती के तौर पर खड़ा किया जा रहा है और यह पहला राज्य है जिस राज्य में, देश में सबसे अधिक जेल के अंदर यदि कोई बंदी पढ़ता है, तो वह बिहार है जहां नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है साथियों, सबसे ज्यादा, लगभग 1256 बंदियों को दसवीं की परीक्षा कराने का काम किया गया और 183 बंदी जो बारहवीं की पढ़ाई करना चाहते हैं उनका नामांकन कराने का काम इग्नू के माध्यम से किया गया और आगे भी क्योंकि कई अपराधी आते हैं, अब उनको जेल में रखने के लिए भी बहुत नाटक होता है, तो अब हमलोगों ने सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का निर्णय लिया है । नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा, जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का और हाई–सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसे दुनिया से अलूप होने का काम किया जाएगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बिहार में अभियोजन निदेशालय का हमलोगों ने गठन किया, इसके माध्यम से अब तो जो आदमी उपस्थित नहीं भी है उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया यह सबसे ऐतिहासिक काम है, जिससे कि केस का डिस्पोजल आसानी से हो पाएगा, क्योंकि पुलिस डायरी में, पुलिस के सुपरविजन में सारी चीजें आ जाती हैं और उसके बाद अपराधी भागता रहता है कि वह किसी तरह जेल में न रहे, उसको फंसना नहीं पड़े, तो वह भागने का काम करता है । अध्यक्ष महोदय, लगातार इस पर भी गवाही के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 474 लोगों के खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किए गए, उसको गिरफ्तार करने का काम किया । इश्तिहार के माध्यम से लगभग 80 हजार, जो कुर्की जब्ती होती है उसके माध्यम से किया गया और तामिला जो है, लगभग 2 लाख 46 हजार गवाहों की गवाही कराई गई जिससे कि बिहार में सुशासन स्थापित हो रहा है । इसलिए आज रिकॉर्ड समय में अभियोजन का काम पूरा किया जा रहा है और कई चीजें अभी हमलोगों ने गाइडलाइन दिए हैं, मैं सिर्फ संक्षेप में एक दो इशू आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने कई गाइडलाइन अभी जारी किया है । कई लोग चर्चा करते हैं कि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप उस समय कहां थें ? नाम पुकारा गया था आपका । आपका नाम पुकारा गया था, अबसेंट थे आप ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि बिहार कहां खड़ा है ? मैं बिहार खड़ा होने की स्थिति को बताना चाहता हूं । बिहार में फिरौती के लिए अपहरण होने की स्थिति में देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार खड़ा है, यह है बिहार । यह बिहार है नीतीश कुमार का । जिसने सुशासन स्थापित किया, जिन्होंने आज अपराधी के कोई फिरौती के मामले में सबसे कम मामला कहीं होता है, तो बिहार में होता है और आप समझिए, डकैती का मामला होता था, डकैती के मामले में हम देश में 31वें स्थान पर हैं, 35 में से 31वें स्थान पर हैं, पूछता है बिहार कहां खड़ा है ? बिहार 31वें स्थान पर खड़ा है और फिरौती, जो किडनैपिंग होती थी, तो उसमें तो अंतिम चले गए । महिला पर हमला के मामले में हम अंतिम स्थान 35वें स्थान पर खड़े हैं और ये पूछते हैं । ये लोग सिर्फ एक ट्वीट जारी कर देंगे, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिएगा, ऐसे एक चला आता है, सवेरे–सवेरे लिख देगा, भैया इसकी जानकारी भी तो लो । कोई अपराध होता है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है, जब पुलिस कार्रवाई करती है, तो पता चलता है कि भांजे ने मामा को मार दिया । हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी तारापुर में, मालूम चला कि एक मामा ने एक भांजी के साथ अपराध किया पुलिस ने कार्रवाई की । पुलिस का काम है यदि घटना घटेगी तो सीधा कार्रवाई करने का काम है अध्यक्ष जी, यह लगातार पुलिस कर रही है । मैं तो सिर्फ यह बता रहा था कि मैं कहा हूं ? यौन उत्पीड़न के मामले में हम देश में 35वें स्थान पर खड़े हैं, हम यह बताना चाहते हैं । ये लोग बोलते हैं कि अपराध बिहार में हो रहा है । देश को समझिए, देश की स्थिति क्या है ? बलात्कार के मामले में 1.5 अपराध दर के साथ बिहार 30वें स्थान पर खड़ा है और ये लोग कहते हैं कि रोज अपराध हो रहा है । पॉक्सों अधिनियम के तहत हम 23वें स्थान पर हैं, 35 में 23वें स्थान पर हैं, बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में हम 35 में 32वें स्थान पर खड़े हैं और तब ये पूछते हैं सुशासन कहां है ? हत्या के मामले में हम देश में 11वें स्थान पर खड़े हैं कि जब कि हमारी आबादी कई राज्यों को मिलने के बाद पूरे सेवन सिस्टर्स को मिला दीजिएगा, तब भी हमारी आबादी उन पर भारी पड़ेगी, यह स्थिति है, तब भी हम 11वें स्थान पर खड़े हैं । आज डकैती के मामले में 7वें स्थान पर हैं उसी तरह बिहार में अपराध रंगदारी के मामले में हम आपको बताने का काम किए, इसके साथ–साथ अध्यक्ष जी, हमलोगों ने कई और मामले मैं आपको बताना चाहता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–26 / पुलकित / 20.02.2026

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अभी एक नीट छात्रा का मामला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, जब पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ से लेकर जहानाबाद तक कार्रवाई की, सब लोगों के एविडेंस को कलेक्ट किया गया और जब लोगों को यह लगा कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सी0बी0आई0 को दे देना है । हम लोगों ने तुरंत सी0बी0आई0 को दिया जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, एजेंसी को तय करने का अधिकार दिया । हम लोग रोके नहीं, बचाना नहीं है, किसी को बचाया नहीं जा सकता है । उसी के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की । अभी जो हॉस्टल के प्रबंधक हैं उनके लिए भी पूरे प्रदेश में हम लोगों ने गाइडलाइन देने का काम किया, कैसे रखना है, सी0सी0टी0वी0 रखना है, कैमरा लगाना है । उसी तरह कई लोग शिकायत करते थे कि गाना बजता है, दो अर्थी होती है, उस पर निर्देश देने का काम बिहार की पुलिस ने किया । महोदय, इसके साथ–साथ बिहार में जो लगातार कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है ।

मैं सिर्फ एक जानकारी दे देता हूँ कि कुछ नई चीज हम लोग करने वाले हैं । अभी जब हम गृह मंत्री के तौर पर काम करना शुरू किए और मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहता है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाइए, महिलाओं को काम आगे दीजिए और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कीजिए । बिहार पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ी की कि हम अभया बिग्रेड जिसको पुलिस दीदी के तौर पर गठन करेंगे, जिससे कि पूरे बिहार में जितने स्कूल और कॉलेज हैं, लगभग 1500 स्कूटी खरीदने का काम किया जा रहा है और लगभग 2500 हम मोटरसाइकिल इससे खरीदेंगे, जो स्कूल–कॉलेज की पूरी तरह सुरक्षा करने का काम करेगी ।

उसी तरह बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के लिए केंद्र से हम लोगों को सहयोग मिलेगा और बिहार की सरकार सहयोग करके बिहार में स्थापना करने का काम करेगी । उसी तरह हाई सिक्योरिटी जेल हमने बताया और भागलपुर में एक नए मुक्ति कारागार का निर्माण बिहार की सरकार कराएगी, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा ।

इसके साथ–साथ दो महत्वपूर्ण चीज, पुलिस के लिए दो महत्वपूर्ण काम हम लोग करने जा रहे हैं । एक, सभी पुलिस लाइन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना जिला के पुलिस लाइन में जीविका दीदी के माध्यम से रसोई घर शुरू किया है जो मात्र 60 रुपया में उनको खाना उपलब्ध कराने का काम कर रही है । कोई टेंशन नहीं, बनाना कैसे है, उनको सीधा भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रही है । महोदय, ये सभी पुलिस लाइन, जो हमारे 40 पुलिस लाइन हैं, सभी जगह देंगे, हम ट्रेनिंग कैंप में तो चला रहे हैं,

हमारा जहाँ–जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ हमारे काम चल रहे हैं रसोई का, जीविका दीदी इस काम को आगे बढ़ा रही हैं । लेकिन इसको और विस्तृत करते हुए सभी पुलिस लाइन में हम बढ़ाएंगे । महोदय, इसके साथ–साथ जो सभी पुलिस लाइन हैं, उनके बच्चे जो पुलिस वालों के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए इधर–उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सभी पुलिस लाइन में एक–एक स्कूल खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी ।

महोदय, इसके साथ–साथ जो अग्निवीर हैं जो भारत की सरकार के द्वारा अग्निवीर है । अग्निवीर में जो लोग आएंगे हमारे पास उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे । हम लोग उनको भी एक आरक्षण के तहत जो एक कैटेगरी में रिलैक्सेशन हो सकता है, उसको देने का काम करेंगे । अब मैं आग्रह करूँगा जो माननीय साथी सतीश जी हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय है, बिहार में सुशासन चाहिए और बिहार में सुशासन के लिए राशि की जरूरत है, तो आपने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लें और मैं सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि गृह विभाग की मांग को आप सर्वसम्मत पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाय।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20132,86,69,000/– (बीस हजार एक सौ बत्तीस करोड़ छियासी लाख उनहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से ली जाएगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए :–

मांग संख्या – 01 कृषि विभाग के संबंध में 3446,45,26,000/–

(तीन हजार चार सौ छियालीस करोड़ पैंतालीस लाख छब्बीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 02 डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के संबंध में 1915,96,81,000/– (एक हजार नौ सौ पंद्रह करोड़ छियानवे लाख इक्यासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 6153,71,74,000/–
(छह हजार एक सौ तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख चौहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या – 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 370,50,53,000/–
(तीन सौ सत्तर करोड़ पचास लाख तिरेपन हजार) रूपये

मांग संख्या – 06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 323,53,51,000/–
(तीन सौ तेइस करोड़ तिरेपन लाख इक्यावन हजार) रूपये

मांग संख्या – 07 निगरानी विभाग के संबंध में 63,73,44,000/–
(तिरसठ करोड़ तिहतर लाख चौवालीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 08 कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में 187,55,18,000/–
(एक सौ सत्तासी करोड़ पचपन लाख अठारह हजार) रूपये

मांग संख्या – 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 1201,41,16,000/–
(एक हजार दो सौ एक करोड़ इकतालीस लाख सोलह हजार) रूपये

मांग संख्या – 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 18737,05,67,000/–
(अठारह हजार सात सौ सैंतीस करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार) रूपये

मांग संख्या – 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के संबंध में 1749,43,88,000/– (एक हजार सात सौ उनचास करोड़ तैंतालीस लाख अठासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 12 वित्त विभाग के संबंध में 1541,36,83,000/–
(एक हजार पाँच सौ इकतालीस करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 15 पेंशन के संबंध में 35140,33,59,000/–
(पैंतीस हजार एक सौ चालीस करोड़ तैंतीस लाख उनसठ हजार) रूपये

मांग संख्या – 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 10995,50,82,000/–
(दस हजार नौ सौ पंचानवे करोड़ पचास लाख बयासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में 276,59,01,000/–
(दो सौ छिहतर करोड़ उनसठ लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या – 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 1195,18,55,000/–(एक हजार एक सौ पंचानवे करोड़ अठारह लाख पचपन हजार) रूपये

मांग संख्या – 19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 1075,39,60,000/– (एक हजार पचहत्तर करोड़ उनचालीस लाख साठ हजार) रूपये

मांग संख्या – 23 उद्योग विभाग के संबंध में 3337,63,69,000/–
(तीन हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ तिरसठ लाख उनहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या – 24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 280,13,39,000/– (दो सौ अस्सी करोड़ तेरह लाख उनचालीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 290,43,53,000/– (दो सौ नब्बे करोड़ तैंतालीस लाख तिरेपन हजार) रूपये

मांग संख्या – 26 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के संबंध में 371,63,31,000/– (तीन सौ इकहत्तर करोड़ तिरेसठ लाख इकतीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 27 विधि विभाग के संबंध में 1736,90,80,000/– (एक हजार सात सौ छत्तीस करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार) रूपये

मांग संख्या – 29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 78,39,86,000/– (अठहत्तर करोड़ उनचालीस लाख छियासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 896,21,32,000/– (आठ सौ छियानवे करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 9,87,56,000/– (नौ करोड़ सत्तासी लाख छप्पन हजार) रूपये

मांग संख्या – 32 विधान मंडल के संबंध में 358,30,35,000/– (तीन सौ अट्ठावन करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 1264,71,99,000/– (एक हजार दो सौ चौसठ करोड़ इकहत्तर लाख निन्यानवे हजार) रूपये

मांग संख्या – 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 2596,57,11,000/– (दो हजार पाँच सौ छियानवे करोड़ संतावन लाख ग्यारह हजार) रूपये

मांग संख्या – 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 2469,35,12,000/–(दो हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार) रूपये

मांग संख्या – 38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 742,74,93,000/– (सात सौ बयालीस करोड़ चौहत्तर लाख तिरानवे हजार) रूपये

मांग संख्या – 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 9399,26,71,000/– (नौ हजार तीन सौ निन्यानवे करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या – 43 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 1003,57,10,000/– (एक हजार तीन करोड़ संतावन लाख दस हजार) रूपये

मांग संख्या – 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 2086,66,46,000/– (दो हजार छियासी करोड़ छियासठ लाख छियालीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 340,47,65,000/– (तीन सौ चालीस करोड़ सैंतालीस लाख पैंसठ हजार) रूपये

(क्रमशः)

टर्न–27 / हेमन्त / 20.02.2026

(क्रमशः)

मांग संख्या – 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 665,70,51,000 / – (छः सौ पैंसठ करोड़ सत्तर लाख इक्यावन हजार) रूपये

मांग संख्या – 47 परिवहन विभाग के संबंध में 351,44,12,000 / – (तीन सौ इक्यावन करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार) रूपये

मांग संख्या – 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 15236,99,84,000 / – (पंद्रह हजार दो सौ छत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख चौरासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 1351,19,79,000 / – (एक हजार तीन सौ इक्यावन करोड़ उनीस लाख उनासी हजार) रूपये

मांग संख्या – 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 8470,06,39,000 / – (आठ हजार चार सौ सत्तर करोड़ छः लाख उनचालीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 52 खेल विभाग के संबंध में 240,75,21,000 / – (दो सौ चालीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्कीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 53 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 1379,57,70,000 / – (एक हजार तीन सौ उनासी करोड़ संतावन लाख सत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या – 54 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 8012,34,24,000 / – (आठ हजार बारह करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार) रूपये

मांग संख्या – 55 सिविल विमानन विभाग के संबंध में 698,47,94,000 / – (छः सौ अंठानवे करोड़ सैंतालीस लाख चौरानवे हजार) रूपये

से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभी मांगे स्वीकृत हुईं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–54 (चौवन) है, अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।